

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण कमजोर होता जा रहा है क्योंकि मुद्रास्फीति में गिरावट रुक रही है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम फिर से बढ़ रहा है। पूंजी प्रवाह अस्थिर हो गया है क्योंकि घबराए हुए निवेशक जोखिम से बचने लगे हैं। इस बात को लेकर आशावाद बढ़ रहा है कि भारत लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक उड़ान के मुहाने पर है। हाल के संकेतक सकल मांग की गति में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। ग्रामीण व्यय में सुधार के संकेत से खाद्येतर व्यय को बढ़ावा मिल रहा है। अप्रैल 2024 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली कमी इस उम्मीद की पुष्टि करती है कि लक्ष्य के साथ संरेखण की एक असमान और धीमी पड़ी हुई गति चल रही है।

I. प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर, आशंकाएं उठ रही हैं। वैश्विक संवृद्धि में सहजता के बावजूद, मुद्रास्फीति में गिरावट रुक रही है, जिससे वैश्विक वित्तीय स्थिरता और संवृद्धि के लिए जोखिम फिर से बढ़ रहे हैं। आधारणीय (नॉन-सस्टेनेबल) लोक ऋण और वैश्विक व्यापार के विखंडन के मंडराते खतरे के साथ-साथ, वैश्विक अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण भी कमजोर होता जा रहा है। वास्तव में, दुनिया अधिक संतुलित संवृद्धि के लिए तैयार हो रही है – क्रय प्रबंधकों के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि दूसरी तिमाही में संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में गतिविधि में कमी आई है, जबकि यूरोजोन गति पकड़ रहा है और यूनाइटेड किंगडम (यूके) मंदी से बाहर निकल गया है। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने भी उत्पादन विस्तार का अनुभव किया। संवृद्धि विचलन का कम होना मुख्य रूप से सेवाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है,

* यह आलेख माइकल देवब्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शशि कांत, रजनी दहिया, शिवम, कुणाल प्रियदर्शी, सौम्यश्री तिवारी, हर्षिता केशन, रमेश कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, हरेंद्र बेहरा, सत्यार्थ सिंह, लव कुमार शांडिल्य, प्रशांत कुमार, खुशी सिन्हा, हर्षिता यादव, प्रतिभा केडिया, शैलजा भाटिया, अंजलि मारिया जोस, सुक्ति खांडेकर, सुवेंदु सरकार, श्रेया गुप्ता, सुप्रियो मंडल, युवराज कश्यप, अभिनंदन बोर्ड, हिमानी शेखर, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव, और रेखा मिश्रा द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

जबकि निर्यात ऑर्डर और आपूर्तिकर्ताओं के डिलीवरी समय में सुधार हुआ है, लेकिन विनिर्माण में लगातार कमजोरी चिंता का विषय बनी हुई है।

2023 तक मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट, जिसने 2024 की पहली तिमाही तक दुनिया भर की लगभग एक तिहाई अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य के बराबर या उससे नीचे की हेडलाइन को ले लिया, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और ईएमई में महीने-दर-महीने (एमओएम) परिवर्तनों के संदर्भ में धीमी हो गई है। सेवाओं की मुद्रास्फीति ने महामारी-पूर्व स्तरों पर स्थिरता प्रदर्शित की है, हालाँकि मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट आई है। आगे देखते हुए, चल रही मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक धीमी गति से आगे बढ़ सकती है। अंतिम मील का सामना अंतिम अंतराल से होता है। चिंता यह है कि जो शोर जैसा दिखता है वह प्रवृत्ति बन सकता है, जिससे मुद्रास्फीति ईई के 2 प्रतिशत के लक्ष्य के बजाय 3 प्रतिशत के करीब रह सकती है: “मुद्रास्फीति अभी भी बहुत अधिक है, इसे नीचे लाने में आगे की प्रगति सुनिश्चित नहीं है, और आगे का रास्ता अनिश्चित है।”¹

हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक यह संकेत दे रहे हैं कि 2024 की शुरुआत से विश्व व्यापार की मात्रा में मामूली सुधार हो रहा है, जिसमें सीमा पार यात्रा और हवाई माल यातायात के साथ-साथ सेवा निर्यात ऑर्डर बढ़ रहे हैं। ई-कॉमर्स में भी जोरदार वृद्धि हुई है। लाल सागर में शिपिंग पर हमलों के परिणामस्वरूप व्यापार प्रवाह को फिर से रूट किया जा रहा है, जनवरी और अप्रैल के बीच औसत दैनिक कंटेनर जहाजों की संख्या 2023 की अंतिम तिमाही की तुलना में 51 प्रतिशत कम है। आर्थिक सहयोग और संवृद्धि संगठन (ओईसीडी) का अनुमान है कि रूटिंग ने विश्व समुद्री व्यापार के 9 प्रतिशत और लंबी दूरी के समुद्री वॉल्यूम के 18 प्रतिशत को प्रभावित किया है, जिसके परिणामस्वरूप यूरोप और एशिया के बीच प्रभावित कार्गो के लिए यात्रा का समय लगभग 30 प्रतिशत बढ़ गया है। पनामा नहर में सूखे के कारण यात्रा का समय भी प्रभावित हुआ है, शिपिंग लागत 2023 के स्तर से 60 प्रतिशत

¹ जेरोम पॉवेल, अध्यक्ष, अमेरिकी फेडरल रिजर्व, प्रेस 1 मई 2024।

अधिक बढ़ गई है। समग्र शिपिंग और लॉजिस्टिक्स वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसमें शिपिंग प्रमुख लागत कम करने के लिए दक्षता और सुव्यवस्थित संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आपूर्ति शृंखला दबाव के संकेतक अब तक केवल मामूली रूप से ही खराब हुए हैं; तथापि, उच्च शिपिंग लागत वैश्विक स्तर पर अपस्फीति की गति को धीमा कर देगी।

संभावित ऋण संकट वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर एक अशुभ छाया डालता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वैश्विक ऋण मॉनिटर ने बताया कि कुल वैश्विक ऋण (निजी और सार्वजनिक) बढ़कर 235 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 238 प्रतिशत है। इस बात की गंभीर चिंता है कि 2024 में राजकोषीय विवेक पीछे छूट सकता है, क्योंकि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चुनाव में जाएगी। जड़ मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए ब्याज दरें ऊँची बनी हुई हैं, इसलिए ऋण सेवा लागत बढ़ रही है। यह सरकारी वित्त और घरेलू बजट पर दबाव डालकर, ऋण और निवेश को रोककर वित्तीय अस्थिरता के दुष्चक्र को बढ़ावा दे सकता है। अस्थिर ऋण स्तर सॉवरेन रेटिंग को खराब कर सकते हैं और उत्पादकता बढ़ाने वाले सार्वजनिक निवेश के लिए संसाधन जुटाने की सरकारों की क्षमता को बाधित कर सकते हैं। ओवरलेवरेज्ड कॉरपोरेशन को दिवालियापन के जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू स्तर पर, अनिश्चित वित्त नौकरी छूटने और उच्च उधार लागत के बीच उपभोक्ता व्यय में भारी कटौती का संकेत दे सकता है, जिससे कुल मांग में कमी आ सकती है। ऋण संकट ने पहले ही संवृद्धिशील देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया है, जिससे उनकी कमजोरियाँ और भी बढ़ गई हैं। एक पूर्ण विकसित ऋण संकट गरीबी उन्मूलन, बीमारी से लड़ने और संवृद्धि को आगे बढ़ाने की दिशा में दशकों की प्रगति को उलट सकता है। बढ़ते तूफान के खिलाफ कार्रवाई करने का समय अब आ गया है, जिसकी शुरुआत अंतरराष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त का लोकतंत्रीकरण, सीमा पार दिवालियापन व्यवस्थाओं में सामंजस्य स्थापित करने और बहुपक्षीय सुरक्षा जाल को पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने से हो सकती है।

उभरते हुए विश्व में, पूंजी प्रवाह फिर से अस्थिर हो गया है क्योंकि घबराए हुए निवेशक जोखिम से बचने लगे हैं। फिर भी, कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में आत्मविश्वास बेहतर बना हुआ है, जहाँ संवृद्धि लचीला बना हुआ है, जैसे कि भारत, इंडोनेशिया और मैक्सिको। उपभोक्ता व्यय के उच्च आवृत्ति संकेतक हाल ही में थोड़े नरम पड़े हैं और चीन को छोड़कर औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि नरम बनी हुई है। ओईसीडी के अनुसार एशियाई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से भारत और इंडोनेशिया, में मोटे तौर पर स्थिर और तेज़ संवृद्धि जारी रहने की उम्मीद है, जबकि मुद्रास्फीति में और कमी आनी चाहिए, बशर्ते खाद्य कीमतें चरम मौसम की घटनाओं से सुरक्षित रहें। लैटिन अमेरिका में, विशेष रूप से ब्राजील और मैक्सिको में, संवृद्धि अच्छी तरह से बना हुआ है, जिसे लचीले श्रम बाजारों, बुनियादी ढांचे के निवेश और विनिर्माण के नीयर-शोरिंग द्वारा समर्थित किया गया है। अगले वर्ष मुद्रास्फीति के लक्ष्य की ओर कम होने की संभावना है। अप्रैल के मध्य में आईएमएफ-विश्व बैंक की वसंतीय बैठकों के दौरान आयोजित हाल ही में वैश्विक सॉवरेन ऋण गोलमेज बैठक ने ऋण के बोझ से दबे निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए आशा की किरण दिखाई। पिछले तीन वर्षों में, इन देशों में सॉवरेन ऋण में चूक की संख्या बढ़कर 18 हो गई है, जो पिछले दो दशकों की कुल संख्या से अधिक है। ऋण सेवा पर व्यय एक दशक पहले की तुलना में पाँच गुना अधिक है। अप्रैल 2024 के अंकटाड के अपडेट के अनुसार, नौ निम्न और मध्यम आय वाले देश ऋण संकट में पड़ गए, जबकि 25 अन्य देश ऋण संकट के कगार पर हैं। इस संदर्भ में, गोलमेज सम्मेलन ने ऋण उपचार के लिए जी20 सामान्य ढांचे के तहत भविष्य के ऋण पुनर्गठन मामलों के लिए 2-3 महीनों के भीतर कार्यक्रम अनुमोदन का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा। सूचना प्रवाह को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया और इस संबंध में बहुपक्षीय संस्थानों को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

वैश्विक वित्तीय स्थितियों में मामूली सुधार हुआ है। बाजार की उम्मीदों और केंद्रीय बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप होने के

कारण, अस्थिरता में कमी के बीच इक्विटी की कीमतों में मजबूती आई है, खासकर तकनीक से जुड़े शेयरों के लिए। वर्ष 2024 के आरम्भ से ही बांड प्रतिफल में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ब्याज दरों में शीघ्र कटौती की उम्मीदें कम हो रही हैं, तथा साथ ही मात्रात्मक सख्ती के कारण बढ़ते राजकोषीय जोखिमों और चलनिधि की तंगी के प्रति संवेदनशीलता के कारण भी ब्याज दरों में भविष्य में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इसके विपरीत, दुनिया के कुछ हिस्सों में कॉर्पोरेट दिवालियापन की संख्या में वृद्धि के बावजूद, रेटिंग श्रेणियों में कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड में नरमी आई है। अमेरिकी डॉलर में नॉमिनल प्रभावी दृष्टिकोण से वृद्धि हुई है, हालांकि इस मजबूती का कुछ हिस्सा येन में लगातार कमजोरी को दर्शाता है। नतीजतन, बड़े पैमाने पर मूल्यहास ने उभरते बाजार की मुद्राओं को नीचे खींच लिया है।

भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से प्रमुख कमोडिटी कीमतों पर काफी दबाव बढ़ रहा है, जिसमें कच्चे तेल और सोने की कीमतों में सबसे ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है। 2023 में कीमतों में गिरावट के बाद बेस मेटल की कीमतों में 2024 में जोरदार उछाल देखने को मिला है। इससे मौजूदा स्तरों से मुद्रास्फीति में गिरावट में बाधा आ सकती है और इसलिए मौद्रिक नीति में ढील की शुरुआती संभावनाएं कम हो सकती हैं। वैश्विक संवृद्धि की धीमी गति के संदर्भ में कमोडिटी की कीमतों में हाल ही में हुई तेजी भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के अलावा कई अन्य कारकों को दर्शाती है – आपूर्ति की स्थिति में सख्ती; जलवायु परिवर्तन; चीन में बुनियादी ढांचे पर व्यय में तेजी; और औद्योगिक गतिविधि और व्यापार के कारण मांग में मजबूती। जबकि विश्व बैंक के कमोडिटी की कीमतों में 2024 और 2025 में धीमी वैश्विक वृद्धि के कारण गिरावट का अनुमान है, जोखिम बढ़ोतरी की ओर है – मुख्य रूप से ऊर्जा आपूर्ति को बाधित करने वाले संघर्ष और मौसम की घटनाओं के कारण।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर आशावाद बढ़ रहा है कि भारत लंबे समय से प्रतीक्षित आर्थिक उड़ान के मुहाने पर है। 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि को करीब 2 प्रतिशत

अंकों से संशोधित करते हुए, आईएमएफ के अप्रैल 2024 के विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूओ) में 2024 और 2025 में अपेक्षित संवृद्धि की मजबूती का संकेत दिया गया है और इसे "घरेलू मांग में निरंतर मजबूती और कामकाजी आयु वर्ग की बढ़ती आबादी को दर्शाया गया है"² ओईसीडी का मई 2024 का आर्थिक आउटलुक हाल के मासिक संकेतकों में भारत में मजबूत गति की ओर इशारा करता है और उम्मीद करता है कि "भारत में मजबूत निवेश और कारोबारी आत्मविश्वास में सुधार ... वास्तविक जीडीपी वृद्धि को बनाए रखेगा"³ गरीबी में कमी आई है। विश्व बैंक का अनुमान⁴ है कि हाल के अनुमानों से पता चलता है कि अत्यधिक गरीबी जिसे कभी भारत का पर्याय माना जाता था, अब विलुप्त होने वाला है।

राजमार्गों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों सहित भौतिक अवसंरचना के परिवर्तन पर दुनिया भर में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत के बिजली क्षेत्र ने 100 प्रतिशत विद्युतीकरण प्राप्त कर लिया है और इसे पूरे देश में एक ही ग्रिड में एकीकृत कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दैनिक बिजली की उपलब्धता बढ़कर 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे हो गई है। कुल तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान काफी कम हो गए हैं। अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण में उछाल आया है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक बन गया है। इसने भुगतान दक्षता, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लाभ उठाने में विश्व नेतृत्व प्राप्त किया है। वर्तमान में, भारत में सबसे अधिक डिजिटल वित्तीय लेन-देन होते हैं, जो एक विशाल इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार द्वारा समर्थित है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में भी उल्लेखनीय उछाल आया है, जो हमारे 93 प्रतिशत से अधिक गांवों तक पहुंच गया है। भारत नेट परियोजना सभी गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ेगी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म एक बड़ा बाजार प्रदान करके छोटे व्यवसायों को सशक्त बना रहे हैं। भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी

² विश्व आर्थिक परिदृश्य, आईएमएफ, अप्रैल 2024।

³ ओईसीडी आर्थिक परिदृश्य, मई 2024।

⁴ <https://data.worldbank.org/country/india>.

ढांचा – इंडिया स्टैक – उत्पादकता, दक्षता को बढ़ावा दे रहा है और रोजगार सृजन कर रहा है, साथ ही राजकोषीय हस्तांतरण को बेहतर ढंग से लक्षित करने में भी सक्षम बना रहा है।

हाल के संकेतक समग्र मांग की गति में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। व्यक्तिगत उपभोग के क्षेत्र में, नीलसन आईक्यू डेटा संकेत देता है कि एक स्वागत योग्य मोड़ आ रहा है जो व्यय की इस श्रेणी को बढ़ावा देगा। कम से कम दो वर्षों में पहली बार, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की ग्रामीण मांग ने शहरी बाजारों को पीछे छोड़ दिया है – बीती तिमाही में, एफएमसीजी की मात्रा में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि, घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की मजबूत मांग के दम पर 5.7 प्रतिशत की शहरी वृद्धि के मुकाबले ग्रामीण संवृद्धि की 7.6 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई थी। शहरी उपभोग वृद्धि में क्रमिक कमी राशन (चावल, नमक, आटा) की मात्रा वृद्धि में मंदी के कारण है, जो इन श्रेणियों में उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाता है। दूसरी ओर, कार और दोपहिया वाहनों की बिक्री सहित खाद्येतर व्यय को ग्रामीण मांग में शुरुआत से बढ़ावा मिल रहा है।

निजी निवेश की बात करें तो, सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के लिए, 2023-24 की दूसरी छमाही के दौरान प्रतिधारित आय निधि का प्रमुख स्रोत बनी रही। इनका उपयोग मुख्य रूप से अचल संपत्तियों और गैर-वर्तमान निवेशों के निर्माण के लिए किया गया, जो वर्ष की पहली छमाही के सापेक्ष नई क्षमता निर्माण में तेजी का संकेत देता है। सूचीबद्ध कॉरपोरेट्स द्वारा अब तक घोषित किए गए परिणामों से संकेत मिलता है कि उन्होंने जनवरी-मार्च 2024 में दर्ज तिमाही राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष और क्रमिक रूप से उच्चतम वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 को बंद कर दिया। दूसरी ओर, परिचालन लाभ वृद्धि धीमी हो गई क्योंकि बढ़ते व्यय ने – विशेष रूप से विनिर्माण फर्मों के लिए इनपुट लागत और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के लिए कर्मचारियों की लागत – आय में लाभ को कम कर दिया। अन्य आय, लाभांश और राजकोषीय गतिविधियों से आय को दर्शाती है, वार्षिक आधार पर घटी, आंशिक रूप से प्रतिकूल आधार

प्रभाव के कारण। कुल मिलाकर, लगातार चार तिमाहियों में मजबूत वृद्धि के बाद पहली बार सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए निवल लाभ में वर्ष-दर-वर्ष गिरावट आई। इससे पता चलता है कि विनिर्माण द्वारा सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 2023-24 की चौथी तिमाही में पिछली तिमाहियों की तुलना में कम रहा होगा, जिसका अर्थव्यवस्था के समग्र जीवीए/जीडीपी संवृद्धि पर असर पड़ा होगा। दूसरी ओर, सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों ने प्रावधान लागत और ब्याज व्यय में वृद्धि के बावजूद, टॉप-लाइन और बॉटम-लाइन वृद्धि दोनों के संदर्भ में एक मजबूत तिमाही प्रदर्शन दर्ज किया। मजबूत ऋण वितरण के कारण निवल लाभ में दोहरे अंकों में वृद्धि के साथ, वित्तीय क्षेत्र के जीवीए में जनवरी-मार्च 2024 में जोरदार वृद्धि होने की संभावना है। इन घटनाक्रमों पर खंड IV में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

वैश्विक चुनौतियों के बीच विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) की अनुकूलनशीलता और लचीलेपन से भारत में निजी निवेश गतिविधि को बढ़ावा मिल रहा है। वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी, मीडिया और दूरसंचार जैसे पारंपरिक रूप से प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर समेकन और पुनर्गठन एम एंड ए गतिविधि को बढ़ावा दे रहा है।⁵ नवीकरणीय ऊर्जा में लेन-देन के कारण ऊर्जा स्पष्ट रूप से एम एंड ए के लिए उभरता हुआ क्षेत्र है। सीमा पार निवेश इंजन बल है, जिसमें इनबाउंड रणनीतिक निजी इक्विटी सौदे बढ़ रहे हैं जबकि आउटबाउंड सौदों में काफी गिरावट आई है।

निवल निर्यात में अलग-अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। पेट्रोलियम उत्पादों की हिस्सेदारी स्थिर रही है, साथ ही रसायनों और समुद्री उत्पादों की हिस्सेदारी भी स्थिर रही है, जबकि रत्न और आभूषणों की हिस्सेदारी आधी रह गई है और रेडीमेड कपड़ों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है। इंजीनियरिंग निर्यात और सूत और कपड़ों सहित कपास की सफलता की कहानियाँ हैं। सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अंकटाड के अनुसार,

⁵ हिंदू बिजनेस लाइन, 22 अप्रैल 2024.

भारत 2023 में सेवाओं के निर्यात में विश्व औसत से आगे निकल जाएगा। सबसे बड़ी बढ़त डिजिटल रूप से कारोबार की जाने वाली सेवाओं में हुई, उसके बाद यात्रा में। वर्तमान में, भारत दुनिया में सेवाओं का सातवाँ सबसे बड़ा निर्यातक है और संवृद्धिशील देशों में दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। वैश्विक क्षमता केंद्रों की बढ़ती व्यावसायिक सेवाओं में तेजी देखी गई है। हालाँकि कुल में सॉफ्टवेयर निर्यात की हिस्सेदारी घटकर लगभग 46 प्रतिशत रह गई है, लेकिन 2024 में वैश्विक आईटी व्यय में 8 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और भारत से आईटी निर्यात वैश्विक आईटी व्यय से आगे निकल सकता है, जिसका नेतृत्व कंसल्टिंग खंड करेगा⁶

अप्रैल 2024 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति में मामूली कमी ने हमारी इस उम्मीद की पुष्टि की कि लक्ष्य के साथ संरेखण की असमान गति चल रही है। खाद्य श्रेणी में सब्जियों, अनाज, दालों, मांस और मछली की कीमतें अप्रैल एमपीसी संकल्प में निर्धारित अनुमानों के अनुरूप निकट अवधि में हेडलाइन को ऊंचा और 5 प्रतिशत के करीब रख सकती हैं, ईंधन की कीमतों में गिरावट और कोर मुद्रास्फीति के नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर नरम होने के बावजूद। जबकि सांख्यिकीय आधार प्रभाव जुलाई और अगस्त में हेडलाइन मुद्रास्फीति को नीचे खींचने में मदद कर सकते हैं, उम्मीद है कि सितंबर में इसमें उलटफेर देखने को मिल सकता है। यह केवल वर्ष की दूसरी छमाही में है कि लक्ष्य के साथ एक टिकाऊ संरेखण फिर से शुरू हो सकता है और 2025-26 के दौरान लक्ष्य के करीब संख्या दिखाई देने तक बना रह सकता है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि-आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।










⁶ गार्टनर ने अनुमान लगाया है कि 2024 में दुनिया भर में आईटी खर्च 8 प्रतिशत बढ़ेगा (गार्टनर, 17 अप्रैल 2024)।

II. वैश्विक परिदृश्य

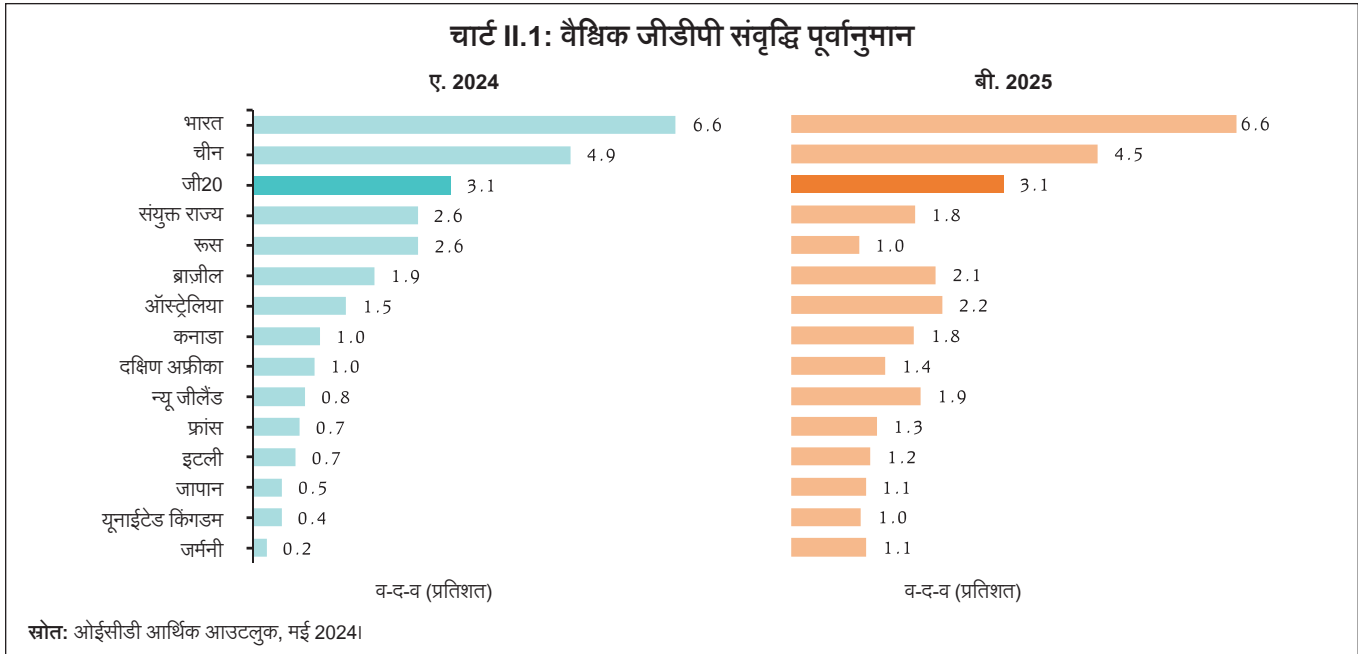
श्रम बाजार की स्थितियों में कुछ ढील के बीच वैश्विक गतिविधि में नरमी आ रही है। मध्यम ढील के बावजूद, वित्तीय स्थितियाँ तंग बनी हुई हैं, खासकर आवास और ऋण बाजारों में। मई 2024 के अपने आर्थिक दृष्टिकोण में, ओईसीडी ने 2024 में वैश्विक वृद्धि 3.1 प्रतिशत (2023 के समान) रहने का अनुमान लगाया है, जो मजबूत वास्तविक आय वृद्धि और कम नीतिगत ब्याज दरों के समर्थन से 2025 में 3.2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। ये अनुमान वैश्विक वृद्धि को महामारी-पूर्व औसत (2013-2019) 3.4 प्रतिशत (सारणी II.1) से कम बताते हैं।

सारणी II.1: सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

(प्रतिशत)

पूर्वानुमान माह → क्षेत्र / देश ↓	2024		2025	
	मई 2024	फरवरी 2024	मई 2024	फरवरी 2024
 विश्व	3.1	2.9	3.2	3.0
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (आई)				
 यूएस	2.6	2.1	1.8	1.7
 यूके	0.4	0.7	1.0	1.2
 यूरो क्षेत्र	0.7	0.6	1.5	1.3
 जापान	0.5	1.0	1.1	1.0
उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)				
 ब्राजील	1.9	1.8	2.1	2.0
 रूस	2.6	1.8	1.0	1.0
 भारत#	6.6	6.2	6.6	6.5
 चीन	4.9	4.7	4.5	4.2
 दक्षिण अफ्रीका	1.0	1.0	1.4	1.2

नोट: * पीपीपी भारिता। #: डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।
स्रोत: ओईसीडी।

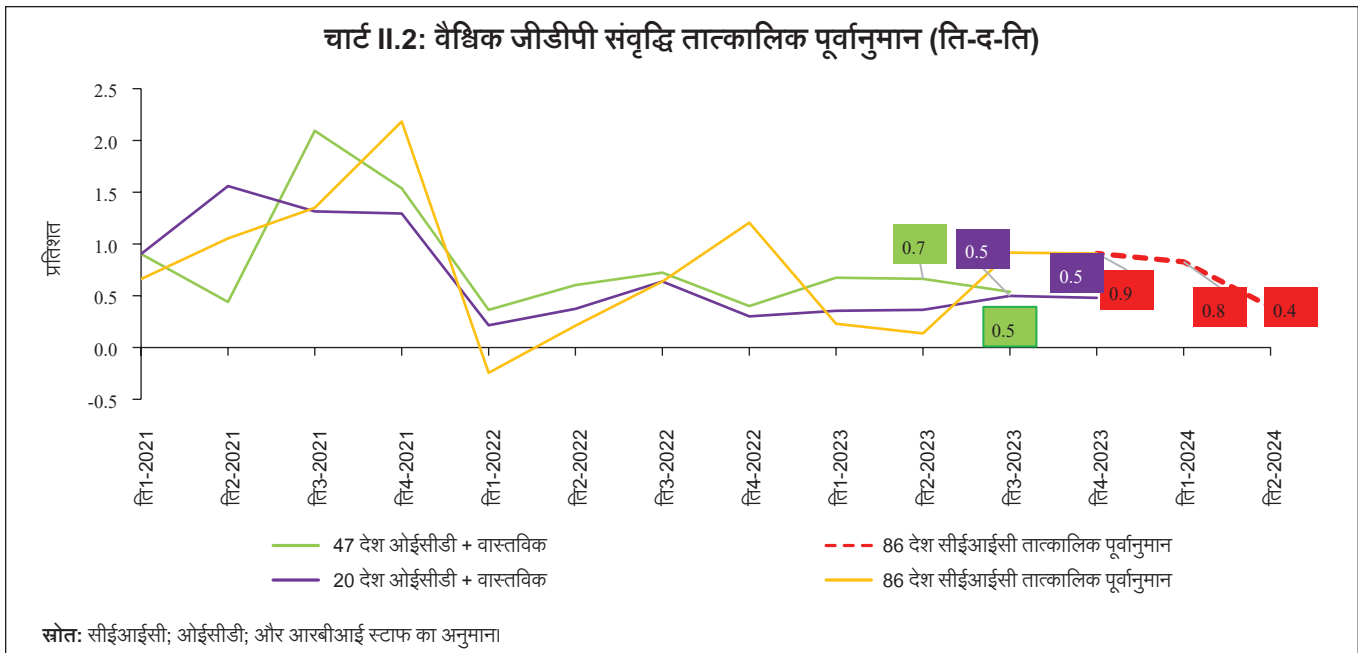


यूरोप और अधिकांश निम्न आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में हाल ही में तेजी आई है, जबकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नरमी आ रही है और कई बड़ी ईएमई मजबूत प्रदर्शन के लिए तैयार हैं। भारत के सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है (चार्ट II.1)।

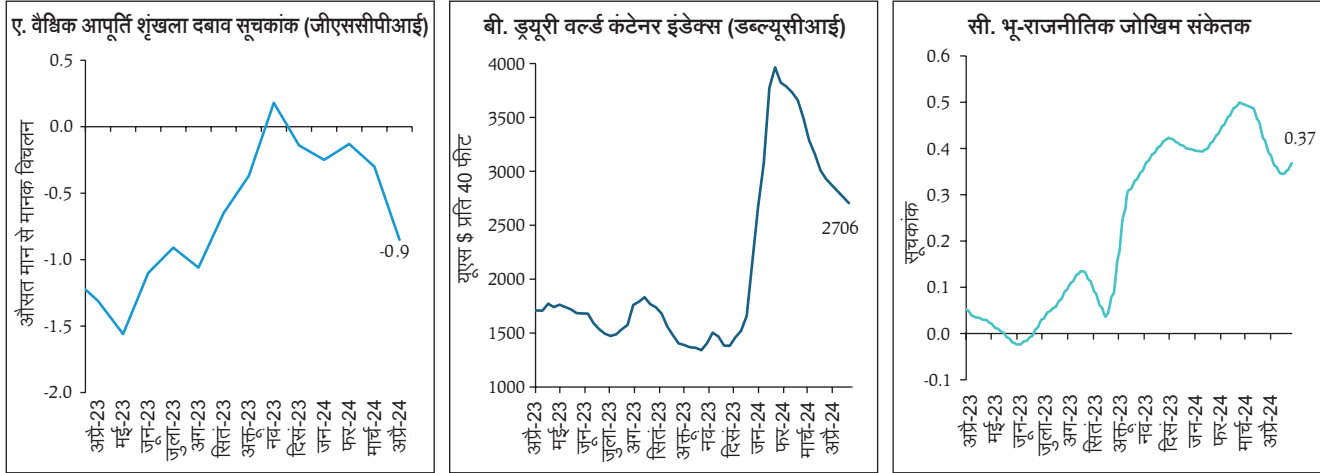
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लिए हमारा पूर्वानुमान 2024 की पहली तिमाही के दौरान निरंतर संवृद्धि गति की ओर इशारा करता है, लेकिन 2024 की दूसरी तिमाही में कुछ मंदी की ओर

इशारा करता है (चार्ट II.2)।

वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) और कंटेनर शिपिंग लागत फरवरी 2024 से कम हो गई है (चार्ट II.3ए और II.3बी)। हालाँकि, ईरान और इजराइल के बीच तनाव फिर से बढ़ने के कारण भू-राजनीतिक जोखिम (जीपीआर) सूचकांक अप्रैल 2024 के मध्य से बढ़ गया है (चार्ट II.3सी)। भू-राजनीतिक जोखिम वैश्विक संवृद्धि के लिए एक बड़ा जोखिम बना हुआ है (बॉक्स 1)।



चार्ट II.3: आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में प्रवृत्तियां



टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों से संबंधित डेटा दर्शाता है।
 2. डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पॉट कंटेनर माल ढुलाई दरों को इंगित करता है। समग्र डाटा मात्रा के हिसाब से 8 शिपिंग मार्गों के भारत औसत का प्रतिनिधित्व करता है और प्रति 40-फुट कंटेनर यूएसडी में सूचित करता है।
स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, अप्रैल 2024; और ब्लूमबर्ग।

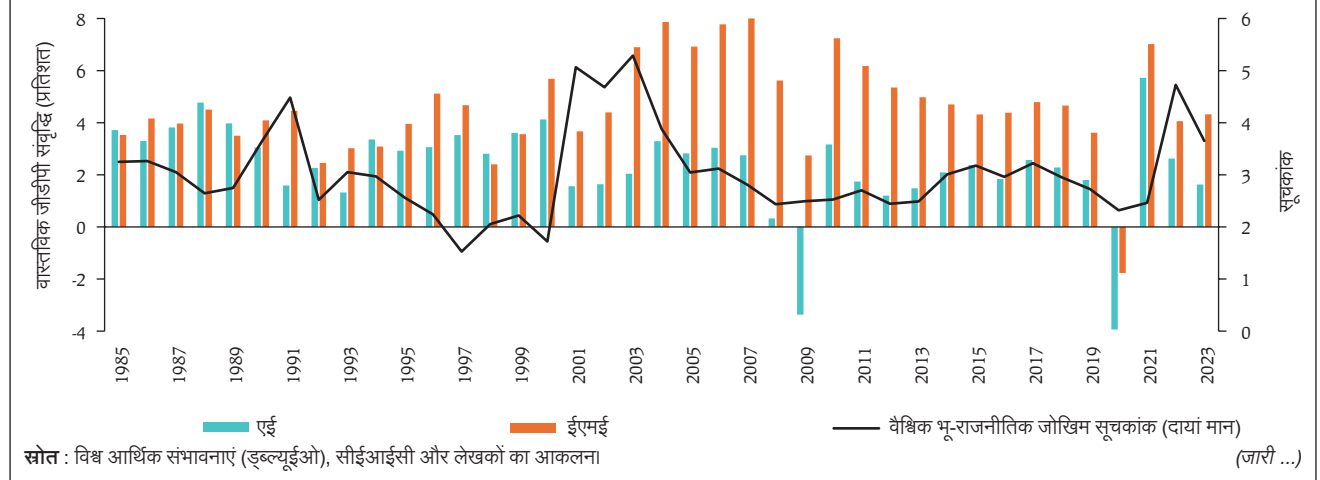
बॉक्स 1: आर्थिक संवृद्धि पर भू-राजनीतिक जोखिमों का प्रभाव: एक अंतर-देशीय विश्लेषण

महामारी के बाद के युग में भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधान वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नई चुनौतियों के रूप में उभरे हैं (दास, 2024)। बढ़े हुए तनाव व्यापार प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं और आस-पास के देशों में भी आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं। प्रतिबंधों और शुल्कों के कारण तेल और गैस जैसे प्रमुख संसाधनों की कमी हो रही है, जिसका असर कमोडिटी की कीमतों और अंततः आर्थिक उत्पादन पर पड़ रहा है। इन कारकों के परिणामस्वरूप उच्च मुद्रास्फीति, कम संवृद्धि और जन-कल्याण की बड़ी हानि हो सकती है

(गोएस और बेकर्स, 2022)। जीपीआर, इसके अतिरिक्त, वित्तीय चैनल, बढ़ी हुई अनिश्चितता, उच्च जोखिम प्रीमियम और आस्तित्व मूल्य वृद्धि (जीएफएसआर, 2023) के माध्यम से आर्थिक संवृद्धि को प्रभावित कर सकता है।

प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार⁷ पत्रों में भू-राजनीतिक तनाव से संबंधित शब्दों की गणना करने वाला जीपीआर का मासिक सूचकांक पिछले तीन दशकों में जीपीआर में वृद्धि के कई प्रकरणों को दर्शाता है (कैल्डारा और इकोविलो, 2022) [चार्ट बी1]।

चार्ट बी 1 : जीडीपी संवृद्धि बनाम वैश्विक भू-राजनीतिक जोखिम



⁷ यह प्रमुख समाचार पत्रों में भू-राजनीतिक तनावों पर चर्चा करने वाले आलेखों की आवृत्ति को मापता है।

पैनल रिग्रेशन परिणाम (स्थिर प्रभाव)					
चर	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	वास्तविक जीडीपी वृद्धि	वास्तविक जीडीपी वृद्धि
जीपीआर सूचकांक	-0.736** (0.341)	-0.746* (0.440)	-0.593 (0.362)	-0.794** (0.368)	-0.782** (0.373)
ईएमई * जीपीआर सूचकांक	-4.164* (2.142)	-4.269** (2.077)	-2.935** (1.412)	-2.650** (1.232)	-2.616** (1.245)
नियंत्रण चर					
निजी खपत (जीडीपी का प्रतिशत)		Y	Y	Y	Y
सरकारी खपत (जीडीपी का प्रतिशत)			Y	Y	Y
निवेश (जीडीपी का प्रतिशत)				Y	Y
वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार (जीडीपी का प्रतिशत)					Y
स्थिरांक	4.187*** (0.454)	3.893*** (0.610)	19.13*** (3.555)	25.09*** (3.719)	16.06*** (3.542)
प्रेक्षण	1,113	1,113	1,113	1,113	1,113
आर-स्क्वायर	0.424	0.490	0.512	0.538	0.538
क्षेत्रों की संख्या	42	42	42	42	42

टिप्पणी : 1. ईएमई एक छद्म चर है जिसे ईएमई के लिए 1 और एई के लिए 0 के रूप में कोडित किया गया है।
 2. परिणामों में समय-निर्धारित प्रभाव शामिल हैं।
 3. कोष्ठक में बड़ी मानक त्रुटियाँ शामिल हैं।
 4. *, **, और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के स्तर पर सांख्यिकीय महत्व को दर्शाते हैं।
स्रोत : सीईआईसी; और लेखकों की गणना।

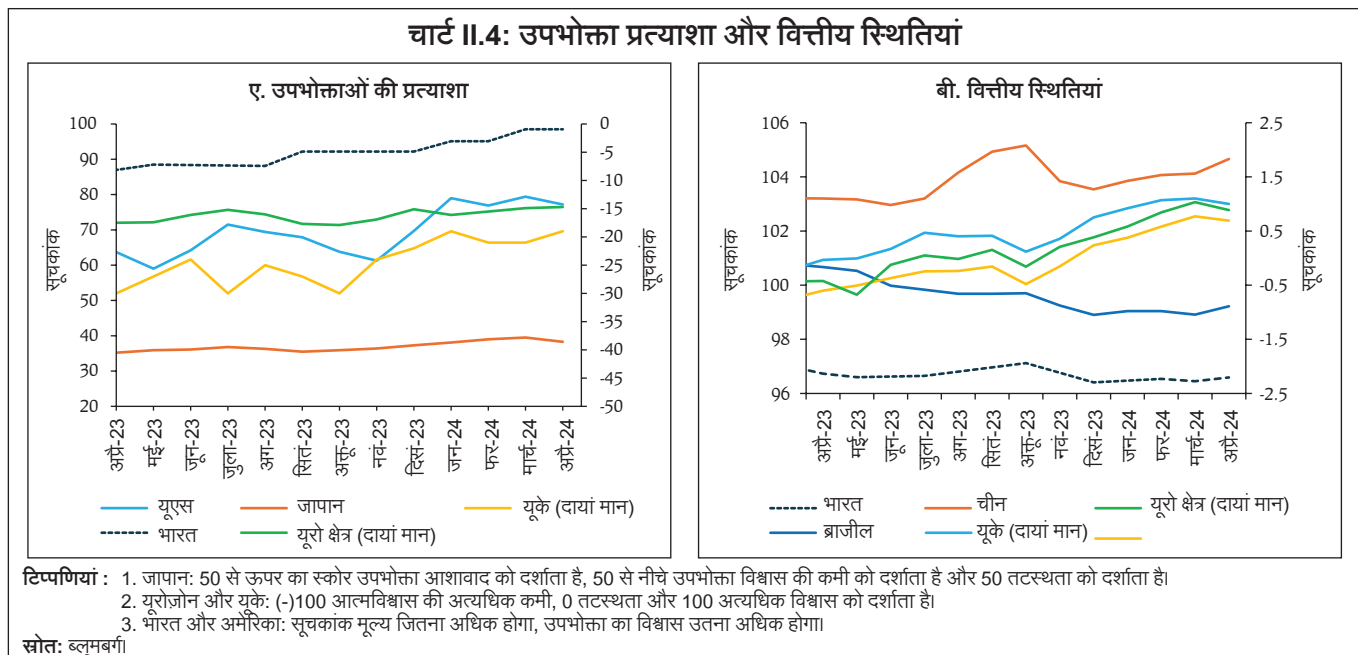
1996 से 2023 के दौरान 42 देशों के डेटा का उपयोग करके एक पैनल डेटा रिग्रेशन प्रेमवर्क से पता चलता है कि वास्तविक जीडीपी संवृद्धि पर जीपीआर का महत्वपूर्ण ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामों में ईएमई के लिए जीपीआर और एक छद्म चर के बीच महत्वपूर्ण व्युत्क्रम संबंध का तात्पर्य है कि जीपीआर में वृद्धि से ईएमई की संवृद्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

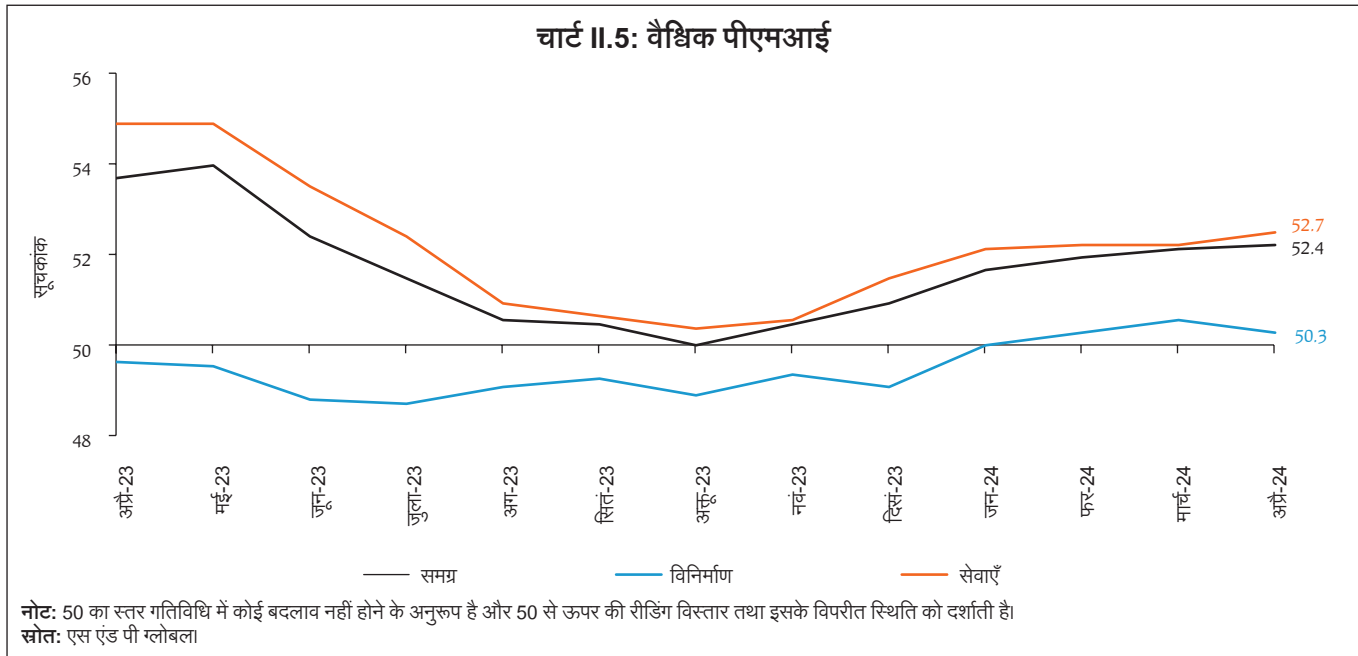
संदर्भ:

- कैलडारा, डी., और इकोविएलो, एम. (2022)। भू-राजनीतिक जोखिम को मापना। अमेरिकी आर्थिक समीक्षा, 112 (4): 1194-1225।
- दास, एस., (2024)। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौलिक बदलाव: नई जटिलताएँ, चुनौतियाँ और नीति विकल्प (मुख्य भाषण)। 59वाँ सीईएसीईएन गवर्नर सम्मेलन, मुंबई।
- गोज़, सी., और बेकर्स, ई. (2022)। व्यापार, संवृद्धि और नवाचार पर भू-राजनीतिक संघर्षों का प्रभाव। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) स्टाफ वर्किंग पेपर।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2023)। भूराजनीति और वित्तीय विखंडन: मैक्रो-वित्तीय स्थिरता के लिए निहितार्थ। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफएसआर) [अध्याय 3]।

अप्रैल 2024 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता प्रत्याशाएँ कम हो गईं, जो आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि को दर्शाती हैं (चार्ट II.4ए)। सरकारी बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि और

इक्विटी बाजारों में अस्थिरता के कारण कुछ क्षेत्रों में वित्तीय स्थिति मामूली रूप से सहज हुई (चार्ट II.4बी)।

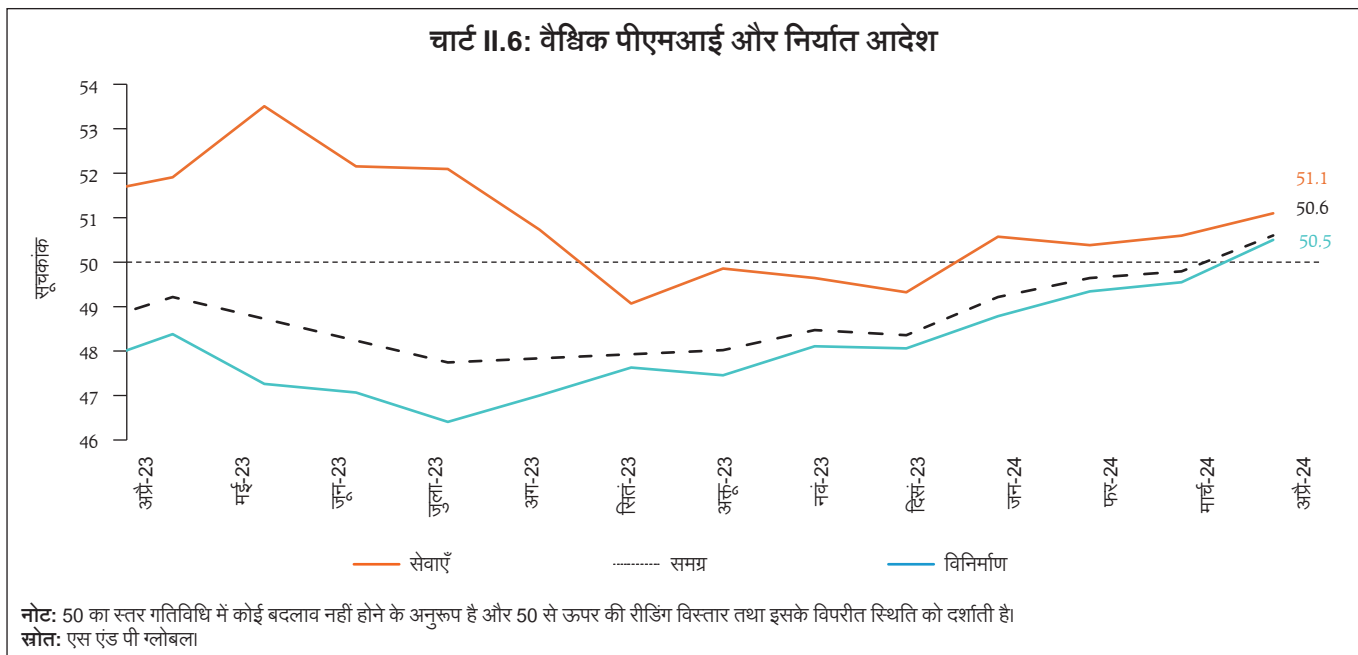




वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने अप्रैल 2024 में क्रमिक वृद्धि दर्ज की, क्योंकि सेवा क्षेत्र के उत्पादन में तेज़ वृद्धि ने विनिर्माण उत्पादन में मामूली मंदी की भरपाई की। नए व्यवसाय की बढ़ती हुई आमद, काम के बैकलॉग में कमी और नए निर्यात ऑर्डर के कारण सेवा पीएमआई दस महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। अप्रैल 2024 में वैश्विक विनिर्माण

में मामूली गिरावट आई; हालाँकि, यह लगातार तीसरे महीने विस्तार क्षेत्र में रहा क्योंकि उत्पादन और नए ऑर्डर में वृद्धि जारी रही (चार्ट II.5)।

वैश्विक व्यापार परिदृश्य में सुधार जारी रहा और निर्यात आदेशों के लिए समग्र पीएमआई ने अप्रैल 2024 में अपनी बढ़त बनाए रखी (चार्ट II.6)। उल्लेखनीय रूप से, विनिर्माण निर्यात



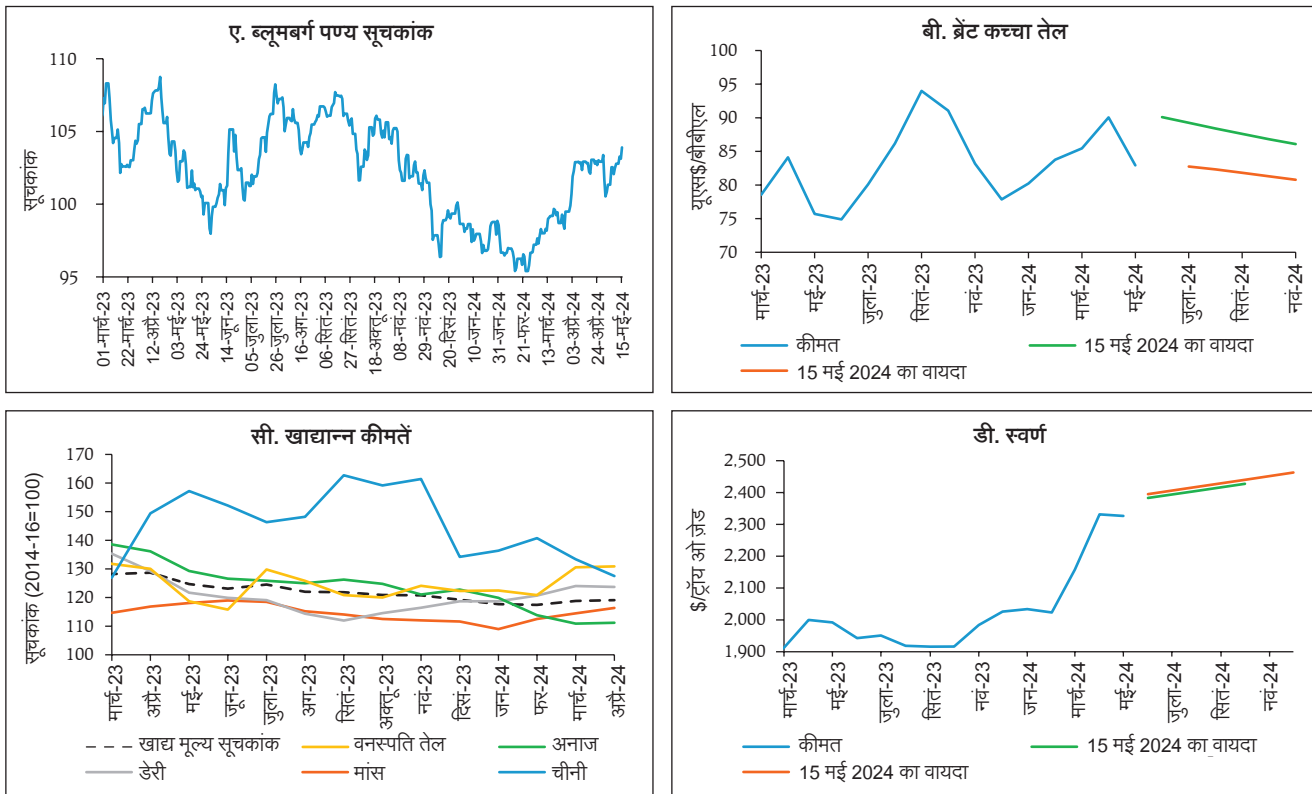
आदेश सूचकांक फरवरी 2022 के बाद पहली बार विस्तार पर लौटा, जो अप्रैल में 26 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सेवा निर्यात आदेश सूचकांक जनवरी 2024 से विस्तार में बना हुआ है।

कच्चे तेल और धातुओं की ऊंची कीमतों के कारण अप्रैल में वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में और बढ़ोतरी हुई। ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स में 2.2 प्रतिशत (मासिक) की वृद्धि हुई [चार्ट 11.7ए]। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में अप्रैल में 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो अप्रैल के मध्य तक 90 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर मँडरा रही थी, लेकिन उसके बाद रुझान उलट गया (15 मई को 81.3 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल पर पहुँच गई) क्योंकि मध्य पूर्व में संभावित युद्धविराम को लेकर आशावाद से जोखिम प्रीमियम कम हो गया (चार्ट 11.7बी)। अमेरिका में कच्चे तेल के भंडार में तेज बढ़ोतरी ने भी कीमतों में हाल की गिरावट में योगदान दिया। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक अप्रैल 2024 में 0.3 प्रतिशत (मासिक) बढ़ा, हालांकि, सूचकांक

में 7.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण अनाज की कीमतों में 18.3 प्रतिशत की गिरावट (वर्ष-दर-वर्ष) थी (चार्ट 11.7सी)। मध्य पूर्व क्षेत्र में संभावित वृद्धि से सुरक्षित आश्रय मांग को बढ़ावा मिलने की चिंताओं के कारण अप्रैल में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गईं, जो मार्च के मुकाबले 8.3 प्रतिशत अधिक रहीं (चार्ट 11.7डी)। हालांकि, भू-राजनीतिक तनाव कम होने से मई 2024 की शुरुआत में सोने की कीमतों में नरमी आई।

हेडलाइन मुद्रास्फीति ने अवस्फीति को पार करने में पीछे रहा और अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में यह लक्ष्य से ऊपर रही। अमेरिका में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति मार्च में 3.5 प्रतिशत से अप्रैल में 3.4 प्रतिशत कम हो गई, जबकि हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति फरवरी में 2.5 प्रतिशत से मार्च में 2.7 प्रतिशत हो गई। फ्लेश अनुमानों के अनुसार, यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति अप्रैल में 2.4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। जापान की सीपीआई मुद्रास्फीति (ताजा भोजन

चार्ट 11.7: पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



स्रोत : ब्लूमबर्ग; विश्व बैंक पिक शीट; और एफएओ

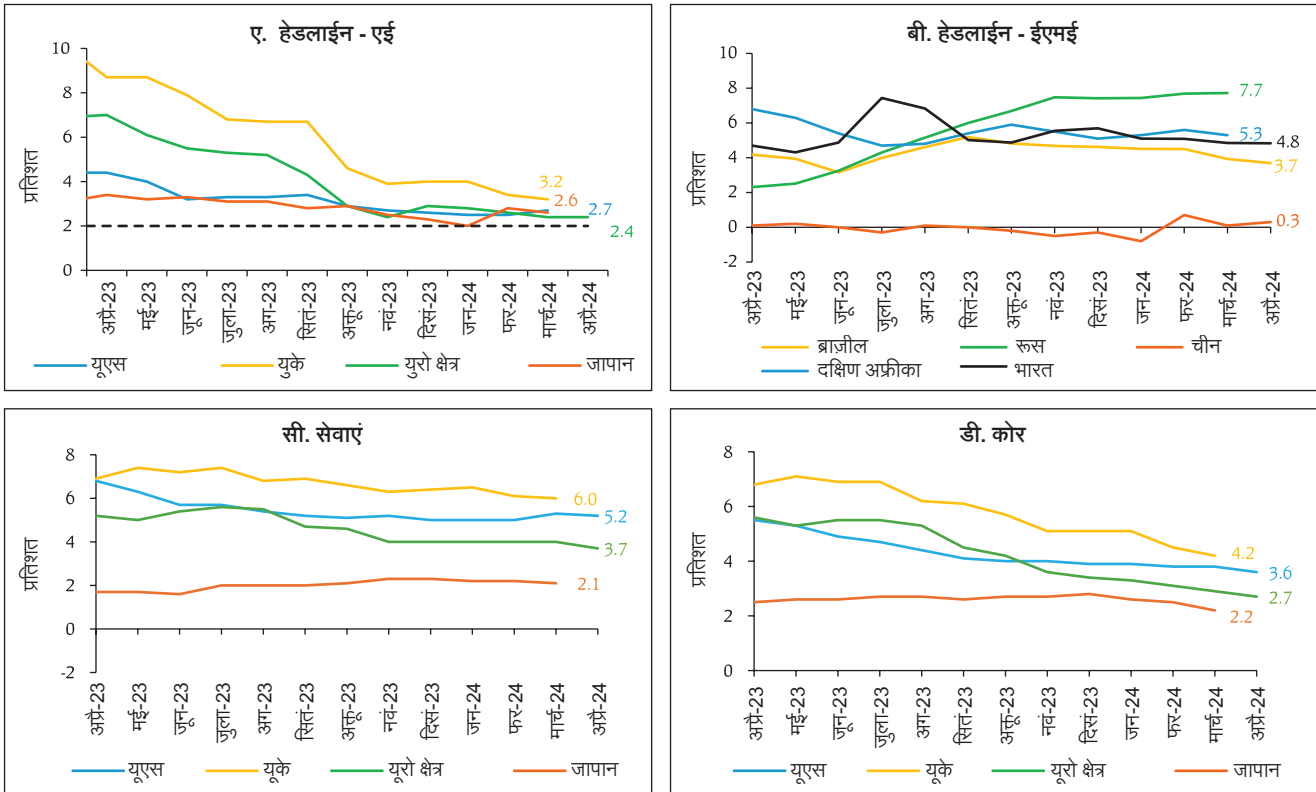
को छोड़कर) मार्च में मामूली रूप से कम होकर 2.6 प्रतिशत हो गई, जबकि यूके में सीपीआई मुद्रास्फीति नरम होकर 3.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट 11.8ए)। ईएमई में, ब्राजील में मुद्रास्फीति कम हुई, जबकि अप्रैल में चीन में यह बढ़ी (चार्ट 11.8बी)।

अप्रैल 2024 में, वैश्विक इक्विटी बाजार मार्च में दर्ज किए गए उच्च स्तर से पीछे हट गए। मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व इक्विटी सूचकांक में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि अमेरिका में मजबूत उपभोक्ता मांग और उच्च पीसीई मुद्रास्फीति के आंकड़ों ने ब्याज दरों के लंबे समय तक उच्च रहने की चिंताओं को फिर से जगा दिया (चार्ट 11.9ए)। निराशाजनक सेमीकंडक्टर आय और बढ़ते जीपीआर ने भी गिरावट में योगदान दिया। हालांकि, मई के पहले पखवाड़े में इक्विटी बाजारों में सुधार हुआ क्योंकि मध्य पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव कम हो गया और अमेरिका में श्रम बाजार और मुद्रास्फीति में कमी के संकेत मिले। अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल - 10 वर्ष और 2 वर्ष दोनों - अप्रैल में 40 आधार अंकों (बीपीएस) से

अधिक बढ़ गई क्योंकि वित्तीय बाजारों ने 2024 में यूएस फेड द्वारा कम दर कटौती की कीमत लगाई। हालांकि, मई की शुरुआत में इसने प्रवृत्ति को उलट दिया, प्रत्येक में 30 बीपीएस से अधिक की नरमी आई (चार्ट 11.9बी)। मुद्रा बाजारों में, प्रतिबंधात्मक अमेरिकी मौद्रिक नीति और फेड द्वारा दरों में कटौती की कम संभावना के कारण अमेरिकी डॉलर सूचकांक मजबूत हुआ, लेकिन नरम अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रिंट और उपभोक्ता व्यय डेटा जारी होने के बाद मई के पहले पखवाड़े में इसमें नरमी दर्ज की गई। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक ने अप्रैल में ग्रीनबैंक की चाल को प्रतिबिंबित किया, जो पूंजी बहिर्वाह, विशेष रूप से इक्विटी सेगमेंट में (चार्ट 11.9सी और 11.9डी) द्वारा बढ़ा दिया गया था।

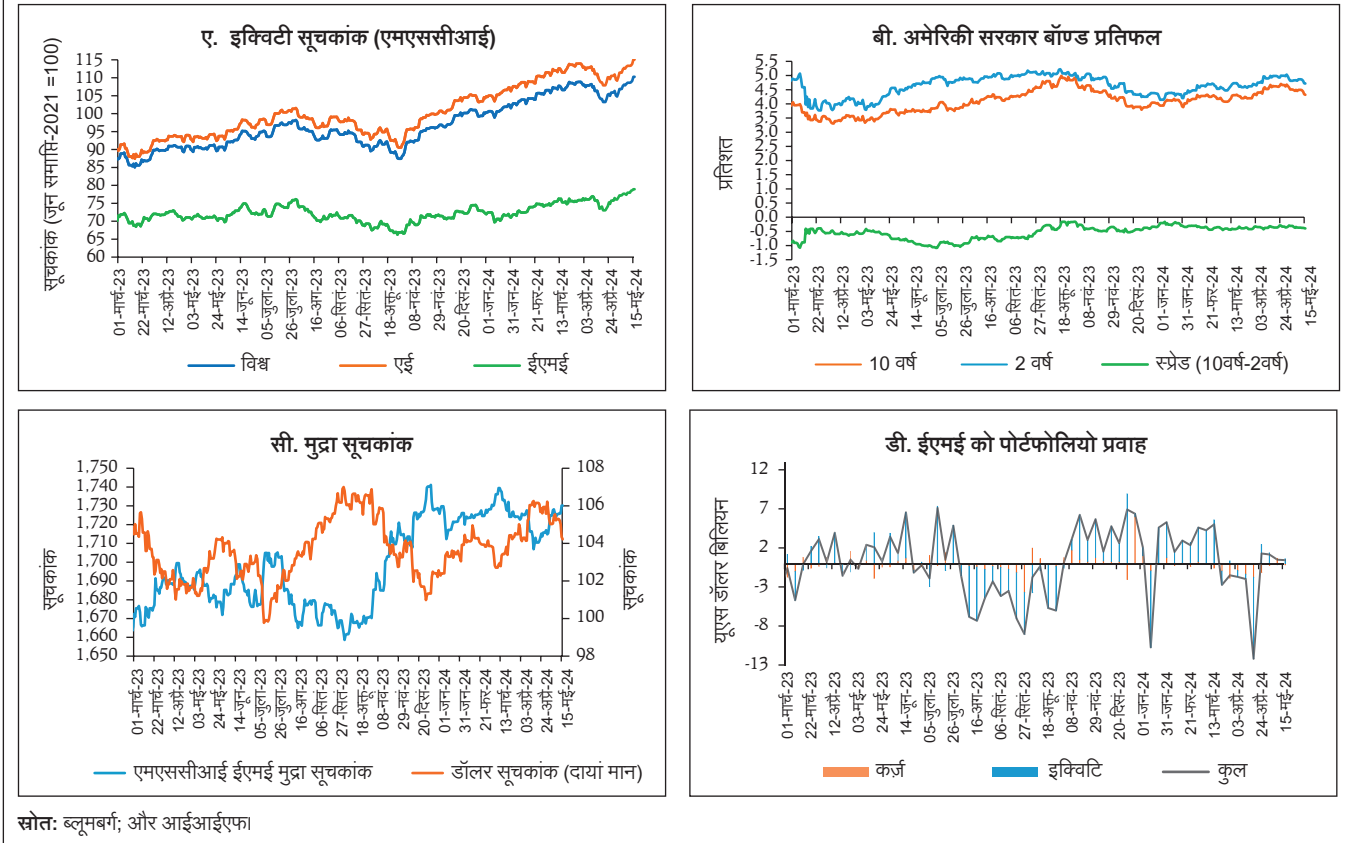
प्रमुख केंद्रीय बैंकों, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, ने अपनी प्रतिबंधात्मक नीतिगत स्थिति को बरकरार रखा, तथा अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरों को स्थिर रखा। दूसरी ओर, चेक गणराज्य और स्वीडन ने अपनी मई बैठकों में अपनी नीतिगत दरों में क्रमशः 50 आधार अंकों और 25 आधार

चार्ट 11.8 : मुद्रास्फीति - ई और ईएमई



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

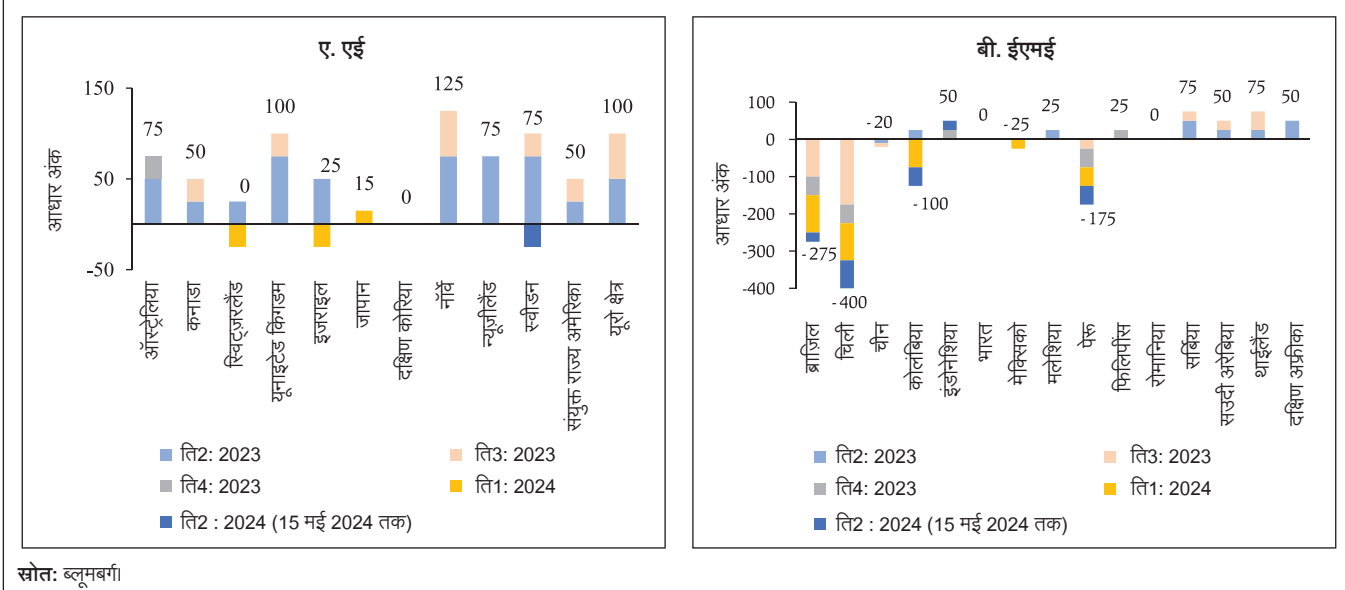
चार्ट II.9 वैश्विक वित्तीय बाजार



अंकों की कमी की (चार्ट II.10ए)। उदीयमान बाज़ार अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंकों में, ब्राजील और पेरू ने अपनी मई बैठकों में अपनी नीतिगत दरों में 25 आधार अंकों की कमी की, जबकि

हंगरी और कोलंबिया ने अपनी अप्रैल बैठकों में अपनी बेंचमार्क दरों में 50 आधार अंकों की कटौती की। हालांकि, इंडोनेशिया ने पिछली पांच बैठकों में दर को स्थिर रखने के बाद अपनी अप्रैल

चार्ट II.10: नीति दरों में परिवर्तन



बैठक में अपनी नीतिगत दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की (चार्ट II.10बी)।

III. घरेलू घटनाक्रम

भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपूर्ति शृंखला पर दबाव डालने वाली भू-राजनीतिक प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है (चार्ट III.1ए)। आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) के अनुसार, अप्रैल में गतिविधि में उछाल आया और शुरुआती अनुमान बताते हैं कि 2024-25 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत के करीब रहने की संभावना है (चार्ट III.1बी और III.1सी)।

सकल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक अप्रैल 2024 में घरेलू मांग की स्थिति में निरंतर गति की ओर इशारा करते हैं। मार्च 2024 में 10.4 करोड़ के रिकॉर्ड उच्च स्तर से क्रमिक मॉडरेशन के बावजूद, अप्रैल 2024 में ई-वे बिल में 14.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.2ए)। अप्रैल 2024 में टोल संग्रह में 8.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

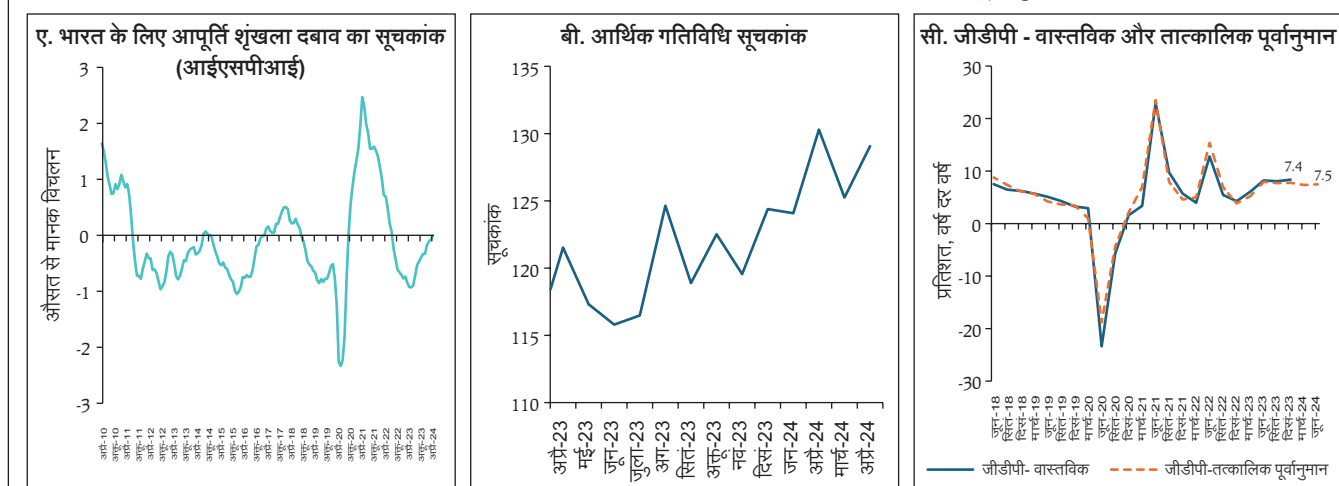
अप्रैल 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 25.4 प्रतिशत

(वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसकी अगुवाई दोपहिया और तिपहिया खंड में मजबूत वृद्धि ने की, जबकि यात्री वाहनों ने अब तक की सबसे अधिक मासिक बिक्री दर्ज की।⁸ घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री में अप्रैल 2024 में सुधार के संकेत मिले (चार्ट III.3ए और III.3बी)। वाहन पंजीकरण में अप्रैल 2024 में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई, जो गैर-परिवहन वाहन खंड के कारण हुई (चार्ट III.3सी)। अप्रैल 2024 में औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसकी अगुवाई मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) ने की [चार्ट III.3डी]।

रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा किए गए व्यापार सर्वेक्षण के अनुसार, खेल के सामान, खाद्य और किराना, परिधान और कपड़े, जूते और त्वरित सेवा रेस्तरां की बिक्री वृद्धि में तेजी के कारण खुदरा बिक्री वृद्धि (वर्ष दर वर्ष) में पिछली तिमाही की तुलना में ति4: 2023-24 में गति मिली (चार्ट III.4)।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को इस वित्तीय वर्ष और अगले वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूरा होने की उम्मीद है। इस वर्ष लगभग ₹700 बिलियन मूल्य की⁹ हरित ऊर्जा परियोजनाएँ चालू होने वाली हैं, जो किसी भी एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक निवेश पूर्णता को दर्शाती हैं। इसके अलावा, पर्यावरण के

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान



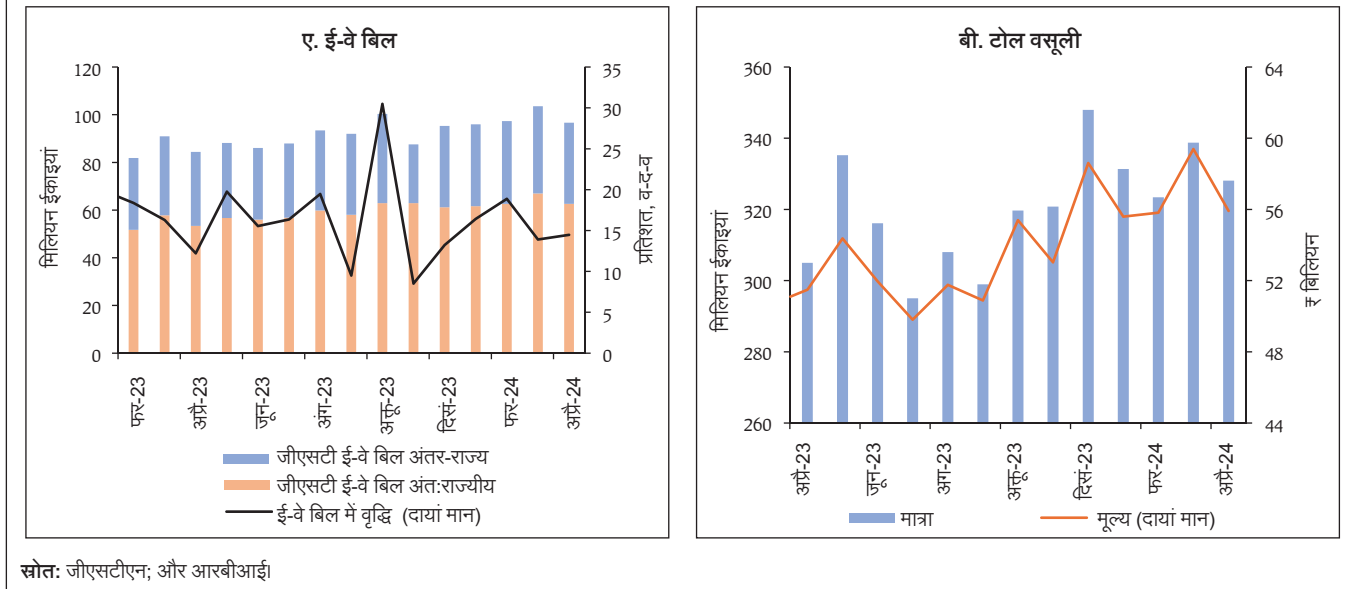
नोट: आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्तियों को लेते हुए किया गया। ईएआई फरवरी 2020 में 100 तक बढ़ गया और अप्रैल 2020 में 0 था जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।

स्रोत: आरबीआई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

⁸ <https://www.carandbike.com/news/auto-sales-april-2024-india-saw-25-growth-in-volume-driven-by-strong-two-wheeler-sales-3213133>

⁹ <https://industryoutlook.cmie.com/kommon/bin/sr.php?kall=wshreport&nvdrt=20240429162158756&nvpc=055000000000&nvtype=ANALYSIS+%26+OUTLOOK&icode=0101030110000000&ver=pf>
(Centre for Monitoring Indian Economy)

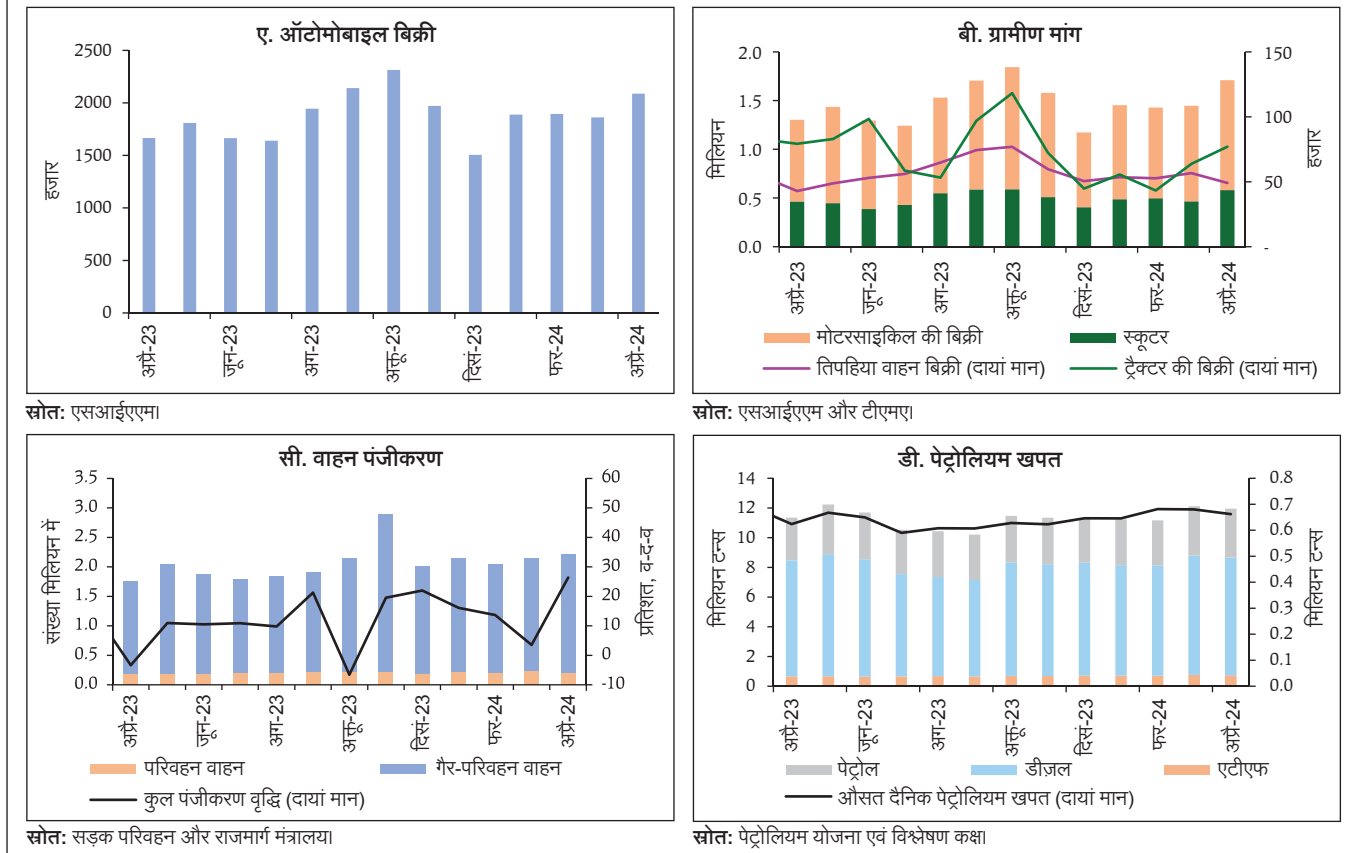
चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल वसूली

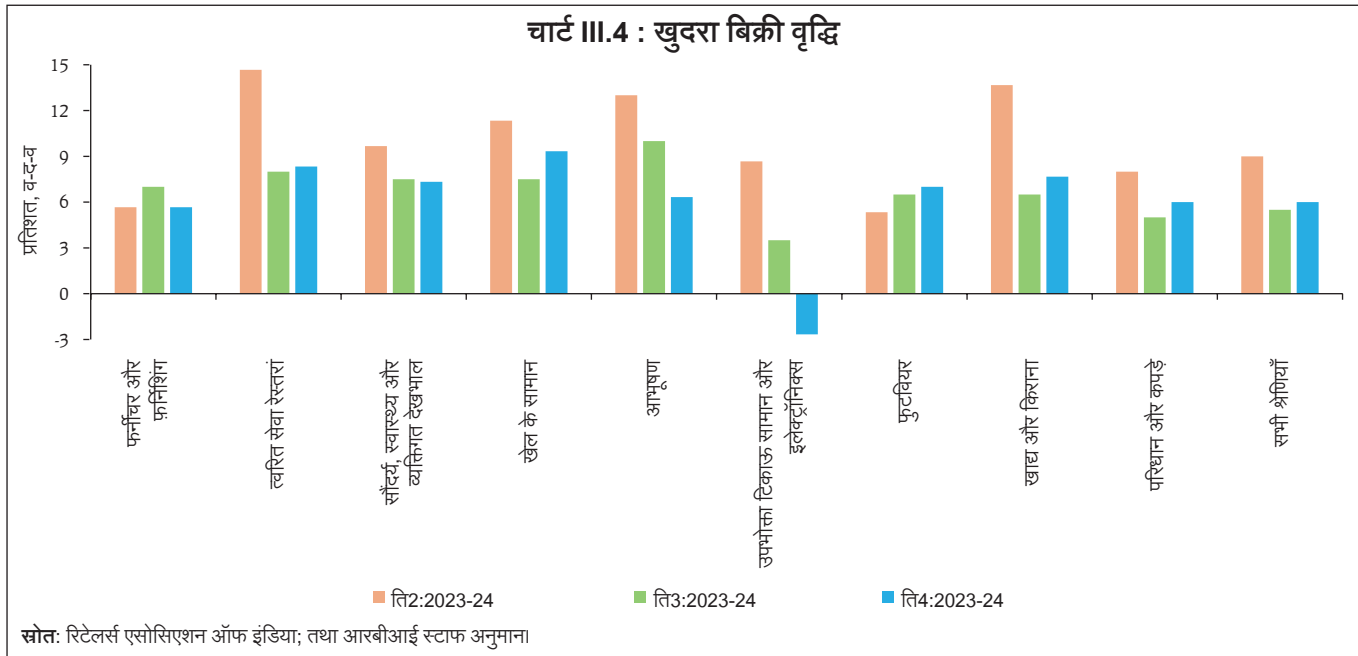


अनुकूल ऊर्जा स्रोतों पर भारत की निर्भरता बढ़ाने पर नीतिगत ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित होकर, 2025-26 तक वृद्धिशील

परियोजना निवेश बढ़कर ₹765.2 बिलियन हो जाने का अनुमान है।

चार्ट III.3 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक

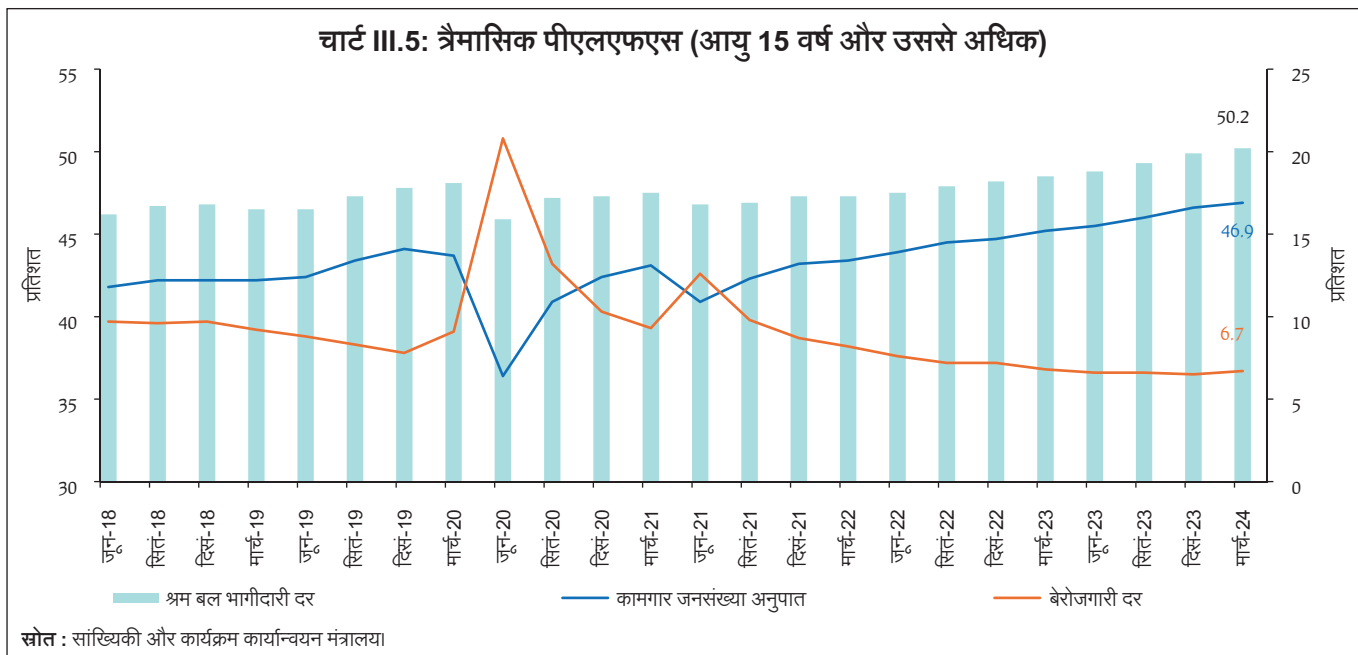




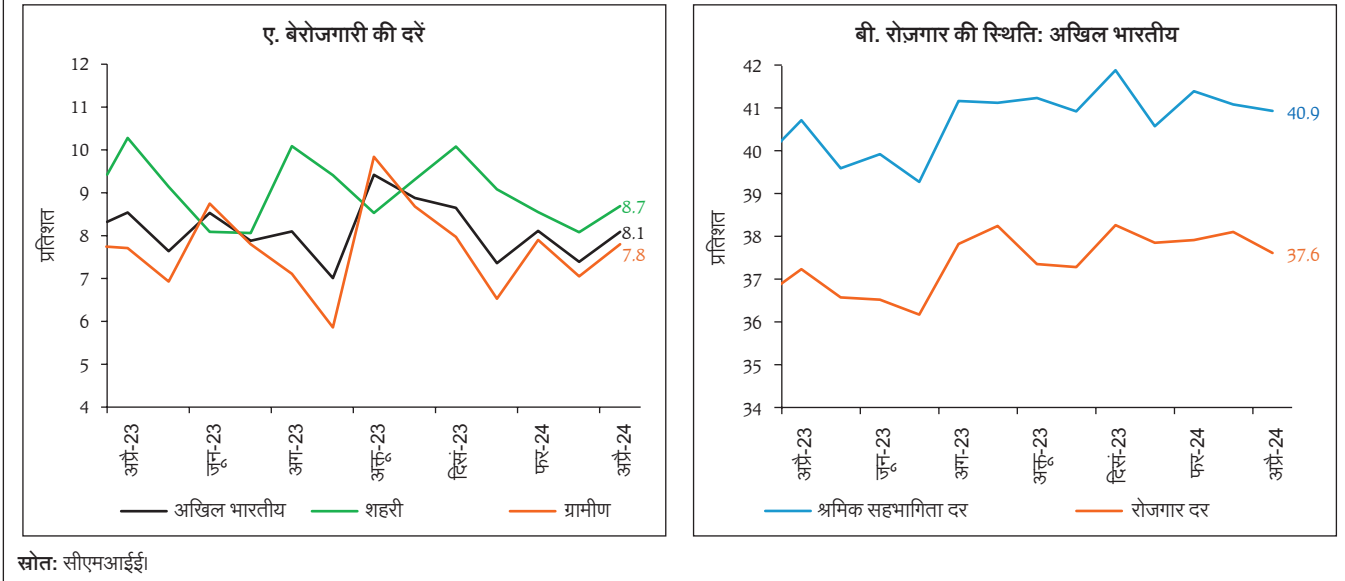
15 मई 2024 को जारी त्रैमासिक शहरी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) और श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) ति4: 2023-24 के दौरान बढ़ गया – 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एलएफपीआर बढ़कर 50.2 प्रतिशत हो गया, जो सर्वेक्षण की शुरुआत से अब तक सबसे अधिक है (चार्ट III.5)। अधिक महिला श्रमिकों के कारण डब्ल्यूपीआर

बढ़कर 46.9 प्रतिशत हो गया, जो तीसरी तिमाही में 46.6 प्रतिशत था। रोजगार में वृद्धि स्वरोजगार से प्रेरित थी, जबकि नियमित वेतनभोगी और आकस्मिक श्रम की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के समान ही रही। बेरोजगारी दर (यूआर) तीसरी तिमाही के 6.5 प्रतिशत के मुकाबले 6.7 प्रतिशत थी।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में अखिल भारतीय यूआर 8.1



चार्ट III.6 श्रम बाजार स्थितियां



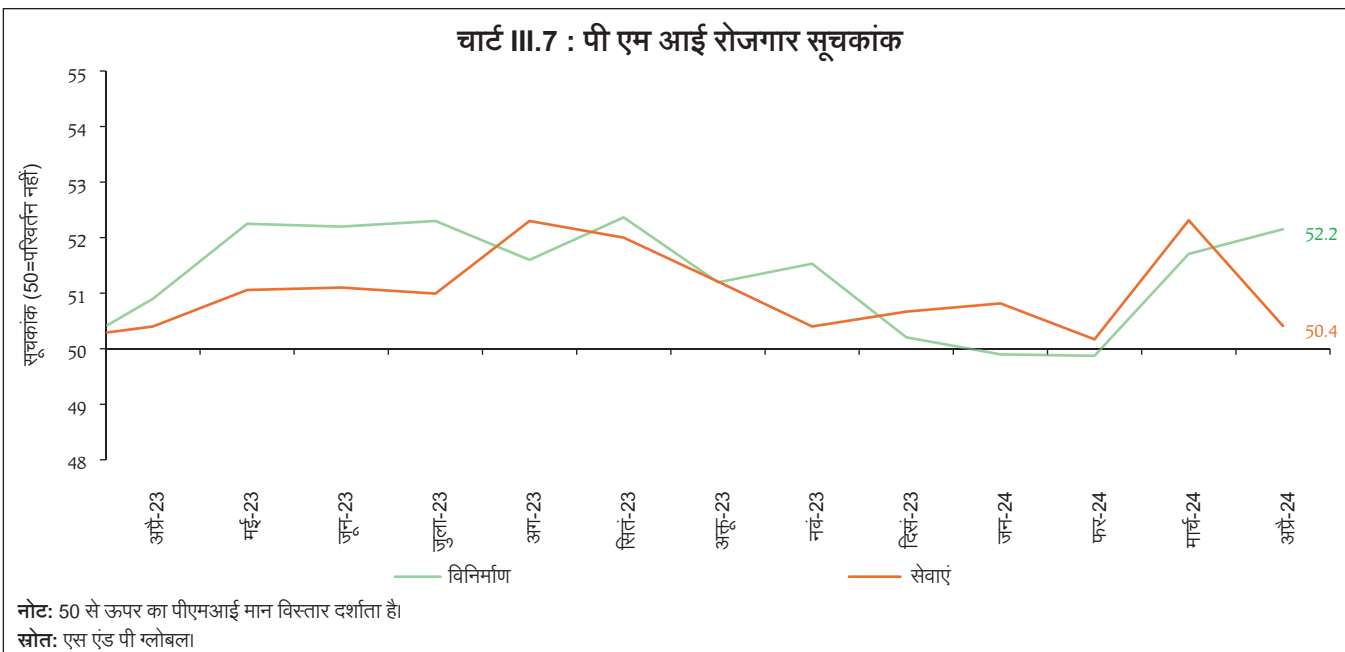
प्रतिशत था (चार्ट III.6ए)। एलएफपीआर और रोजगार दर (ईआर) पिछले महीने की तुलना में मामूली रूप से गिर गई (चार्ट III.6बी)।

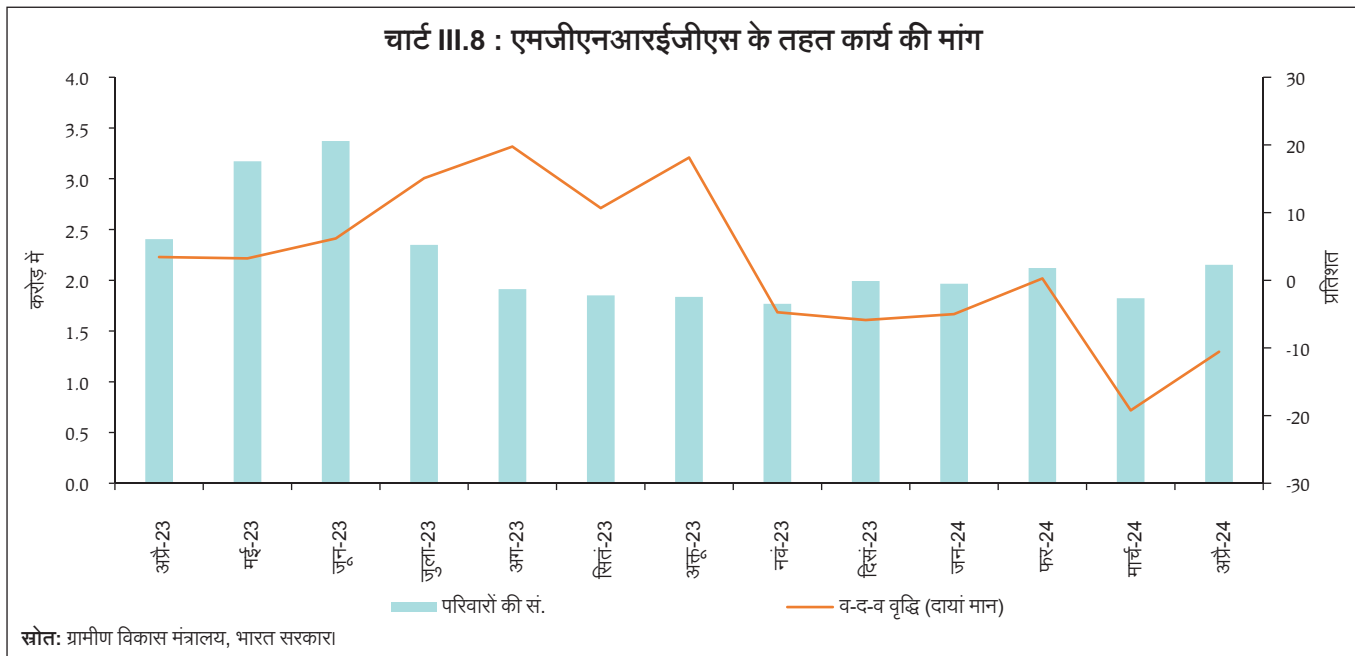
अप्रैल 2024 में, संगठित विनिर्माण रोजगार ने पिछले सात महीनों में सबसे तेज विस्तार दर्ज किया, जैसा कि पीएमआई रोजगार परिदृश्य द्वारा दर्शाया गया है। अप्रैल में सेवा रोजगार

सृजन विस्तार क्षेत्र में जारी रहा, हालांकि मार्च में दर्ज सात महीने के उच्चतम स्तर से क्रमिक रूप से इसमें कमी आई (चार्ट III.7)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की घरेलू मांग में अप्रैल में 18.0 प्रतिशत (मासिक) की वृद्धि देखी गई, जबकि देश के अधिकांश हिस्सों

चार्ट III.7 : पी एम आई रोजगार सूचकांक

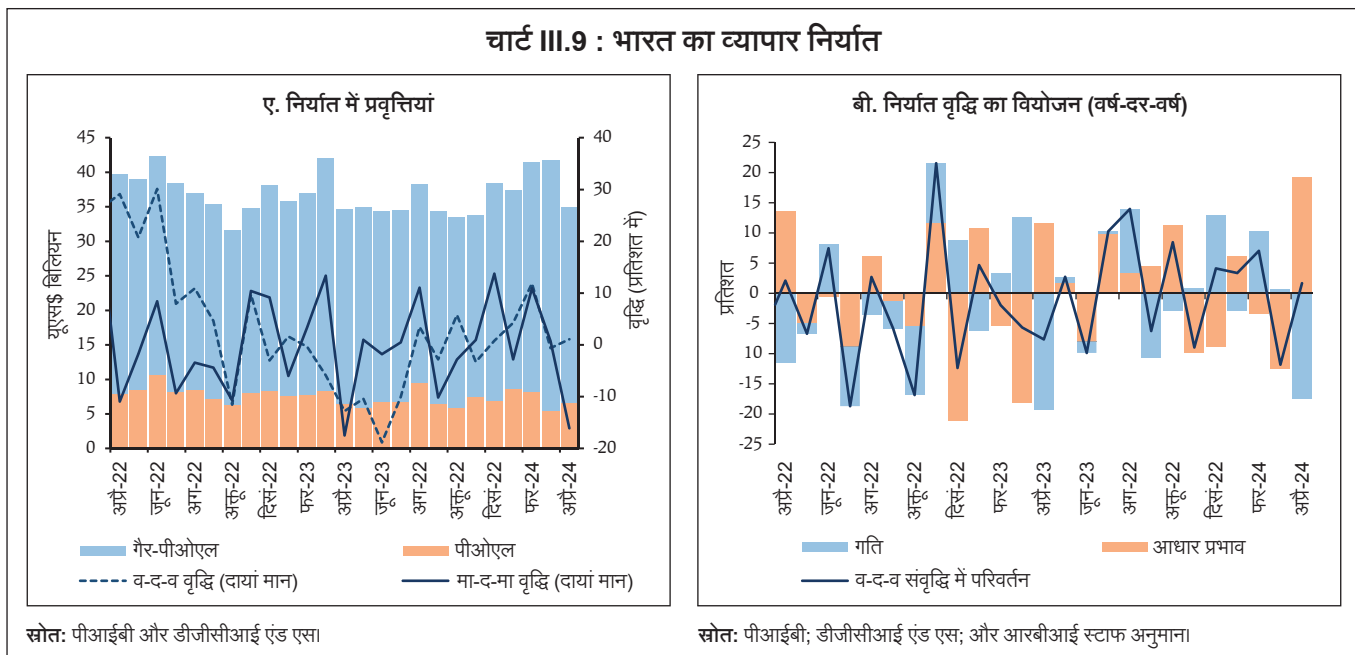




में रबी की कटाई का मौसम समाप्त हो रहा है। हालांकि, मनरेगा रोजगार में सालाना आधार पर 10.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.8)।

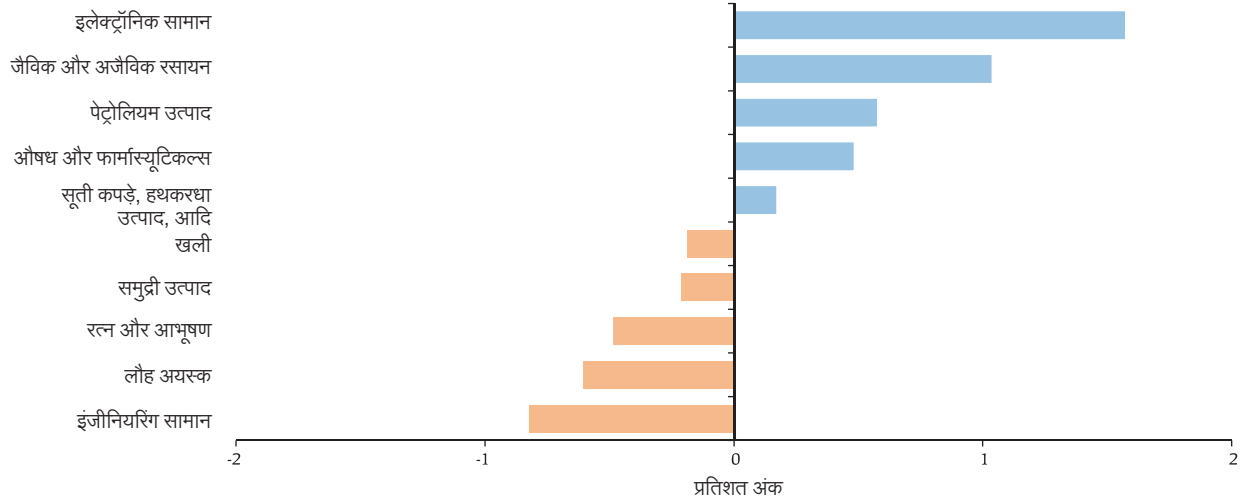
अप्रैल 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 35.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो 1.1 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि के साथ अनुकूल आधार प्रभाव के रूप में ऋणात्मक गति की भरपाई से अधिक है (चार्ट III.9)।

30 प्रमुख वस्तुओं में से 13 वस्तुओं (निर्यात बास्केट का 46.7 प्रतिशत हिस्सा) ने वर्ष दर वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया। इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैविक और अजैविक रसायन, पेट्रोलियम उत्पाद, दवाएँ और फार्मास्यूटिकल्स, और सूती धागा, कपड़े, मेड-अप और हथकरघा उत्पादों ने निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि इंजीनियरिंग सामान, लौह अयस्क, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और खली, ने अप्रैल में समग्र निर्यात को नीचे गिरा दिया (चार्ट III.10)।



स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट III.10 : भारत का व्यापार निर्यात – सापेक्ष योगदान
(अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024)**



स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

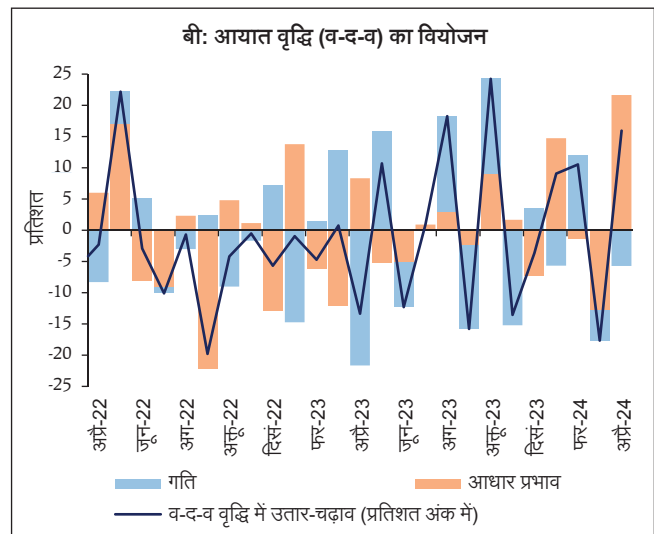
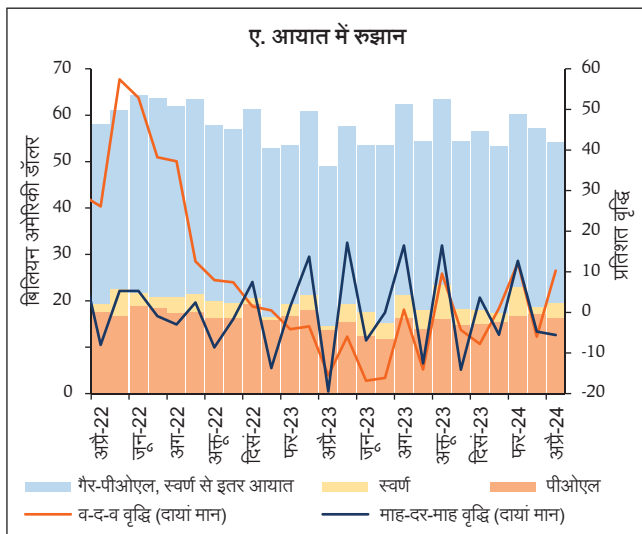
इस महीने में 10.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 54.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापारिक आयात हुआ, क्योंकि आधार प्रभाव ने ऋणात्मक गति को संतुलित कर दिया (चार्ट III.11)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 16 वस्तुओं (आयात बास्केट का 58.7 प्रतिशत हिस्सा) ने अप्रैल में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

पेट्रोलियम कच्चे तेल और उत्पाद, स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दालें और वनस्पति तेल ने आयात वृद्धि का समर्थन

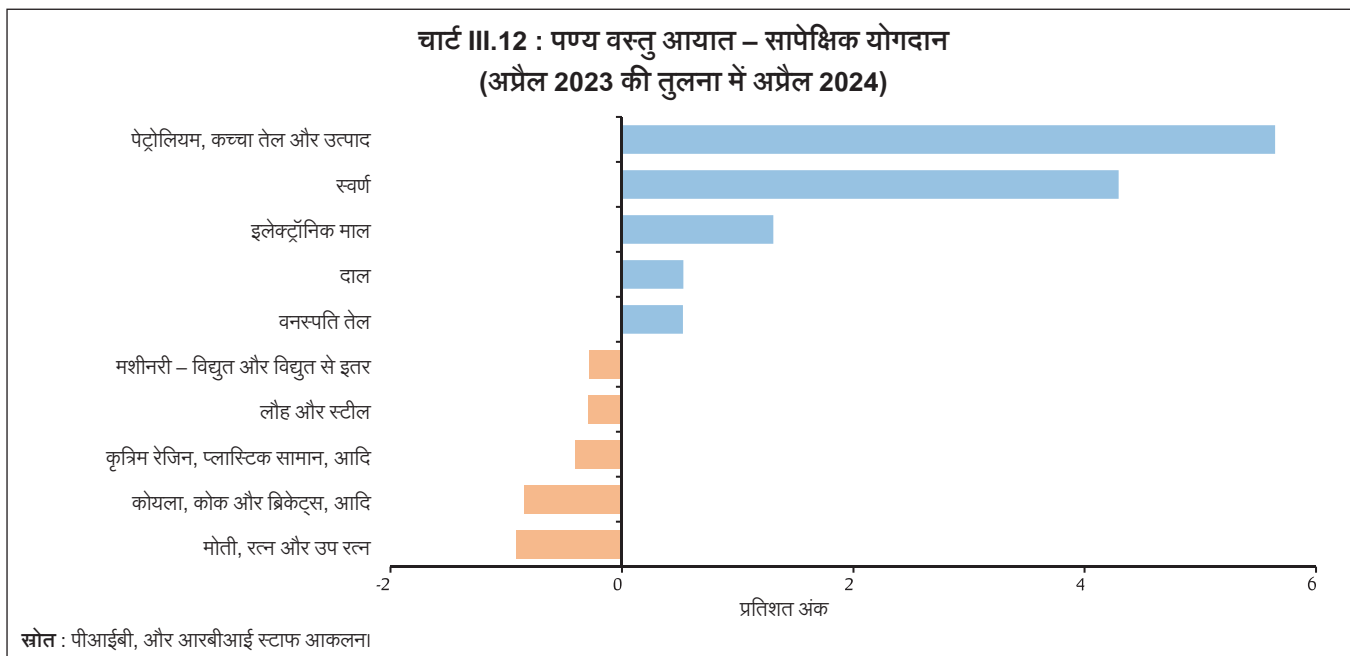
किया, जबकि मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, कोयला, कृत्रिम रेजिन, प्लास्टिक सामग्री, लोहा और इस्पात, और मशीनरी अप्रैल में मुख्य बाधा थे (चार्ट III.12)।

अप्रैल 2024 में वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 5 महीने के उच्चतम स्तर 19.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, क्योंकि क्रमिक आधार पर आयात की तुलना में निर्यात में अधिक कमी आई। तेल से इतर घाटा मार्च में 3.8 बिलियन अमेरिकी

चार्ट III.11 : भारत का पण्य आयात

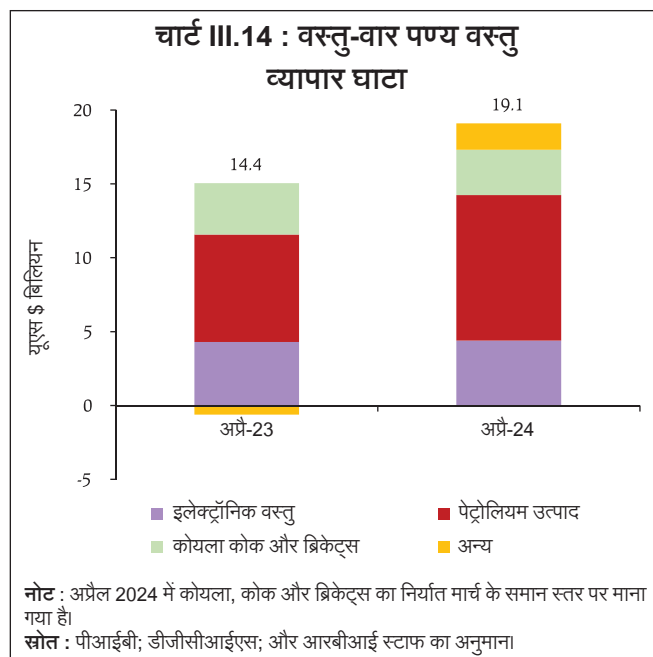
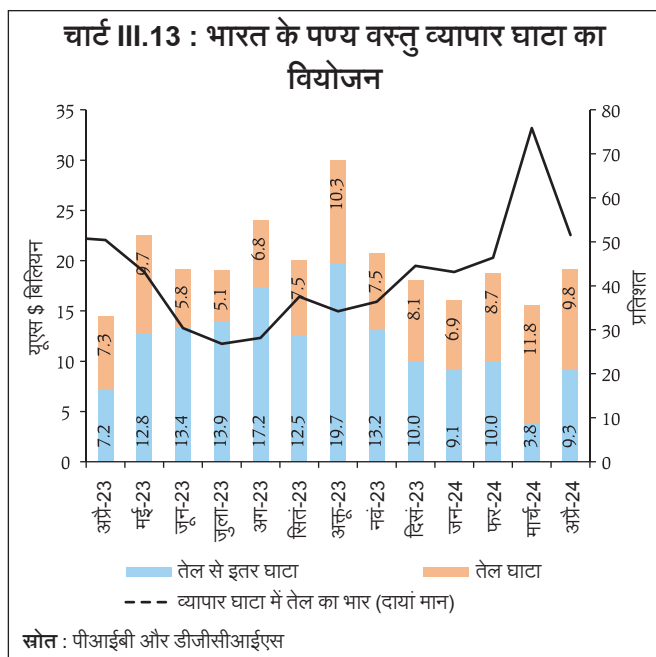


स्रोत: पीआईबी, डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

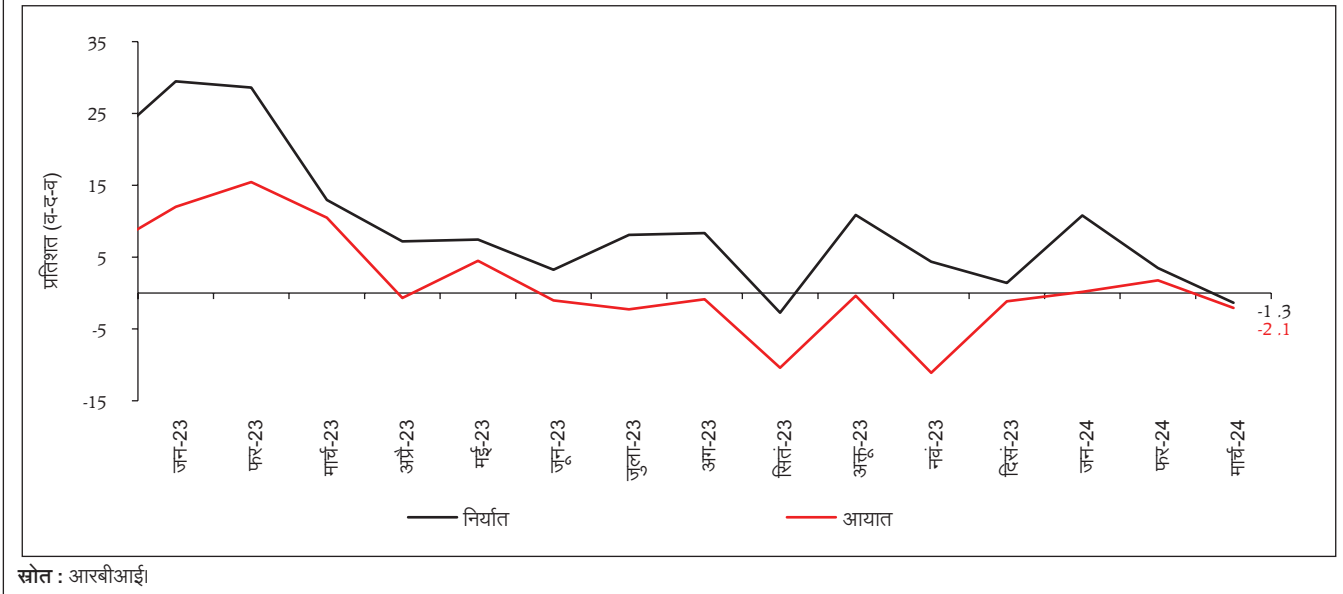


डॉलर से बढ़कर अप्रैल में 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, कुल वस्तु व्यापार घाटे में तेल घाटे की हिस्सेदारी अप्रैल में घटकर 51.5 प्रतिशत रह गई, जो एक महीने पहले 75.9 प्रतिशत थी (चार्ट III.13)। अप्रैल में व्यापार घाटे का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान थे (चार्ट III.14)।

मार्च 2024 में सेवा निर्यात 1.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जो व्यापार, सॉफ्टवेयर और परिवहन सेवाओं में मंदी को दर्शाता है। सेवा आयात 2.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 16.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया, जिसका मुख्य कारण परिवहन सेवाओं में गिरावट है (चार्ट III.15)। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 में निवल सेवा निर्यात



चार्ट III.15 : सेवाएँ निर्यात और आयात : वृद्धि दरें



आय 0.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गई। हालांकि, भारत की सॉफ्टवेयर सेवाओं के लिए दृष्टिकोण सहायक बना हुआ है, वैश्विक आईटी व्यय 2024 में 8 प्रतिशत बढ़कर 5.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है¹⁰

अप्रैल 2024 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह (केंद्र

और राज्य) में वर्ष-दर-वर्ष 12.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पहली बार ₹2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया (चार्ट III.16)। अप्रैल में आमतौर पर वर्ष के अंत में आर्थिक गतिविधि अधिक होने के कारण किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए सबसे अधिक जीएसटी संग्रह होता है¹¹

चार्ट III.16 : मासिक जीएसटी राजस्व



¹⁰ गार्टनर इंक., 17 अप्रैल 2024.

¹¹ अप्रैल का जीएसटी संग्रह वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने मार्च में हुई आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है।

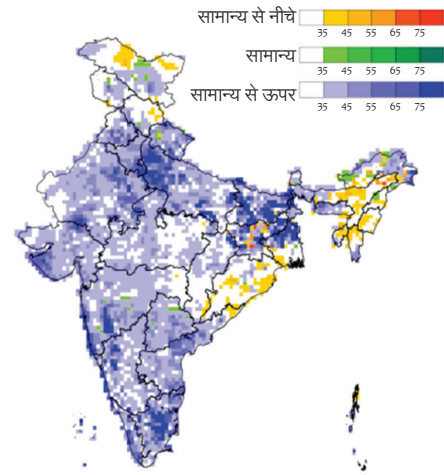
सकल आपूर्ति

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) सीजन के लिए पहले दीर्घावधिक पूर्वानुमान के अनुसार, इस वर्ष जून-सितंबर 2024 के दौरान वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है¹² जिसमें देश के अधिकांश भागों में सामान्य से अधिक वर्षा होगी (चार्ट III.17)।

इसके अतिरिक्त, आईएमडी¹³ के अनुसार, एसडब्ल्यूएम के 01 जून की सामान्य तिथि के बजाय 31 मई को केरल में स्थापित होने की संभावना है। 13 मई 2024 की अपनी नवीनतम रिलीज़ में, राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन (एनओए) ने जून 2024 में अल-नीनो से अल नीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) में शून्य बदलाव का पूर्वानुमान लगाया है, जिसमें जून-अगस्त 2024 (49 प्रतिशत संभावना के साथ) या जुलाई-सितंबर 2024 (69 प्रतिशत संभावना के साथ) तक ला-नीना विकसित हो सकता है। यह आमतौर पर बढ़ी हुई वर्षा गतिविधि से जुड़ा होता है।

हालांकि, गर्मियों/मानसून-पूर्व कम बारिश, सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान और गर्मी के मौसम में लू के दिन¹⁴, प्रमुख जोखिम कारक बने हुए हैं (चार्ट III.18ए)। 15 मई 2024 तक, गर्मियों की बारिश (मार्च-मई) लंबी अवधि के औसत

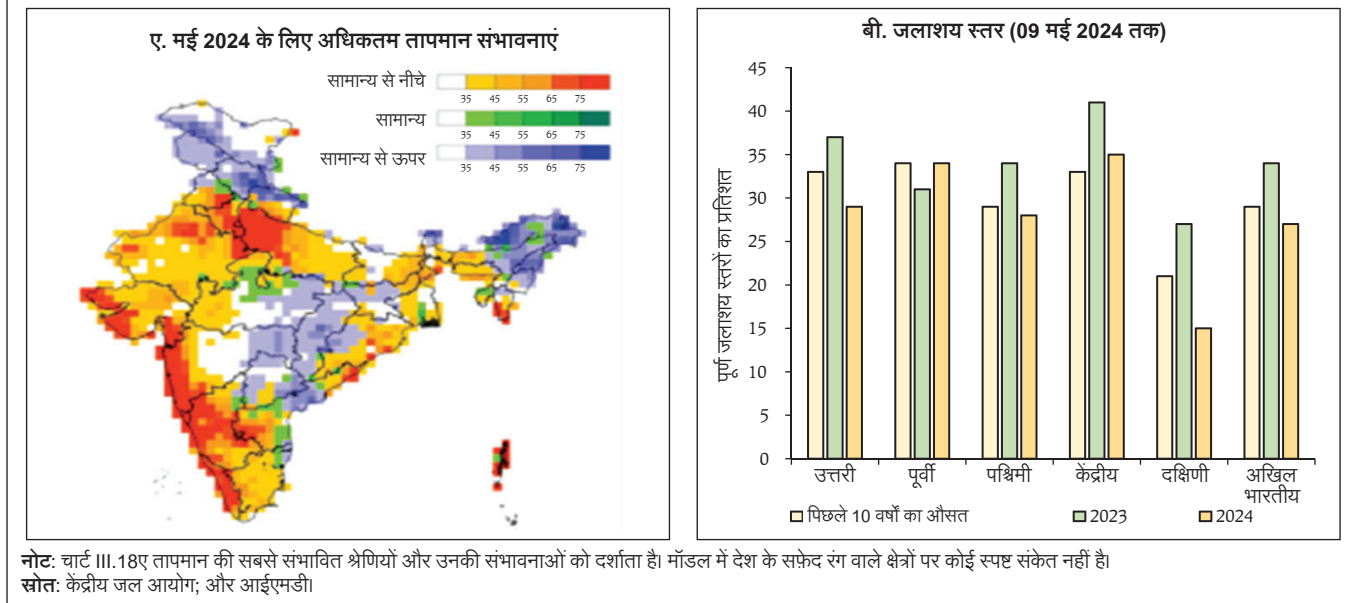
चार्ट III.17: आईएमडी प्रथम चरण 2024 एसवीएम पूर्वानुमान



नोट: चार्ट III.17 वर्षा की सबसे संभावित श्रेणियों और उनकी संभावनाओं को दर्शाता है। मॉडल में देश के सफेद छायांकित क्षेत्रों पर कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।
स्रोत: आईएमडी।

(एलपीए) से 12 प्रतिशत कम रही, जबकि एक वर्ष पहले एलपीए से 18 प्रतिशत अधिक थी। प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण स्तर अखिल भारतीय स्तर पर कुल जलाशय क्षमता का 27 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.8 प्रतिशत कम और दशकीय औसत से 7.7 प्रतिशत कम था (चार्ट III.18बी)।

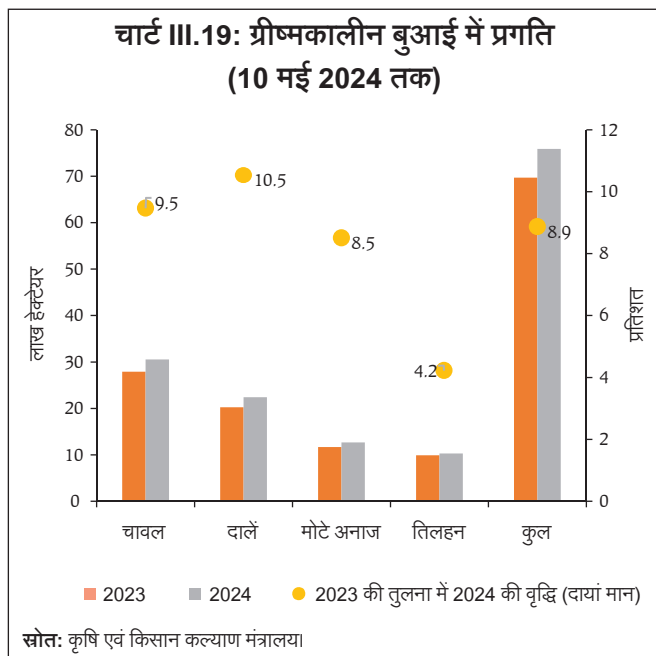
चार्ट III.18 : मौसम की स्थिति और जल-स्तर



¹² 15 अप्रैल 2024 को जारी पूर्वानुमान के अनुसार, ± 5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ वर्षा दीर्घ अवधि औसत (एलपीए) के 106 प्रतिशत पर रहने की संभावना है।

¹³ यह 15 मई 2024 को आईएमडी की नवीनतम रिलीज़ के अनुसार है। पूर्वानुमान में ± 4 दिनों की मॉडल त्रुटि है।

¹⁴ 1 मई 2024 को आईएमडी द्वारा जारी 'मासिक तापमान और वर्षा संभावना' के अनुसार।



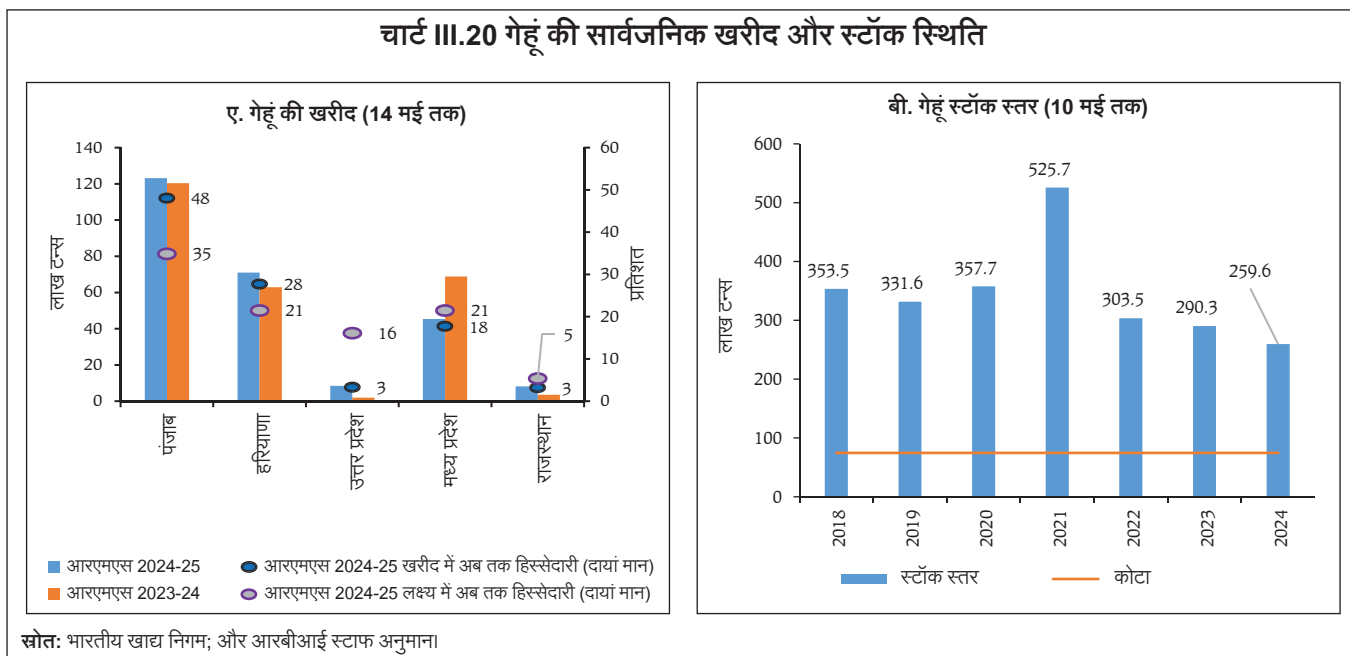
दलहन, मोटे अनाज और तिलहन के तहत अधिक रकबा है (चार्ट III.19)।

रबी विपणन सीजन (आरएमएस) में अब तक (14 मई, 2024 तक) गेहूं की संचयी खरीद 256.4 लाख टन रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मामूली रूप से कम थी (चार्ट III.20ए)। खरीद में तेजी लाने के लिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसी चुनिंदा राज्य सरकारों ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में खरीद मानदंडों में ढील दी है।

01 मई को, गेहूं का स्टॉक 259.6 लाख टन था जो तिमाही बफर मानदंड (अप्रैल-जून 2024) से काफी अधिक था (चार्ट III.20बी)। खरीफ विपणन सीजन में अब तक (01 अक्टूबर, 2023 – 14 मई, 2024) चावल की संचयी खरीद 482.8 लाख टन रही। 01 मई, 2024 तक, चावल का सार्वजनिक स्टॉक 508.9 लाख टन (बफर मानदंड का 3.7 गुना) था।

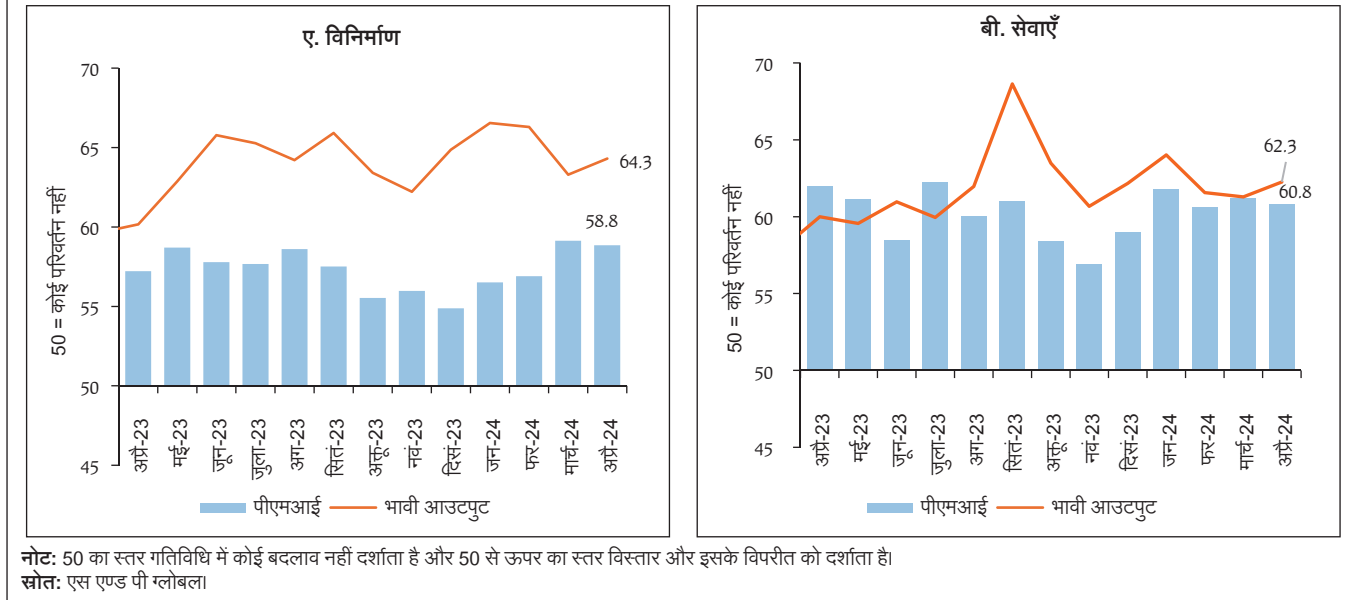
10 मई, 2024 तक ग्रीष्मकालीन फसल क्षेत्र¹⁵ के 75.9 लाख हेक्टेयर में बुआई की जा चुकी है, जिसमें एक साल पहले की तुलना में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जिसमें चावल,

अनुक्रमिक परिनियमन के बावजूद, विनिर्माण के लिए हेडलाइन पीएमई अप्रैल 2024 में विस्तारवादी क्षेत्र में बना रहा, जो नए कार्यादेश और उत्पादन से उत्साहित था (चार्ट III.21ए)। सेवाओं



¹⁵ गर्मी के मौसम में कुल खाद्यान्न उत्पादन (2022-23) के लगभग 5 प्रतिशत में कुछ फसलों मूंग (50.3 प्रतिशत), बाजरा (9.5 प्रतिशत), उड़द (8.7 प्रतिशत), चावल (7.5 प्रतिशत) और मक्का (7.1 प्रतिशत) की अपेक्षाकृत अधिक हिस्सेदारी होती है।

चार्ट III.21: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



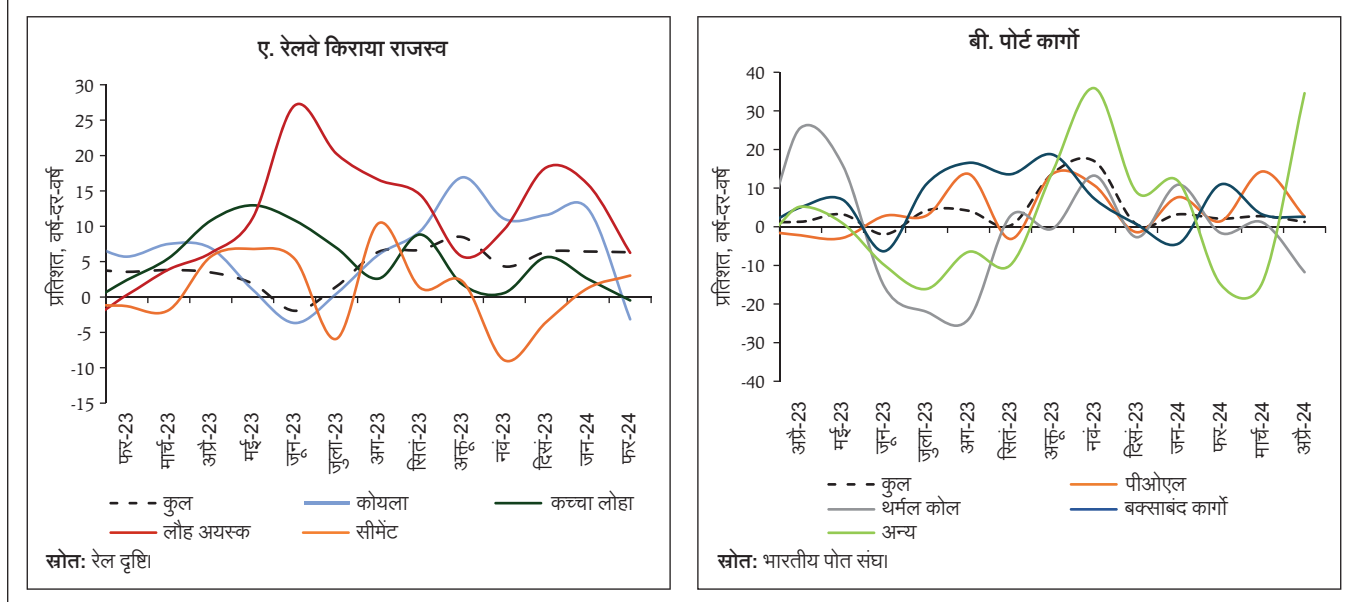
के लिए नए व्यवसाय और उत्पादन में वृद्धि से प्रेरित पीएमआई का भी विस्तार हालांकि धीमी गति से जारी रहा। (चार्ट III.21बी)।

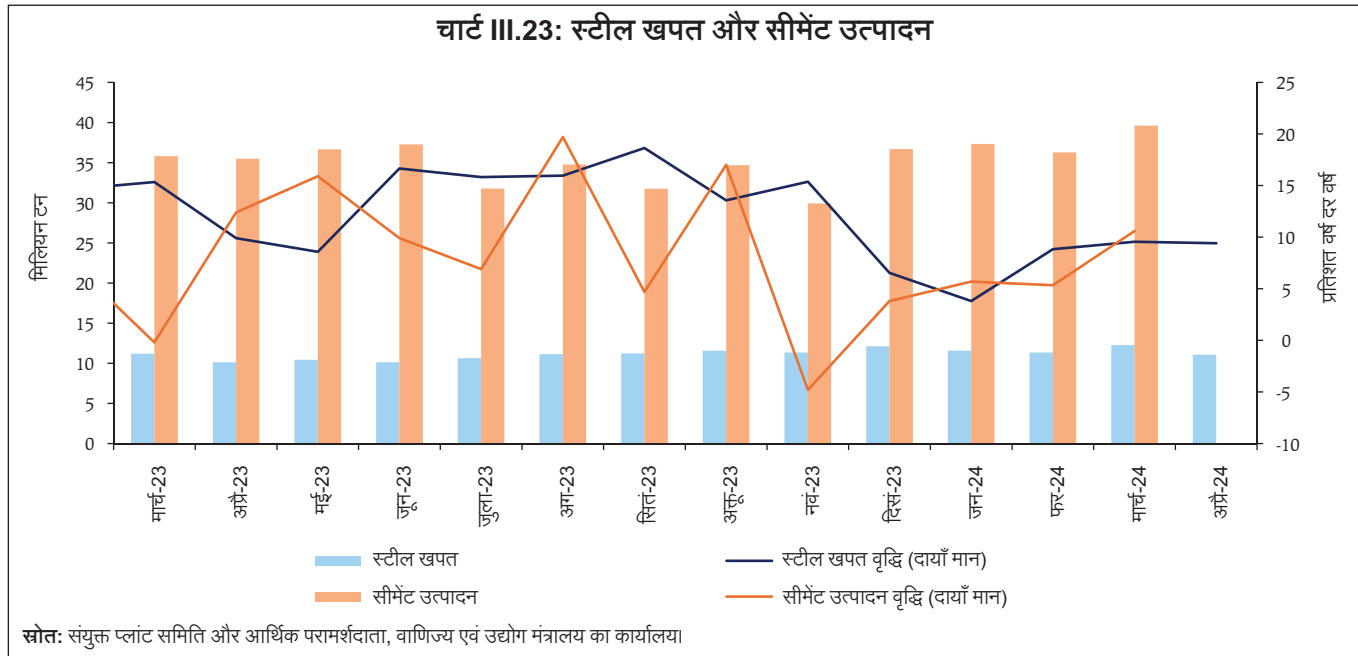
माल परिवहन के संकेतकों ने मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित की। फरवरी 2024 में रेलवे माल राजस्व में 6.3 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसे सीमेंट के माल ढुलाई में वृद्धि से मदद

मिली (चार्ट III.22ए)। अप्रैल 2024 में प्रमुख बंदरगाहों पर कार्गो यातायात में 1.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कोकिंग कोयला और अन्य विविध कार्गो (चार्ट III.22बी) शामिल थे।

निर्माण क्षेत्र के संकेतकों में लगभग दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई क्योंकि अप्रैल 2024 में स्टील की खपत में 9.4 प्रतिशत की

चार्ट 22: रेलवे ट्रैफिक और पोर्ट कार्गो





वृद्धि हुई और मार्च 2024 में सीमेंट उत्पादन में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.23)।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक अप्रैल 2024 में आर्थिक गतिविधियों में समुत्थानशीलता दर्शाते हैं (सारणी III.1)।

सारणी III.1: वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	जुला-23	अग-23	सित-23	अक्टू-23	नव-23	दिस-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रै-24
शहरी मांग	यात्री वाहन बिक्री	2.9	11.6	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2
	दोपहिया वाहनों की बिक्री	-7.2	0.6	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0	15.3	30.8
ग्रामीण मांग	तिपहिया वाहनों की बिक्री	78.9	68.8	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6	4.3	14.5
	ट्रैक्टर बिक्री	6.1	1.1	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-33.0	-23.1	-3.0
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	6.9		3.2			-3.8				
	रेलवे माल यातायात	1.5	6.4	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	6.3		
	पोर्ट कार्गो ट्रैफिक	4.3	4.4	0.3	13.8	16.9	0.6	3.2	-1.4	2.7	1.3
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	-4.1	6.0	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	7.6	8.7	-10.1
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	1.0	7.4	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	25.7	22.5	20.7
	घरेलू हवाई यात्री यातायात *	26.3	23.6	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	2.2	4.7	3.3
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात *	23.6	21.5	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	15.2	15.0	15.0
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	16.4	19.5	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5
	जीएसटी ई-वे बिल (इंट्रा स्टेट)	20.8	22.6	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	9.1	14.4	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6
	होटल अधिभोग दर@	60.9	60.9	61.0	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	14.2	13.9	18.3	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	
पर्यटक आगमन	13.6	22.6	17.5	19.8	16.8	7.8	10.4	11.8			
निर्माण	इस्पात खपत	15.8	16.0	18.6	13.6	15.4	6.5	3.8	8.8	9.6	9.4
	सीमेंट उत्पादन	6.9	19.7	4.7	17.0	-4.8	3.8	5.7	5.3	10.6	
पीएमआई इंडेक्स#	सेवाएं	62.3	60.1	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8

<< संकुचन ----- वस्तुतः >>

नोट: #: स्तरों में डेटा. *: अप्रैल 2024 के आंकड़े दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित हैं। @: डेटा दर में है, वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर में नहीं। जुलाई-2021 से आज तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी, आईएचएस मार्केटिंग, सियाम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; और संयुक्त संयंत्र समिति।

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय सीपीआई¹⁶ में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मार्च में 4.9 प्रतिशत से अप्रैल 2024 में 4.8 प्रतिशत तक कम हो गई क्योंकि 48 बीपीएस की सकारात्मक गति 51 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव के ऑफसेट से अधिक थी (चार्ट III.24)। प्रमुख समूहों में, खाद्य और कोर समूहों (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) के लिए गति लगभग क्रमशः 65 बीपीएस और 55 बीपीएस पर सकारात्मक थी, जबकि ईंधन समूह ने लगभग 100 बीपीएस की नकारात्मक गति दर्ज की।

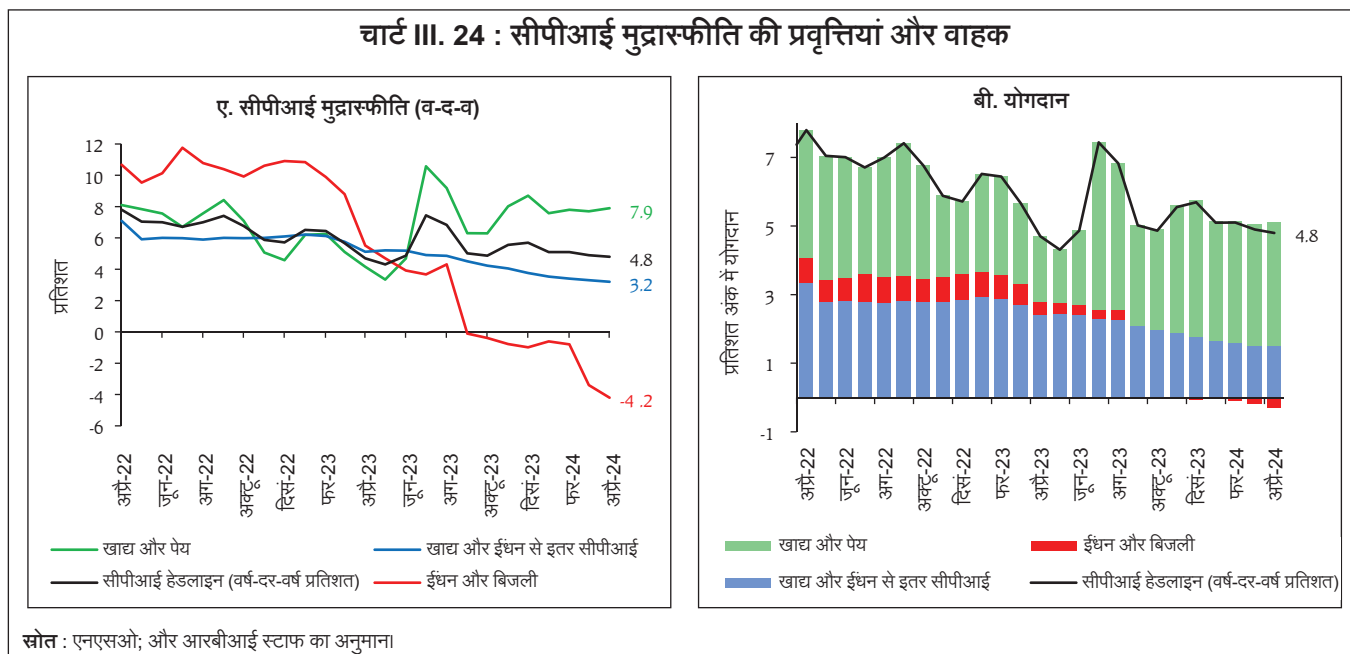
खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मार्च में 7.7 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में 7.9 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में, अनाज, मांस और मछली और फलों में मुद्रास्फीति में मजबूती आई जबकि अंडे, दूध, सब्जियां, दालें, चीनी, मसाले, गैर-मादक पेय और तैयार भोजन ने मुद्रास्फीति में कमी दर्ज की (चार्ट III.25)। खाद्य तेलों में, हालांकि धीमी दर पर अपस्फीति बनी रही।

ईंधन और प्रकाश की कीमतों में अपस्फीति मार्च के (-) 3.4 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल में करीब 4.2 प्रतिशत हो गई जो मुख्यतः व-द-व आधार पर एलपीजी मूल्यों में अपस्फीति के कारण थी। हालांकि, बिजली की कीमतों में अप्रैल 2024 में सालाना आधार पर 10.2 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर्ज की गई।

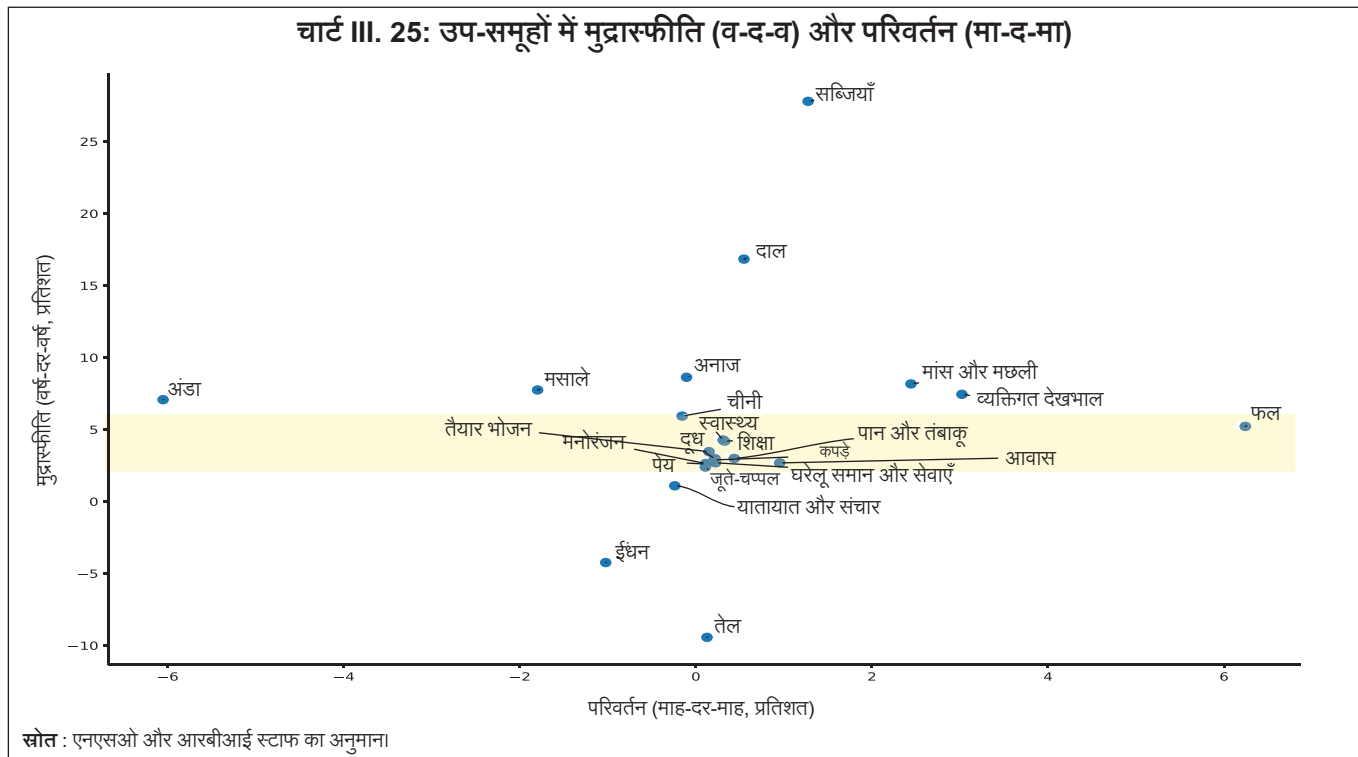
कोर मुद्रास्फीति मार्च में 3.3 प्रतिशत से अप्रैल में 3.2 प्रतिशत (व-द-व) तक कम हो गई, जो वर्तमान सीपीआई (2012 = 100) श्रृंखला में सबसे कम है। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, कपड़ों और जूते, परिवहन और संचार, मनोरंजन और मनोरंजन, और शिक्षा में मुद्रास्फीति के रूप में संतुलन ज्यादातर व्यापक था, जबकि व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव मुद्रास्फीति ने सुधार दर्ज किया (चार्ट III.26)। आवास, घरेलू वस्तुओं और सेवाओं तथा स्वास्थ्य की कीमतों में मुद्रास्फीति स्थिर रही।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति अप्रैल 2024 में शहरी मुद्रास्फीति (4.11 प्रतिशत) से अधिक अर्थात् 5.43

चार्ट III. 24 : सीपीआई मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियां और वाहक

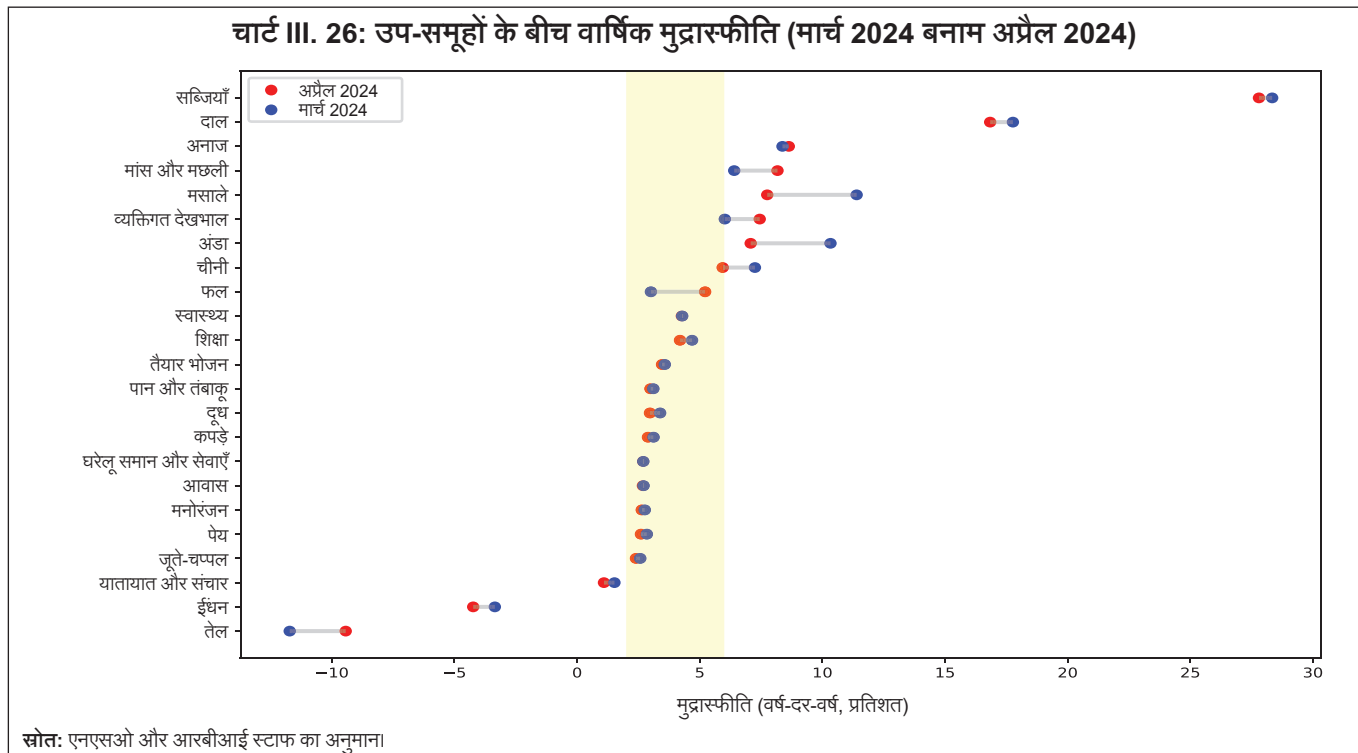


¹⁶ 13 मई 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

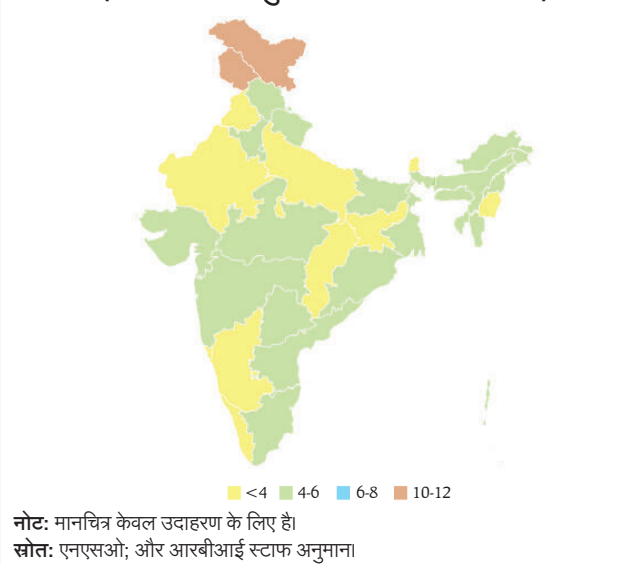


प्रतिशत रही। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम रही (चार्ट III.27)।

अब तक (13 तारीख तक) मई के लिए उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य आंकड़ें बताते हैं कि मुख्य रूप से, गेहूं द्वारा संचालित



चार्ट III.27: मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण अप्रैल 2024
(सीपीआई - संयुक्त, वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)



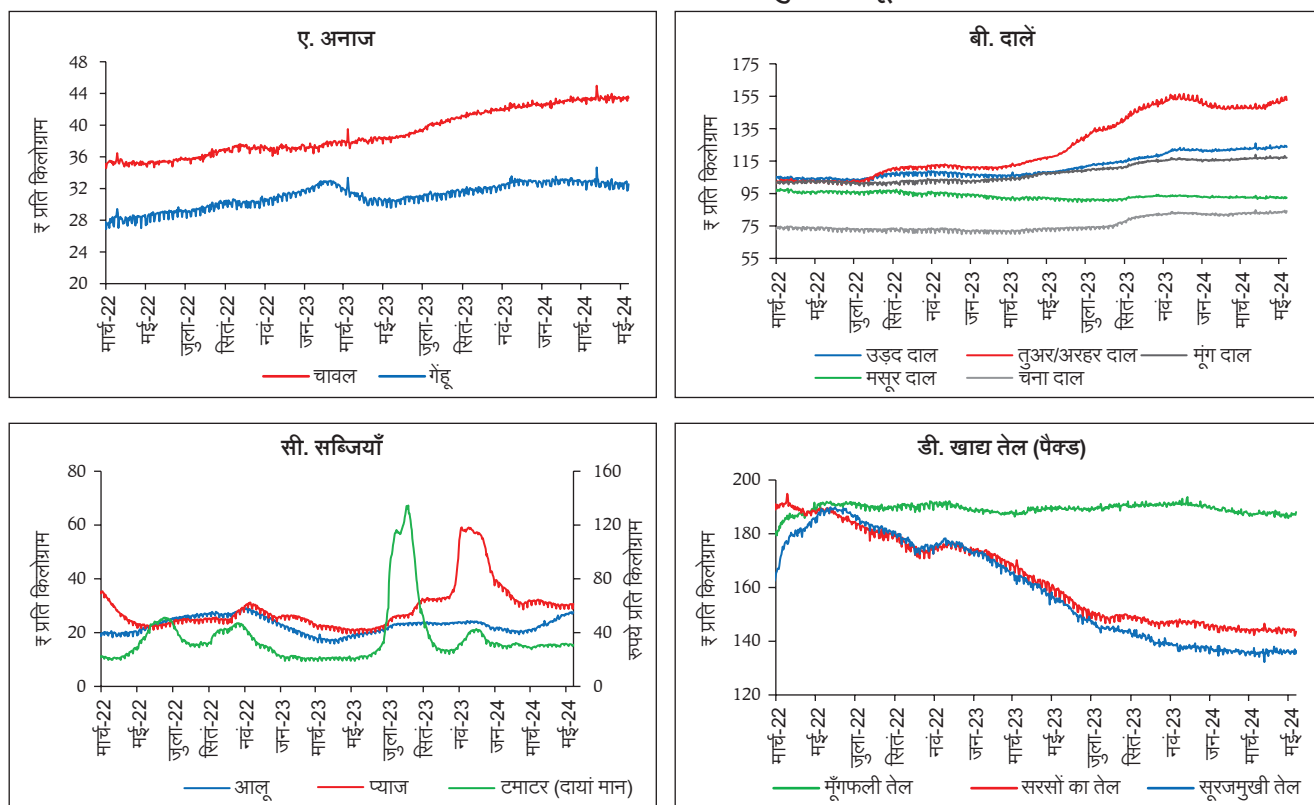
अनाज की कीमतों में गिरावट आई है। दालों की कीमतों में व्यापक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि खाद्य तेल की कीमतों में नरमी आई।

प्रमुख सब्जियों में मई में अब तक प्याज की कीमतों में और गिरावट आई है। आलू और टमाटर की कीमतों में वृद्धि जारी है (चार्ट III.28)।

प्याज के मामले में कीमत का दबाव कम होने पर सरकार ने तीन मई को प्याज निर्यात को 40 प्रतिशत निर्यात शुल्क और 550 डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) के साथ 'प्रतिबंधित' से 'मुक्त' श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया। दालों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को 31 अक्टूबर, 2024 तक बढ़ा दिया है। देसी चना (बंगाल चना) को मार्च 2025 तक आयात शुल्क से छूट दी गई है।

चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें मई में अब तक (13 तारीख तक) स्थिर बनी हुई हैं। मिट्टी तेल और एलपीजी की कीमतें भी अपरिवर्तित रहीं (सारणी III.2)।

चार्ट III.28: डीसीए आवश्यक वस्तुओं का मूल्य



स्रोत : उपभोक्ता मामलों विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		मई-23	अप्रै-24	मई-24 [^]	अप्रै-24	मई-24 [^]
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.91	100.91	0.0	0.0
डीज़ल	₹/लीटर	92.72	90.72	90.72	0.0	0.0
मिट्टी तेल (सब्सिडीकृत)	₹/लीटर	47.55	49.57	49.57	0.0	0.0
एलपीजी (गैर-सब्सिडीकृत)	₹/सिलेंडर	1113.25	813.25	813.25	0.0	0.0

[^]: 1-13 मई, 2024 की अवधि के लिए

नोट: केरोसिन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

अप्रैल 2024 के लिए पीएमआई इंगित करते हैं कि इनपुट लागत के साथ-साथ आउटपुट कीमतों ने विनिर्माण क्षेत्र में विस्तार में तेजी दर्ज की (चार्ट III.29)। सेवा क्षेत्र में, इनपुट और बिक्री मूल्य दोनों के लिए विस्तार की दर कम हो गई।

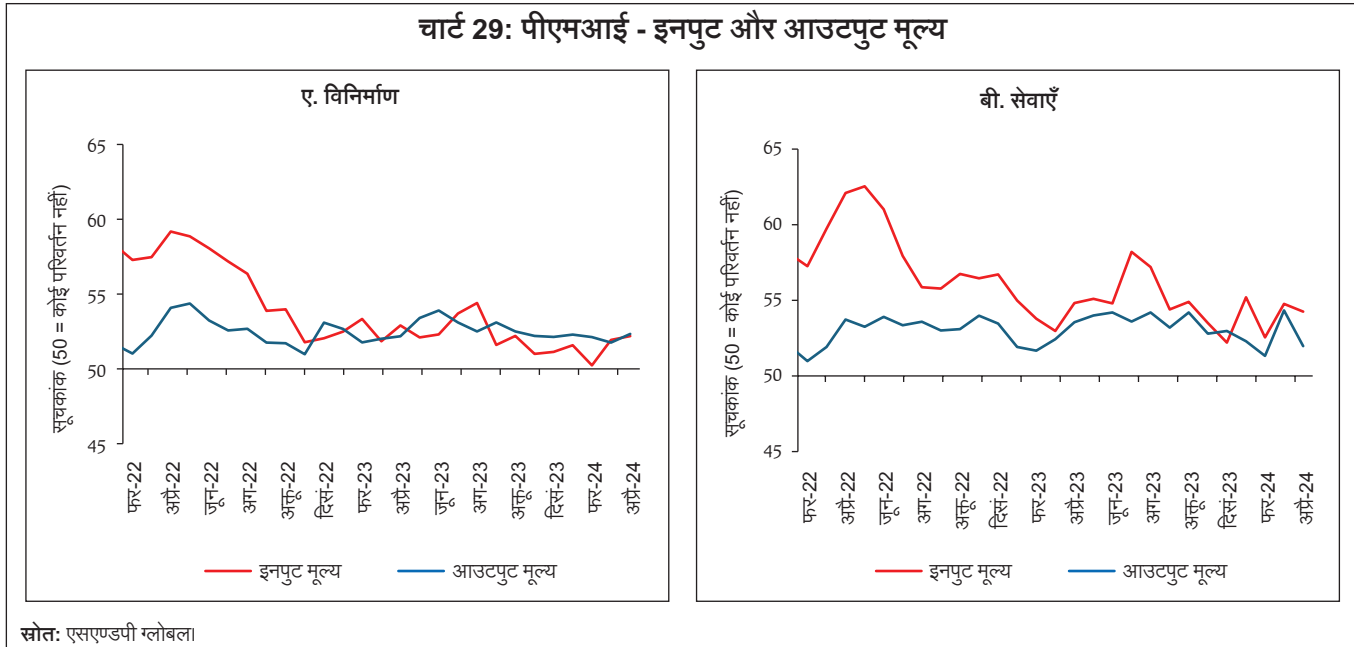
IV. वित्तीय स्थिति

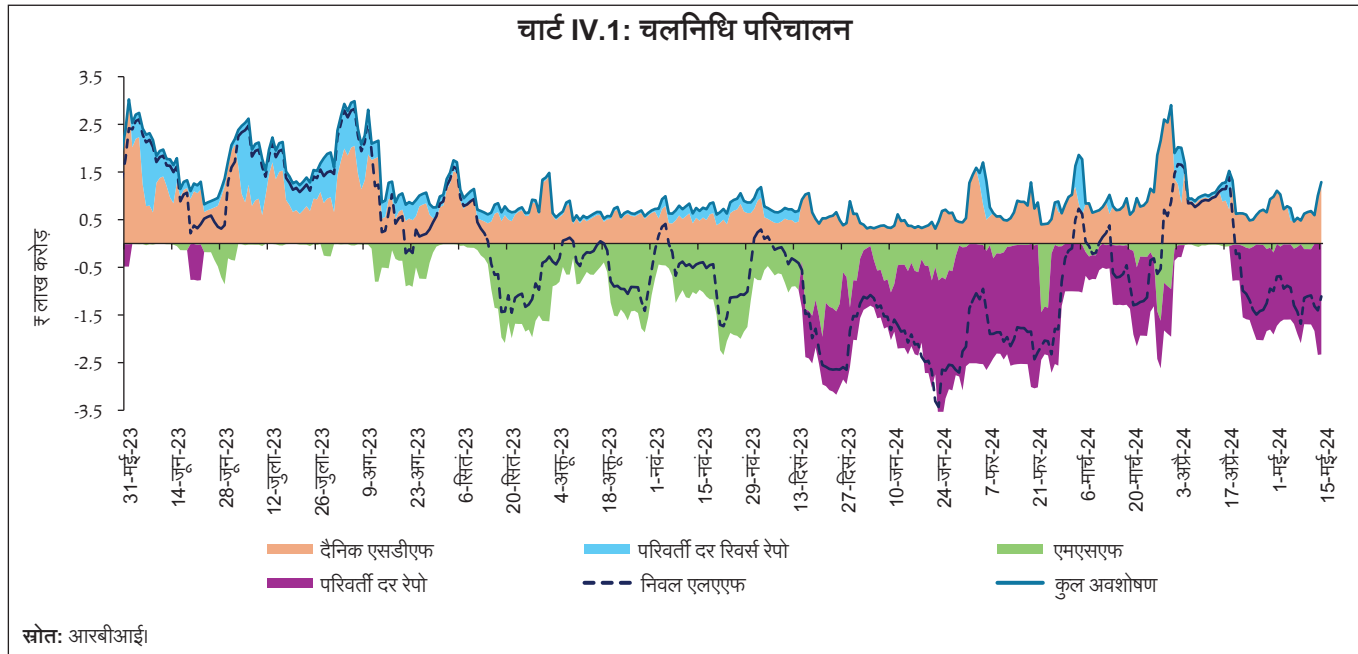
अग्रिम कर भुगतान और माल व सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह के कारण सरकारी नकद शेष राशि के निर्माण ने 20 अप्रैल, 2024 से चलनिधि प्रणाली पर दबाव डाला। जवाब में, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) [सीमांत स्थायी सुविधा

(एमएसएफ) सहित] के तहत औसत दैनिक निवल अन्तःक्षेपण 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान ₹ 0.80 लाख करोड़ रहा, जबकि 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2024 (चार्ट IV.1) के दौरान औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹ 0.20 लाख करोड़ था। 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान रिज़र्व बैंक ने दो मुख्य और नौ सटीक रूप से समायोजित परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि को अंतःक्षेपित किया, जो संचयी रूप से ₹6.3 लाख करोड़ की राशि है। निधि की मांग बहुत अधिक थी जैसा कि मुख्य और सटीक रूप से समायोजित वीआरआर नीलामी दोनों के लिए उच्च बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है।

अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से 15 मई, 2024 के दौरान ₹0.80 लाख करोड़ के औसत कुल अवशोषण में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधियों का नियोजन ₹0.74 लाख करोड़ था, जो 16 मार्च से 15 अप्रैल, 2024 के दौरान ₹1.18 लाख करोड़ से कम था। शेष 0.06 लाख करोड़ रुपये की राशि 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान किए गए परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) संचालन के माध्यम से अवशोषित की गई थी। इस अवधि के दौरान, रिज़र्व बैंक को ₹1.75 लाख करोड़ की कुल अधिसूचित राशि के मुकाबले ₹1.63 लाख करोड़ का संचयी कुल प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

चार्ट 29: पीएमआई - इनपुट और आउटपुट मूल्य

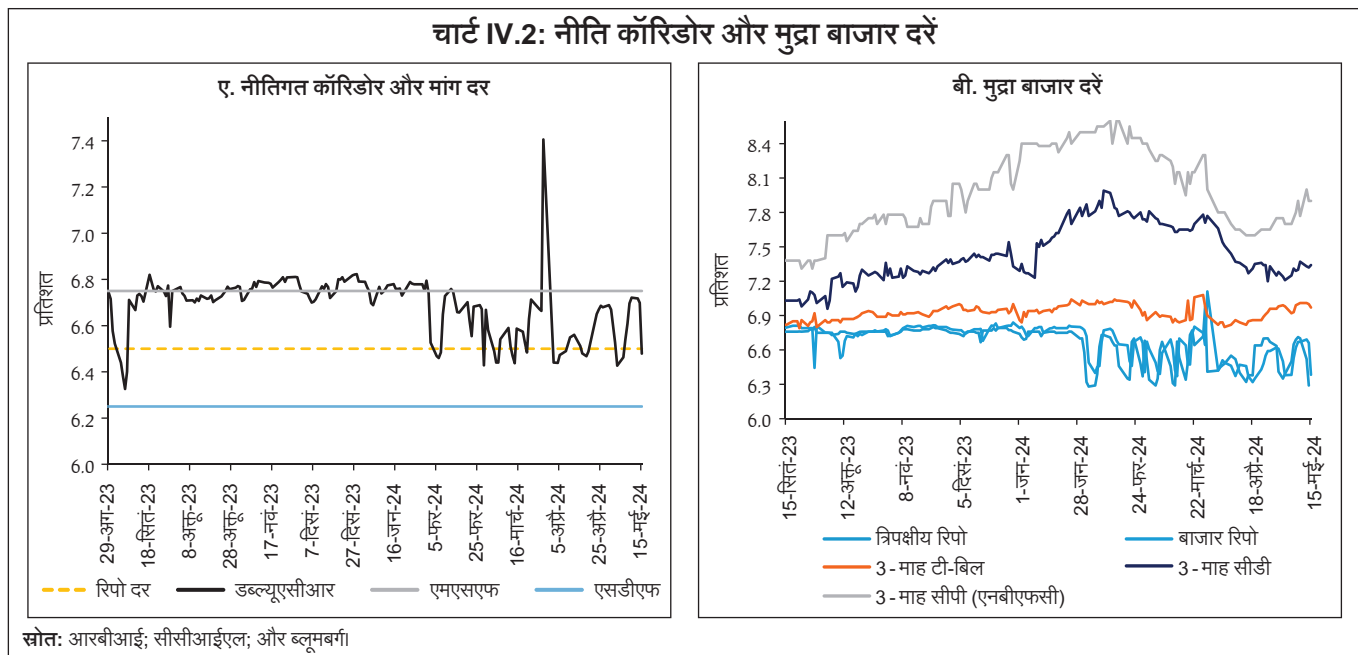


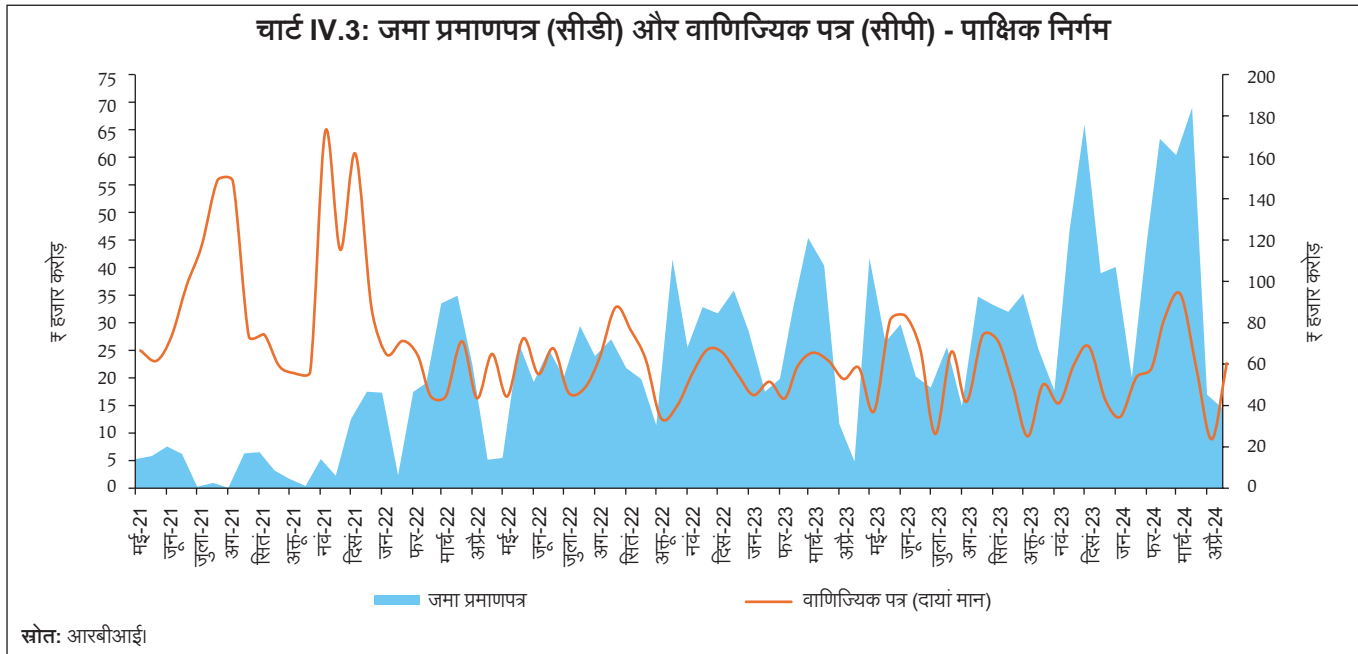


एक दिवसीय मुद्रा बाजार में, भारत औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर) एलएएफ कॉरिडोर के भीतर रहा और 16 मार्च-15 अप्रैल, 2024 के समान 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान औसतन 6.60 प्रतिशत रहा (चार्ट IV.2ए)। संपार्श्विक खंड में दरें - त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें - डब्ल्यूएसीआर के साथ मिलकर चलती हैं। औसत आधार पर, त्रिपक्षीय रेपो और बाजार रेपो दर ने 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान पॉलिसी रेपो दर

से ऊपर क्रमशः 5 बीपीएस और 2 बीपीएस का कारोबार किया (चार्ट IV.2बी)।

मियादी मुद्रा बाजार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए जमा प्रमाण पत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर प्रतिफल कम हो गया, हालांकि, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर मामूली रूप से कमी आई (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3-महीने के सीपी से 91-



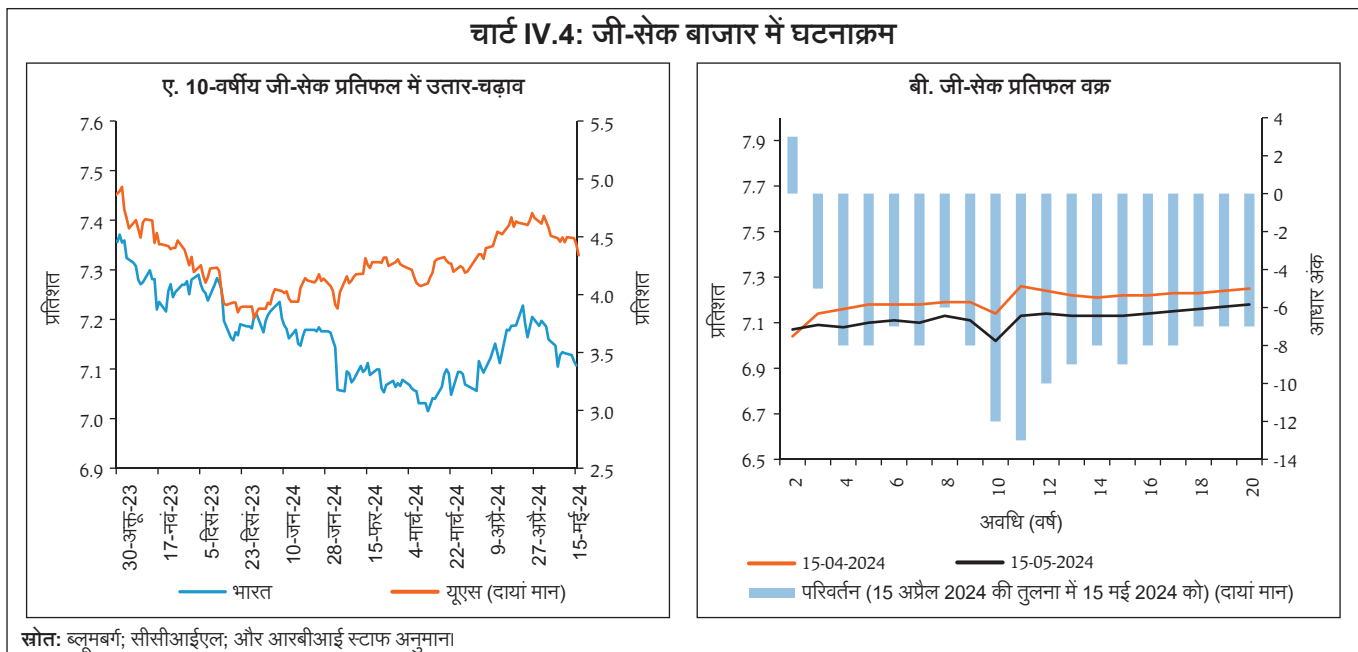


दिवसीय टी-बिल घटाकर) 16 अप्रैल से 15 मई, 2024 के दौरान घटकर 79 बीपीएस हो गया, जो मार्च 16 - अप्रैल 15, 2024 के दौरान 103 बीपीएस था।

प्राथमिक बाजार में, ऋण की निरंतर मांग के जवाब में 2024-25 (3 मई तक) के दौरान सीडी जारी करके जुटायी गई ₹0.46 लाख करोड़ की निधि पिछले वर्ष इसी अवधि में जुटाई गई ₹0.27 लाख करोड़ से अधिक थी (चार्ट IV.3)। दूसरी ओर, 2024-25

(30 अप्रैल तक) के दौरान ₹0.84 लाख करोड़ की सीपी जारी की गई, जो पिछले वर्ष, इसी अवधि में जारी की गई ₹1.11 लाख करोड़ की सीपी से कम थी।

10-वर्षीय भारतीय बेंचमार्क सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर प्रतिफल 15 अप्रैल के 7.18 प्रतिशत से घटकर 15 मई, 2024 को 7.08 प्रतिशत पर बंद हुआ (चार्ट IV.4ए)। भारतीय सॉवरेन बॉन्ड इस अवधि के दौरान सरकारी उधारी में कमी,



वैश्विक बॉन्ड सूचकांक समावेशन के कारण बढ़ती मांग और स्थिर रुपये के कारण, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता से समुत्थानशील और अछूते रहे। सावधि संरचना में वक्र के मध्य से अंतिम सिरे तक पैदावार में अपेक्षाकृत तेज कमी के साथ उपज वक्र नीचे की ओर स्थानांतरित हो गया (चार्ट IV.4बी)। 3 मई, 2024 को भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए अपनी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने 9 मई, 2024 को आयोजित नीलामी में ₹0.53 लाख करोड़ (₹0.40 लाख करोड़ की अधिसूचित राशि का 1.33 गुना) की प्राप्त बोलियों के सामने कुल ₹0.10 लाख करोड़ के जी-सेक खरीदने के प्रस्ताव स्वीकार किए।

कॉर्पोरेट बॉन्ड प्रतिफल और जोखिम प्रीमियम ने 16 अप्रैल से 14 मई, 2024 के दौरान विविध परिपक्वता अवधि प्रोफाइल और दर निर्धारण स्पेक्ट्रम में मिश्रित उतार-चढ़ाव का प्रदर्शन किया (सारणी IV.1)। कुल मिलाकर, 2023-24 के दौरान ₹8.6 लाख करोड़ के कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान जारी ₹7.5 लाख करोड़ से अधिक थे। दीर्घावधि घरेलू निवेशकों और विदेशी कंपनियों की बढ़ती मांग से कंपनियों और बैंकों द्वारा ऋण बाजार में सस्ती दरों पर बड़ी राशि जुटाने में मदद मिली है।

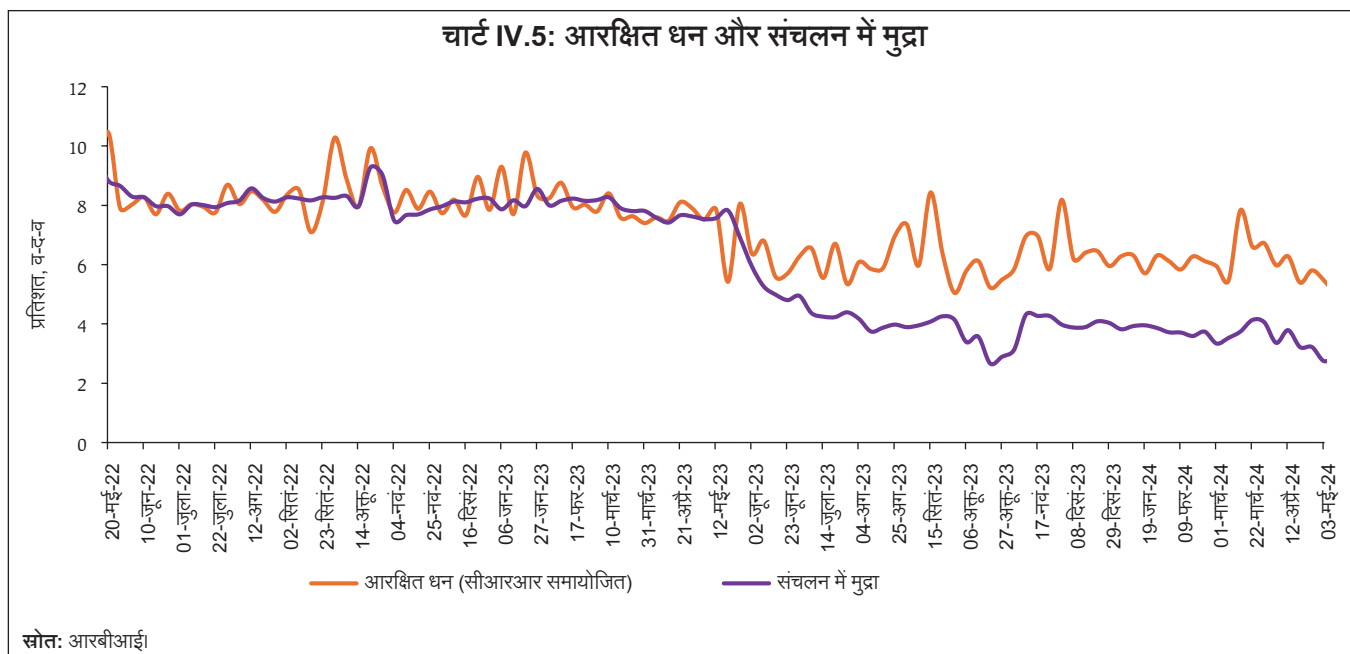
सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और फैलाव

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)			स्प्रेड (बीपीएस) (संबंधित जोखिम-मुक्त दर से अधिक)		
	16 मार्च, 2024 - 15 अप्रै, 2024	16 अप्रै, 2024 - 14 मई, 2024	घट-बढ़	16 मार्च, 2024 - 15 अप्रै, 2024	16 अप्रै, 2024 - 14 मई, 2024	घट-बढ़
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कारपोरेट बांड						
(i) एएए (1 वर्ष)	7.90	7.83	-7	74	66	-8
(ii) एएए (3 वर्ष)	7.88	8.01	13	67	72	5
(iii) एएए (5 वर्ष)	7.75	7.92	17	52	62	10
(iv) एए (3 वर्ष)	8.47	8.61	14	126	132	6
(v) बीबीबी-(3 वर्ष)	12.08	12.19	11	488	490	2

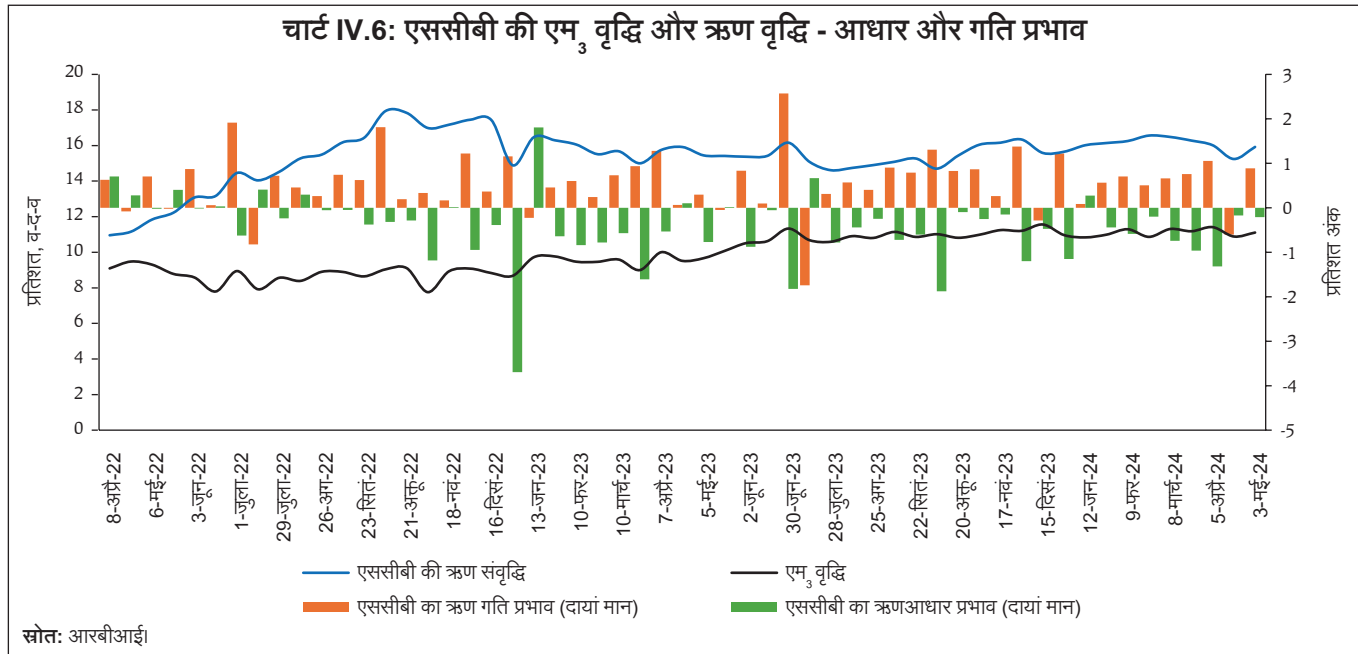
नोट: यील्ड और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधियों के औसत के रूप में की जाती है।
स्रोत: फीम्डा; और ब्लूमबर्ग।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) ने 10 मई, 2024 को 5.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि (एक वर्ष पहले 7.9 प्रतिशत) दर्ज की [चार्ट IV.5]। आरएम के सबसे बड़े घटक, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) की वृद्धि एक साल पहले के 7.6 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई, जो ₹2000 बैंकनोटों

चार्ट IV.5: आरक्षित धन और संचलन में मुद्रा



स्रोत: आरबीआई।

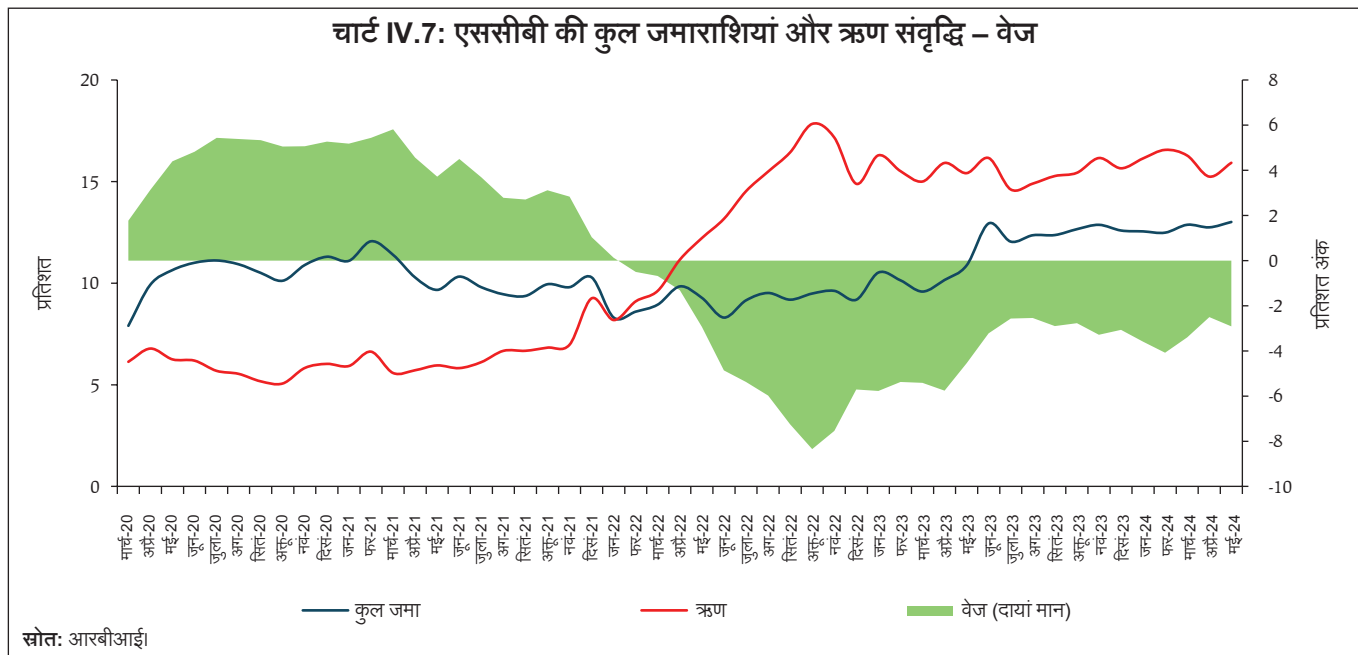


की निकासी को दर्शाती है¹⁷ – उनमें से 97.8 प्रतिशत बैंकनोट ज्यादातर जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गए हैं (19 मई, 2024 तक)।

मुद्रा आपूर्ति (एम₃) 3 मई, 2024 को 11.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) से बढ़ी (एक वर्ष पहले 9.7 प्रतिशत)।¹⁸ बैंकों के साथ एम₃ का सबसे बड़ा घटक अर्थात्, सकल जमा राशि 12.4 प्रतिशत (एक

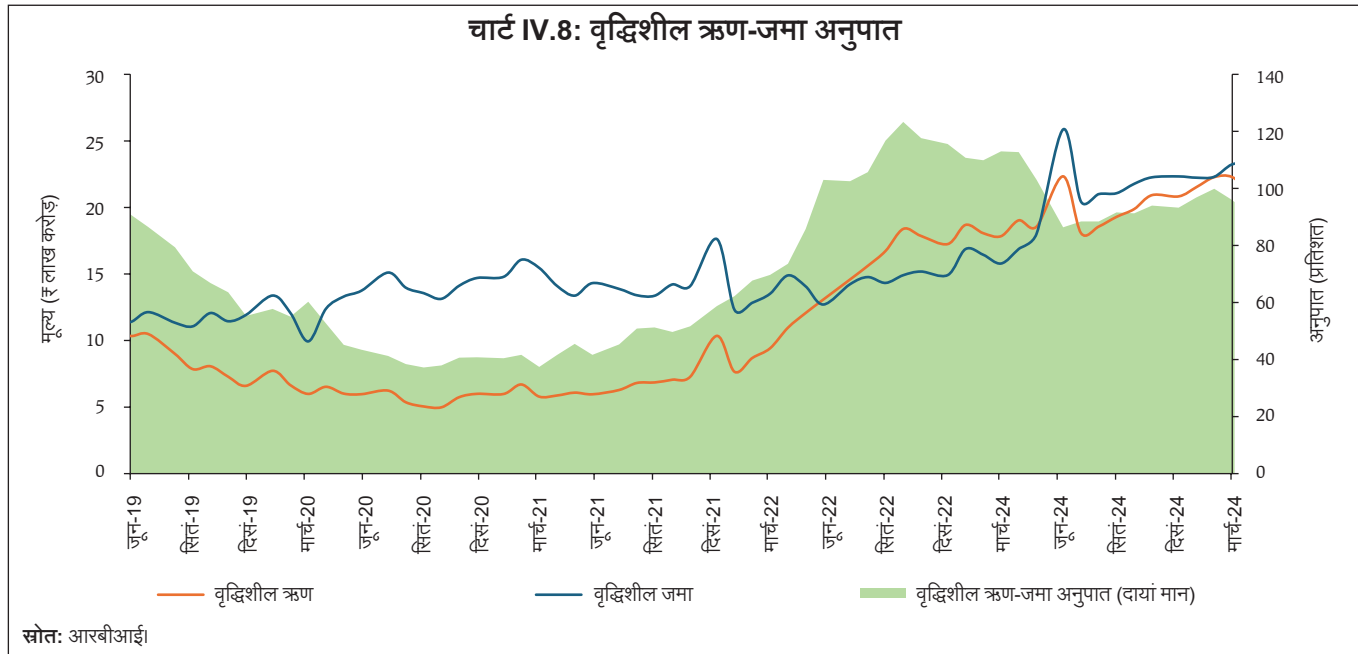
वर्ष पहले 10.0 प्रतिशत) तक बढ़ गई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 3 मई, 2024 को 15.9 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 15.4 प्रतिशत) [चार्ट IV.6]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलयन के प्रभाव को छोड़कर) अप्रैल 2024 में दोहरे अंकों में रही (चार्ट IV.7)।



¹⁷ 19 मई 2023 को की गई घोषणा।

¹⁸ किसी गैर-बैंक के बैंक में विलयन के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।



19 अप्रैल, 2024 तक प्रणाली स्तरीय वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 90.7 प्रतिशत था (चार्ट IV.8)। सीआरआर और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सांविधिक आवश्यकताओं के साथ, लगभग 77 प्रतिशत जमाराशि 19 अप्रैल, 2024 तक ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध थी।

मई 2022 से पॉलिसी रेपो दर में 250 बीपीएस परिवर्तन की प्रतिक्रिया में, बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) में समान परिमाण की वृद्धि हुई। मई 2022 से अप्रैल 2024 के दौरान 1-वर्ष की औसत सीमांत लागत निधि-आधारित उधार

दर (एमसीएलआर) में 166 बीपीएस की वृद्धि हुई। नतीजतन, मई 2022 से मार्च 2024 के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 186 बीपीएस और 113 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमाराशियों के मामले में, उसी अवधि के दौरान, नई और बकाया जमाराशियों पर भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 259 और 185 आधार अंकों की वृद्धि हुई (सारणी IV.2)।

बैंक समूहों में संचरण इंगित करता है कि मई 2022 से मार्च 2024 के दौरान बकाया ऋणों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में जमा और उधार दरों में वृद्धि अधिक

सारणी IV.2: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(बीपीएस में अंतर)

अवधि	रेपो दर (बीपीएस)	सावधि जमा दरें		उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर - नई जमा	डब्ल्यूएडीटीडीआर - बकाया जमा	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएलआर - ताजा रुपया ऋण	डब्ल्यूएलआर - बकाया रुपया ऋण
सहजता अवधि फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्त अवधि मई 2022 से मार्च 2024	250	259	185	250*	166*	186	113

नोट: ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

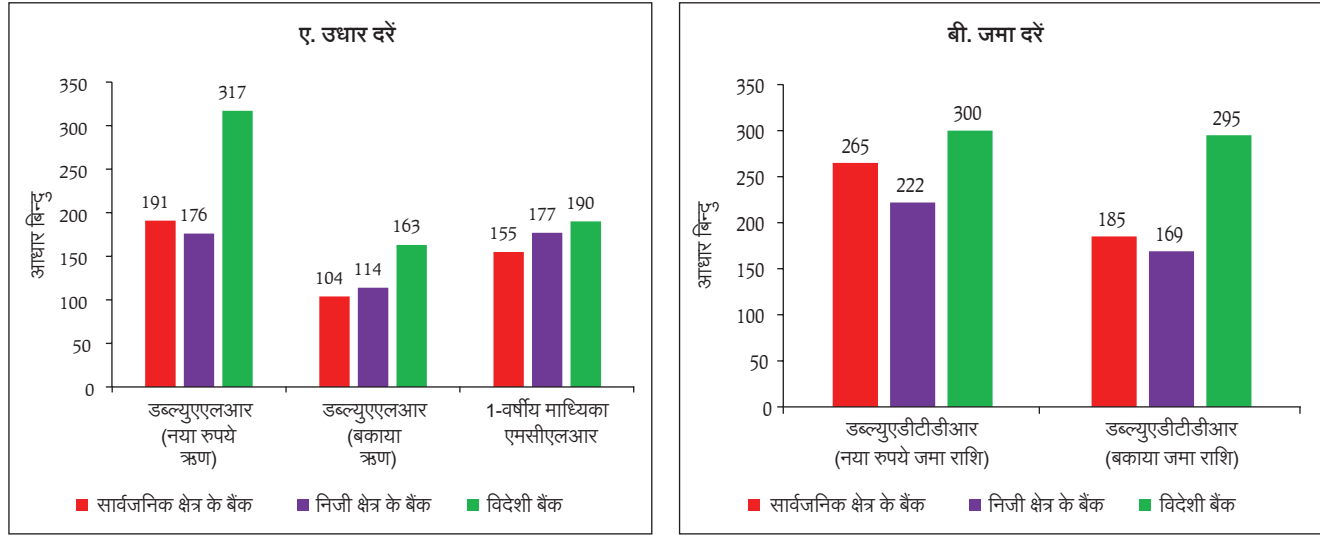
*: ईबीएलआर और एमसीएलआर पर डेटा अप्रैल 2024 से संबंधित है।

डब्ल्यूएलआर: भारित औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारित औसत घरेलू मीयादी जमा दर;

एमसीएलआर: फंड आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क आधारित उधार दर।

स्रोत: आरबीआई।

चार्ट IV.9: बैंक-समूहों में संचरण (मई 2022 से मार्च 2024)



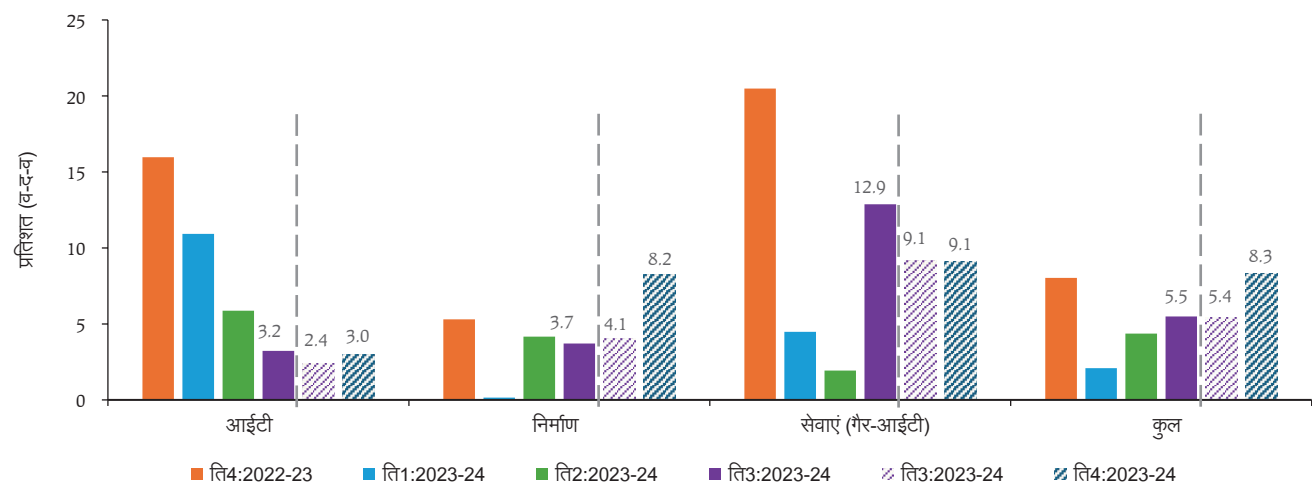
स्रोत: आरबीआई।

थी (चार्ट IV.9)। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की ऋण दरें निजी बैंकों की तुलना में कम रहीं, जबकि उनकी जमा दरें अधिक थीं।

2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान, सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) कंपनियों ने टॉप-लाइन संवृद्धि में मामूली तेजी का प्रदर्शन किया। सूचीबद्ध एनजीएनएफ कंपनियों की बिक्री वृद्धि में सुधार होकर पिछली तिमाही से 2023-24 की

चौथी तिमाही के दौरान 8.3 प्रतिशत (व-द-व) हुई, जो मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित है।¹⁹ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का कार्यनिष्पादन चौथी तिमाही के दौरान मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में कमजोरी और विवेकाधीन व्यय के कारण मंद रहा (चार्ट IV.10)। राजस्व के अनुरूप, परिचालन लाभ मार्जिन चौथी तिमाही (सारणी IV.3)

चार्ट IV.10: बिक्री संवृद्धि



नोट: 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए परिणाम 596 सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों पर आधारित हैं। छायांकित पट्टी ने ति3:2023-24 और ति4:2023-24 में आम कंपनियों की संवृद्धि का संकेत दिया।

स्रोत: कैपिटलइन; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

¹⁹ सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 60 प्रतिशत बनानेवाली 596 कंपनियों के नमूने पर आधारित है।

सारणी IV.3: लाभ मार्जिन

क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	परिचालन लाभ मार्जिन (प्रतिशत)			निवल लाभ मार्जिन (प्रतिशत)		
		ति4: 2022-23	ति3: 2023-24	ति4: 2023-24	ति4: 2022-23	ति3: 2023-24	ति4: 2023-24
आईटी	59	23.1	24.2	23.5	17.7	18.9	20.0
विनिर्माण	369	14.3	15.2	14.9	11.8	10.8	9.1
सेवाएँ (गैर-आईटी)	119	28.7	29.0	29.8	7.8	8.6	10.0
कुल	596	16.8	17.9	17.4	12.6	11.8	11.0

स्रोत: कैपिटलाइन; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में कम हो गया। कर्मचारियों की संख्या में कमी के बावजूद आईटी कंपनियों के कर्मचारियों की लागत में मामूली वृद्धि हुई और शीर्ष पांच आईटी कंपनियों ने चौथी तिमाही के दौरान अपने वैश्विक कर्मचारियों की संख्या में 11,432 की कमी की।

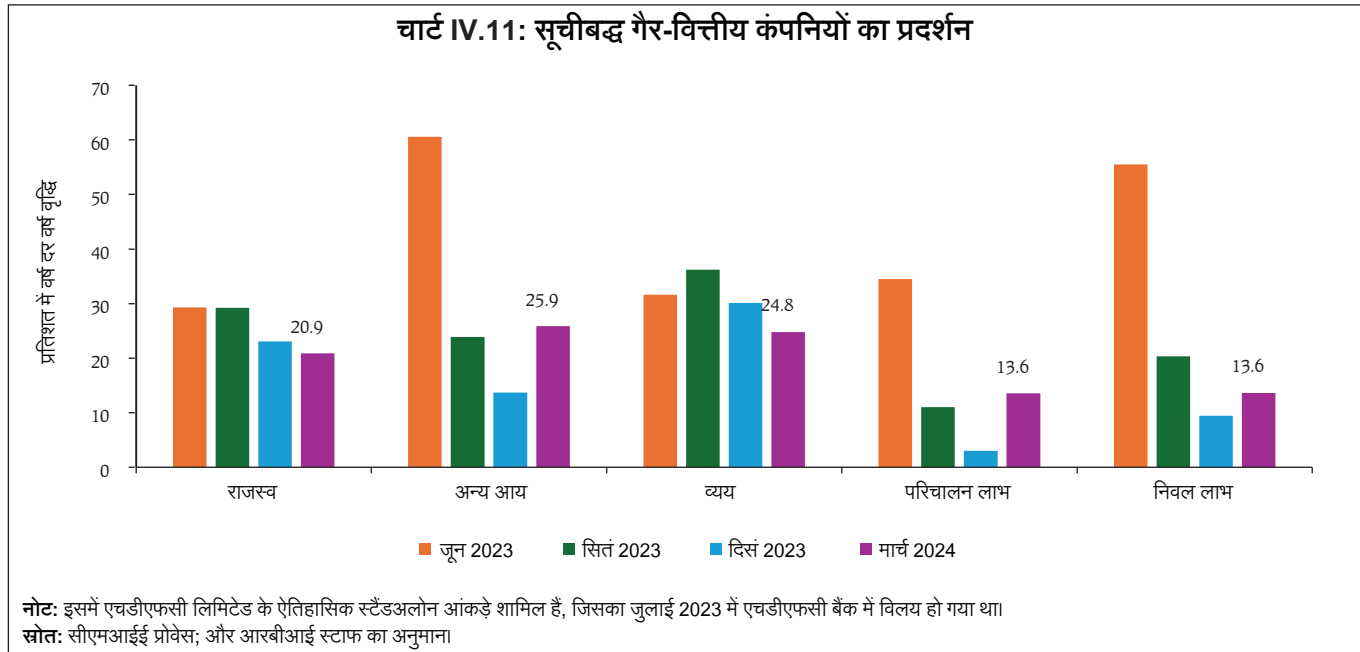
विनिर्माण कंपनियों ने 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान बिक्री में 8.2 प्रतिशत (तीसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की। प्रारंभिक रिपोर्टिंग करनेवाले गैर-आईटी सेवा कंपनियों की बिक्री वृद्धि 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान 9.1 प्रतिशत रही (चार्ट IV.10)।

सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों²⁰ के मामले में, राजस्व, जिसमें मुख्य रूप से बैंकों के मामले में ब्याज आय

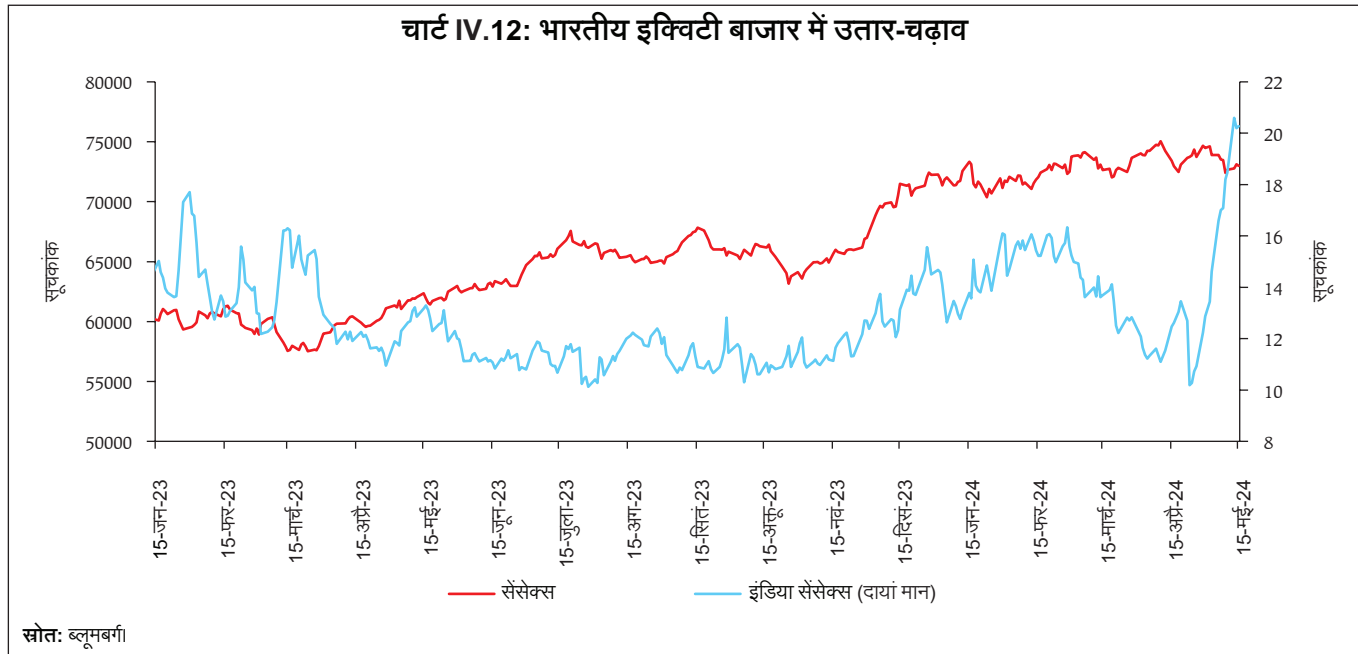
शामिल होती है, ने मजबूत दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की (चार्ट IV.11)। अन्य आय, जिसमें फीस, कमीशन, लाभ और निवेश से हानि शामिल है, ने भी बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की है, जो एक निजी क्षेत्र के बैंक द्वारा किए गए विशिष्ट बिक्री लेनदेन से लाभ के प्रभाव को दर्शाती है। ब्याज व्यय में वृद्धि के बीच व्यय में वृद्धि ने राजस्व वृद्धि को पीछे छोड़ दिया; हालाँकि, परिचालन लाभ में वृद्धि ने क्रमिक सुधार प्रदर्शित किया। इसके अलावा, तिमाही के दौरान निवल लाभ वृद्धि दोहरे अंक में रही।

सकारात्मक वैश्विक संकेतों, मजबूत घरेलू समष्टि आर्थिक डेटा रिलीज और 2023-24 की चौथी तिमाही के समुत्थानशील कॉर्पोरेट आय परिणामों को देखते हुए, घरेलू इक्विटी बाजार

चार्ट IV.11: सूचीबद्ध गैर-वित्तीय कंपनियों का प्रदर्शन



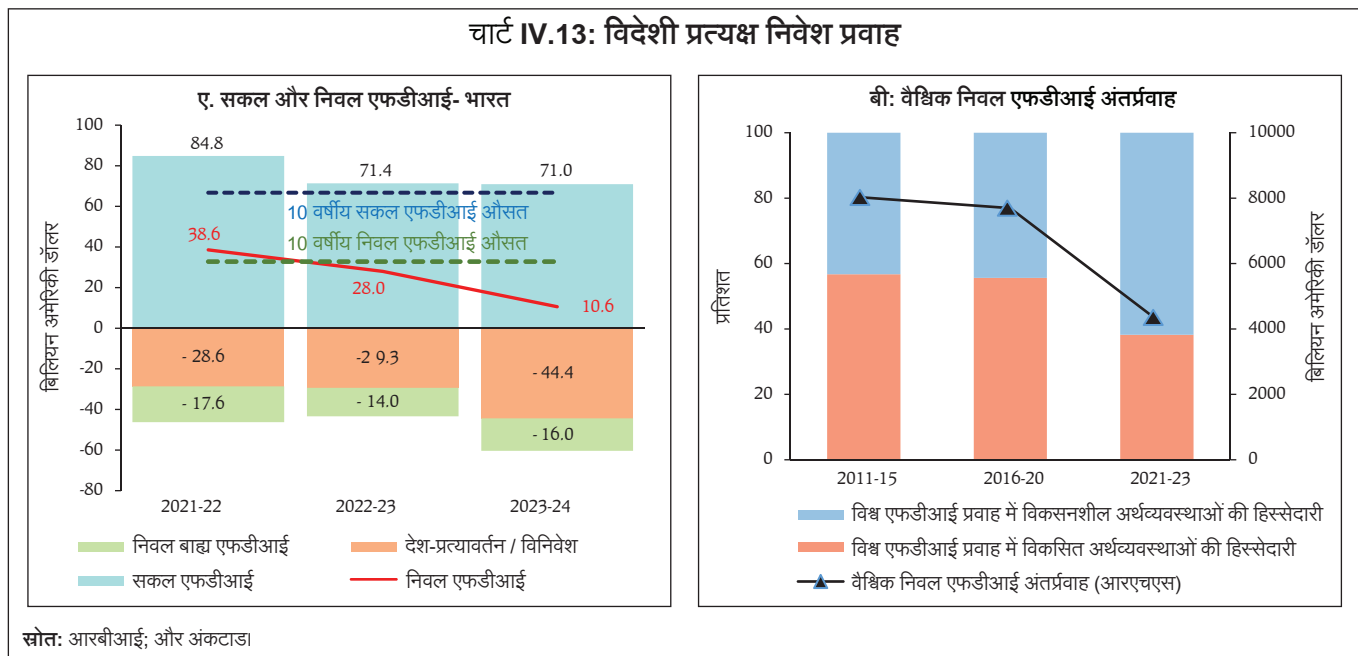
²⁰ सूचीबद्ध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के कुल बाजार पूंजीकरण का लगभग 74 प्रतिशत बनाने वाली 155 कंपनियों के नमूने पर आधारित है।



ने अप्रैल 2024 के चौथे सप्ताह में संवृद्धि दर्ज की। इसके बाद एफपीआई की बिकवाली के बीच, सकारात्मक वैश्विक संकेतों और घरेलू सीपीआई मुद्रास्फीति में और कमी आने पर पुनर्प्राप्ति से पहले, इक्विटी की कीमतों में कुछ सुधार दर्ज किया गया। बेंचमार्क बीएसई सेंसेक्स 15 मई, 2024 को 72,987 पर बंद हुआ, पिछले एक महीने में भारत वीआईएक्स²¹ द्वारा किए गए मापन के अनुसार इक्विटी बाजार में अस्थिरता में तेज उतार-चढ़ाव दर्ज किया

गया(चार्ट IV.12)। अप्रैल 2024 में, एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा फॉलो-ऑन-पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के माध्यम से ₹18,000 करोड़ का एक बड़ा जुटाव भी किया गया था।

2023-24 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लगभग 71.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर (एक साल पहले 71.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर स्थिर रहा (चार्ट IV.13ए)।



²¹ इंडिया वीआईएक्स निफ्टी सूचकांक विकल्प कीमतों पर आधारित एक अस्थिरता सूचकांक है।

60 प्रतिशत से अधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह विनिर्माण, बिजली और अन्य ऊर्जा, कंप्यूटर सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और खुदरा एवं थोक व्यापार की ओर निर्देशित था। सिंगापुर, मॉरीशस, अमेरिका, नीदरलैंड, जापान और संयुक्त अरब अमीरात ने इस प्रवाह में 80 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। 2023-24 के दौरान निवल एफडीआई एक साल पहले के 28.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो मुख्य रूप से उच्च प्रत्यावर्तन को दर्शाता है।

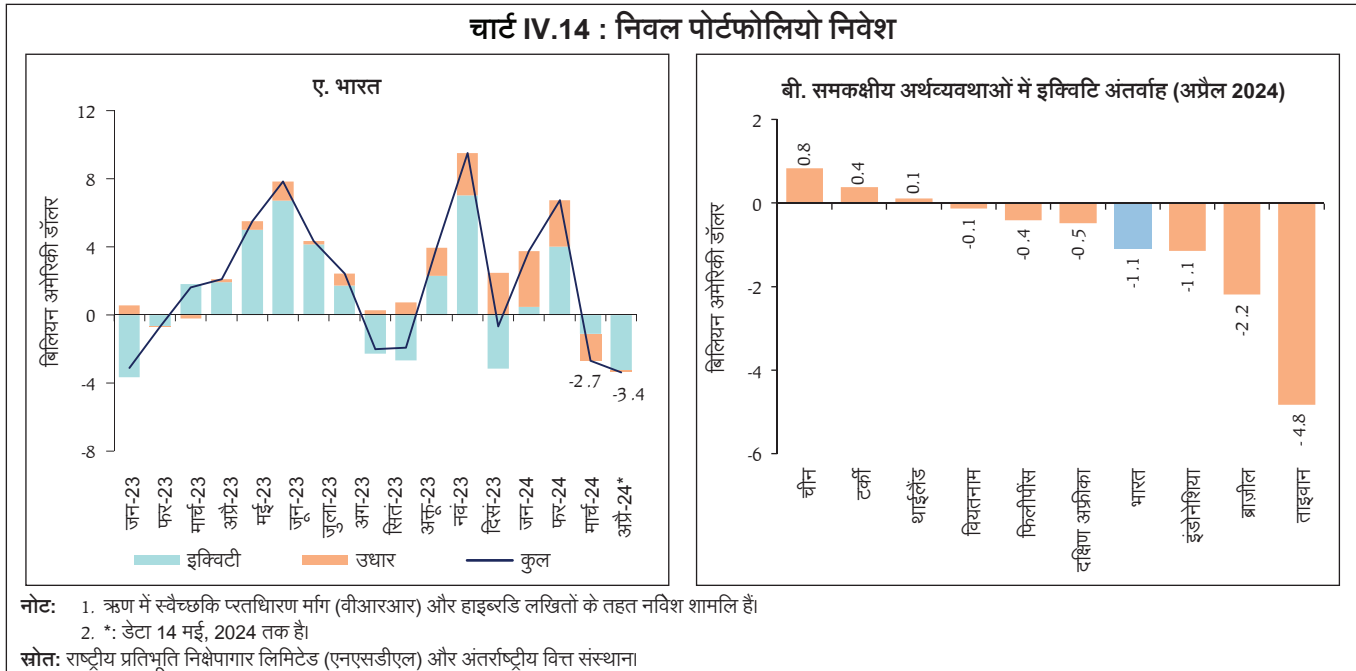
हाल के वर्षों में, वैश्विक एफडीआई प्रवाह उच्चतर उधारी लागत, गहराते भू-विखंडन और बढ़ते संरक्षणवाद से प्रभावित हुआ है। बहरहाल, एफडीआई इंटेलेजेंस²² के अनुसार, भारत 2024 में उच्च एफडीआई गति का अनुभव करने वाली शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, वैश्विक निवेश पैटर्न में एक संरचनात्मक बदलाव आया है, जिससे विकसित अर्थव्यवस्थाओं से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरित एफडीआई प्रवाह, वैश्विक पूंजी के स्रोत के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उभरा है (चार्ट IV.13बी)। 2023 में, जी20-ईएम से होने वाले वैश्विक एफडीआई पूंजी व्यय का हिस्सा 2003 के 8.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर

14.9 प्रतिशत हो गया।²³ 2023 के दौरान, भारतीय कंपनियों ने विदेशों में 550 से अधिक ग्रीनफील्ड एफडीआई परियोजनाओं की घोषणा की, जो पहले के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है।

अप्रैल 2024 में, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और अमेरिकी बांड पैदावार में बढ़ोतरी पर अनिश्चित वैश्विक संकेतों के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) दो महीने के बाद भारतीय पूंजी बाजार में निवल विक्रेता बन गए। अप्रैल 2024 में निवल एफपीआई बहिर्प्रवाह 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें इक्विटी और ऋण दोनों क्षेत्रों में बहिर्वाह दर्ज किया गया था (चार्ट IV.14ए)। तुलनीय उभरते बाजार प्रतिस्पर्धियों के अनुरूप, भारतीय इक्विटी ने अप्रैल 2024 में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया (चार्ट IV.14बी)। क्षेत्र-वार, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और वित्तीय सेवाओं ने सबसे अधिक बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि दूरसंचार और बिजली ने अप्रैल 2024 के दौरान सबसे बड़ा इक्विटी प्रवाह खींच लाया। मई 2024 में निवल एफपीआई बहिर्वाह (14 तारीख तक) 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

2023-24 के दौरान, सभी खातों अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर (बी)] खाता, अनिवासी (बाह्य) रुपया

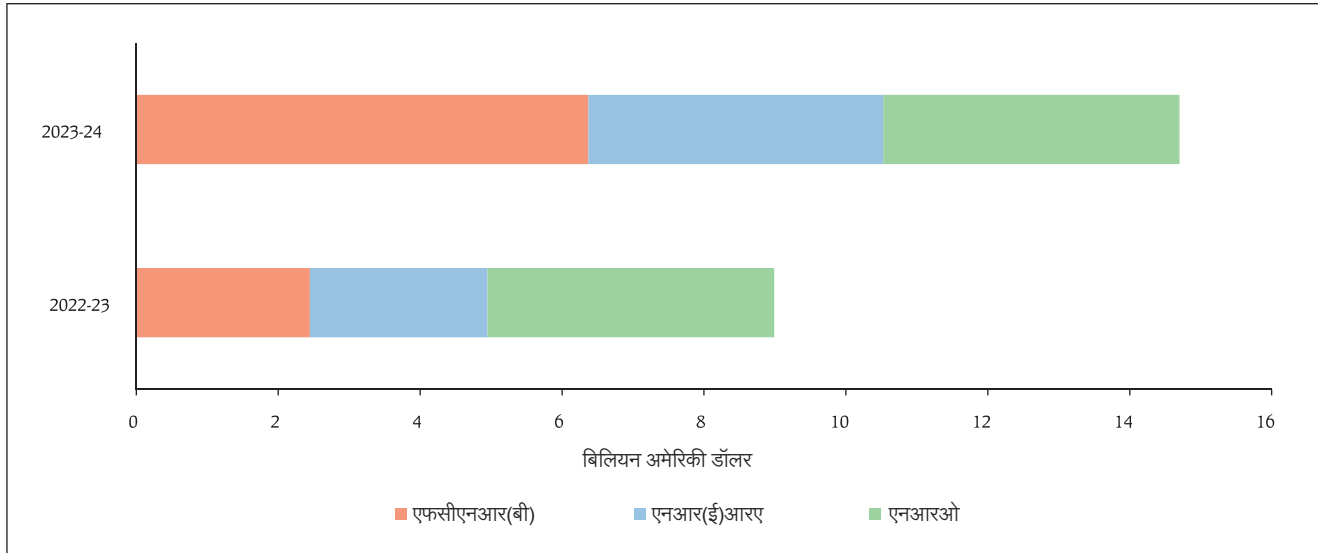
चार्ट IV.14 : निवल पोर्टफोलियो निवेश



²² फाइनेंशियल टाइम्स का एक विशेषज्ञ प्रभाग जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित सेवाओं की व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

²³ एफडीआई इंटेलेजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार।

चार्ट IV.15: अनिवासी जमा खातों के अंतर्गत प्रवाह



स्रोत: आरबीआई

खाता [एनआर(ई)आरए] और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खाते में निवल अभिवृद्धि के साथ अनिवासी जमा राशियों में 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च अभिवृद्धि दर्ज की गई, जो एक साल पहले 9.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी (चार्ट IV.15)।

2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण की राशि 13.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो पिछली तिमाही की तुलना में 87 प्रतिशत अधिक

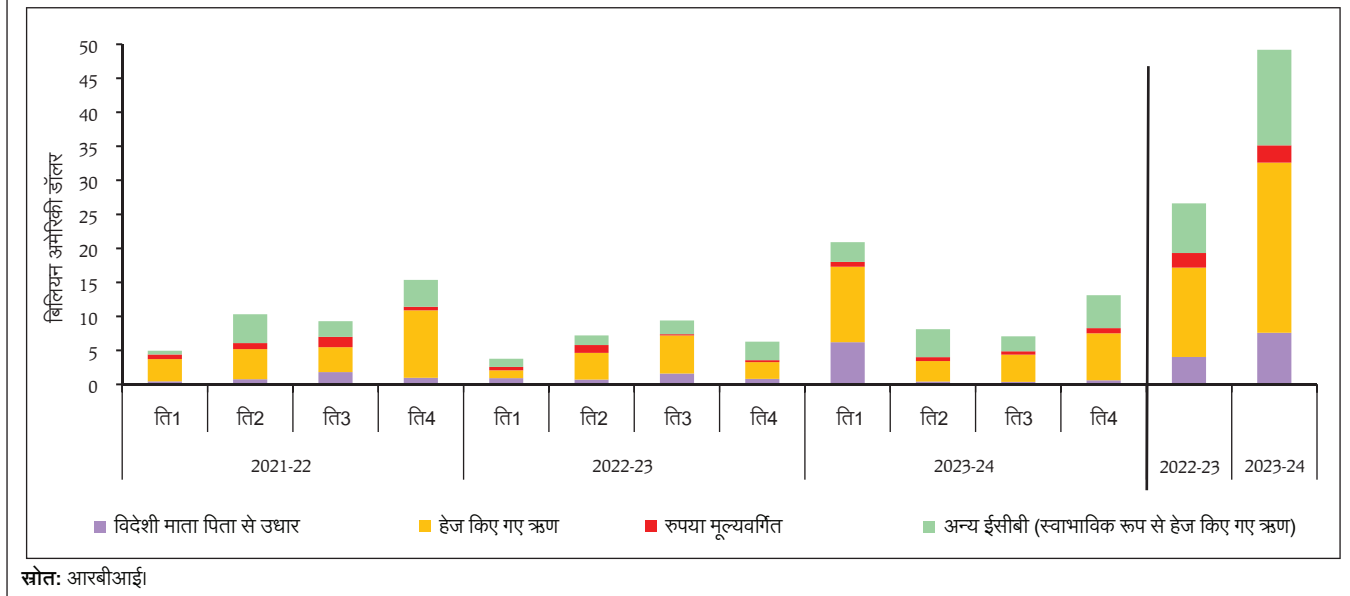
है। ईसीबी अंतर्वाह बहिर्प्रवाह से अधिक होने के कारण, दो तिमाहियों के बाद निवल अंतर्वाह फिर से शुरू हो गया। संचयी रूप से 2023-24 के दौरान, ईसीबी के तहत पंजीकरण (49.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर), संवितरण (38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के साथ-साथ निवल प्रवाह (9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) 2022-23 में दर्ज किए गए स्तरों से काफी अधिक थे (चार्ट IV.16)।

चार्ट IV.16: ईसीबी – पंजीकरण और प्रवाह



स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.17: ईसीबी समझौते - हेजिंग स्थिति



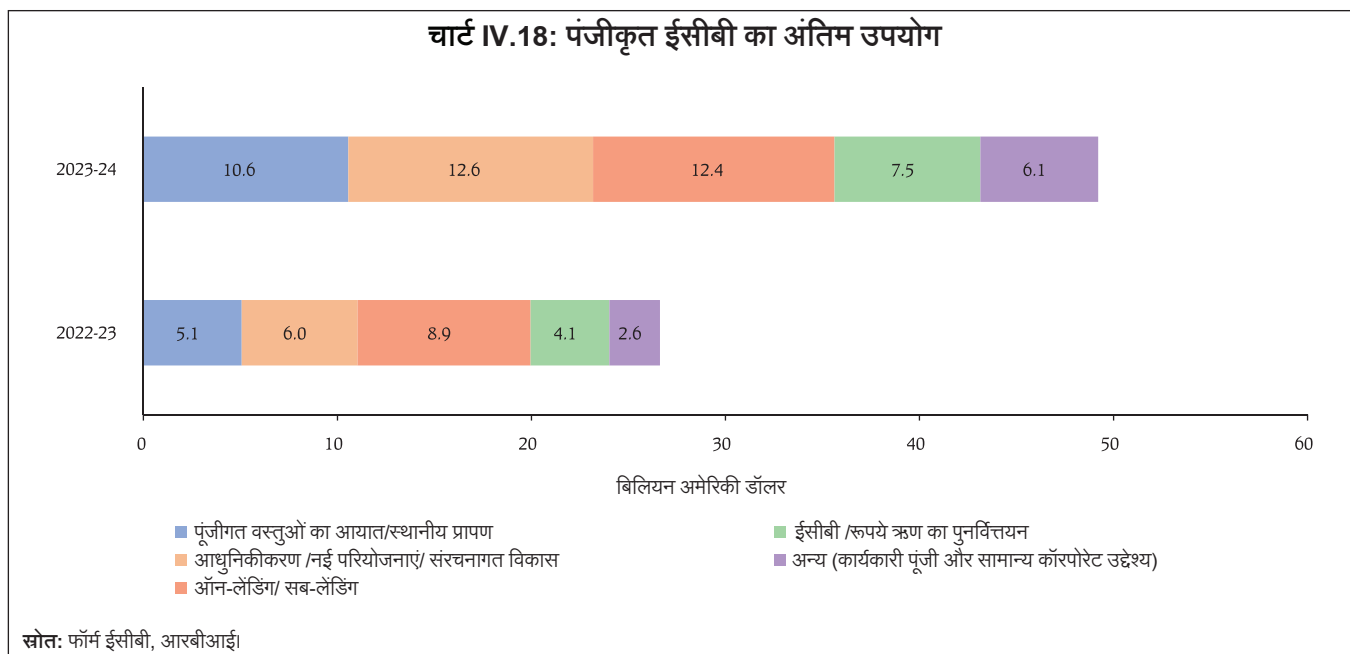
2023-24 के दौरान जुटाए गए 70 प्रतिशत से अधिक ईसीबी सुस्पष्ट हेजिंग, रुपये में मूल्यवर्गीकृत ऋण या विदेशी माता-पिता से ऋण के रूप में प्रभावी ढंग से हेज किया गया था, जिससे बाहरी झटकों का प्रभाव सीमित हो गया (चार्ट IV.17)।

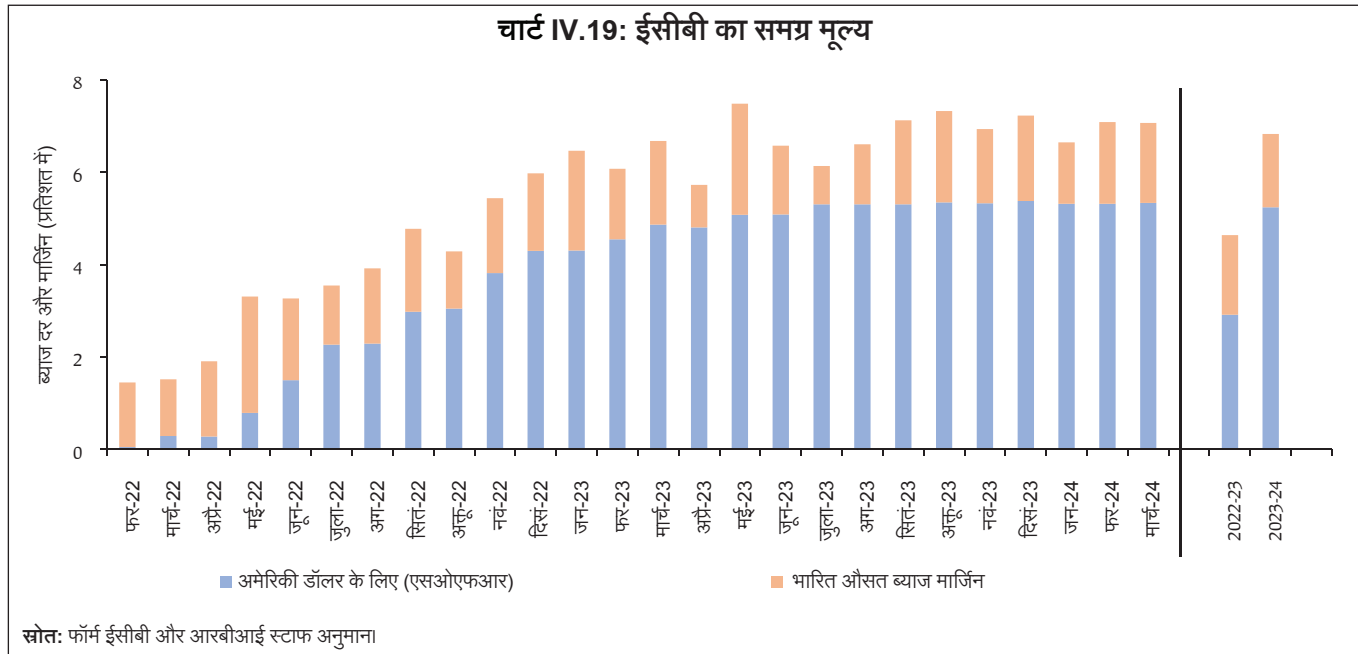
भले ही, 2023-24 के दौरान ईसीबी का अंतिम उपयोग विस्तृत व्यापक था, पूंजीगत वस्तुओं के स्रोत, आधुनिकीकरण परियोजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जुटाए गए

धन में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई। यह अर्थव्यवस्था में समग्र क्षमता वृद्धि के लिए शुभ संकेत है और निजी क्षेत्र की निवेश मांग को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट IV.18)।

2023-24 के दौरान ईसीबी ऋणों की कुल लागत में हुई वृद्धि मुख्य रूप से बड़ी हुई वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरों (जैसे कि सुरक्षित रात्रिकालीन वित्तपोषण दर (एसओएफआर)) के कारण थी जो उच्च वैश्विक ब्याज दरों को दर्शाती है। कुल लागत का

चार्ट IV.18: पूंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग

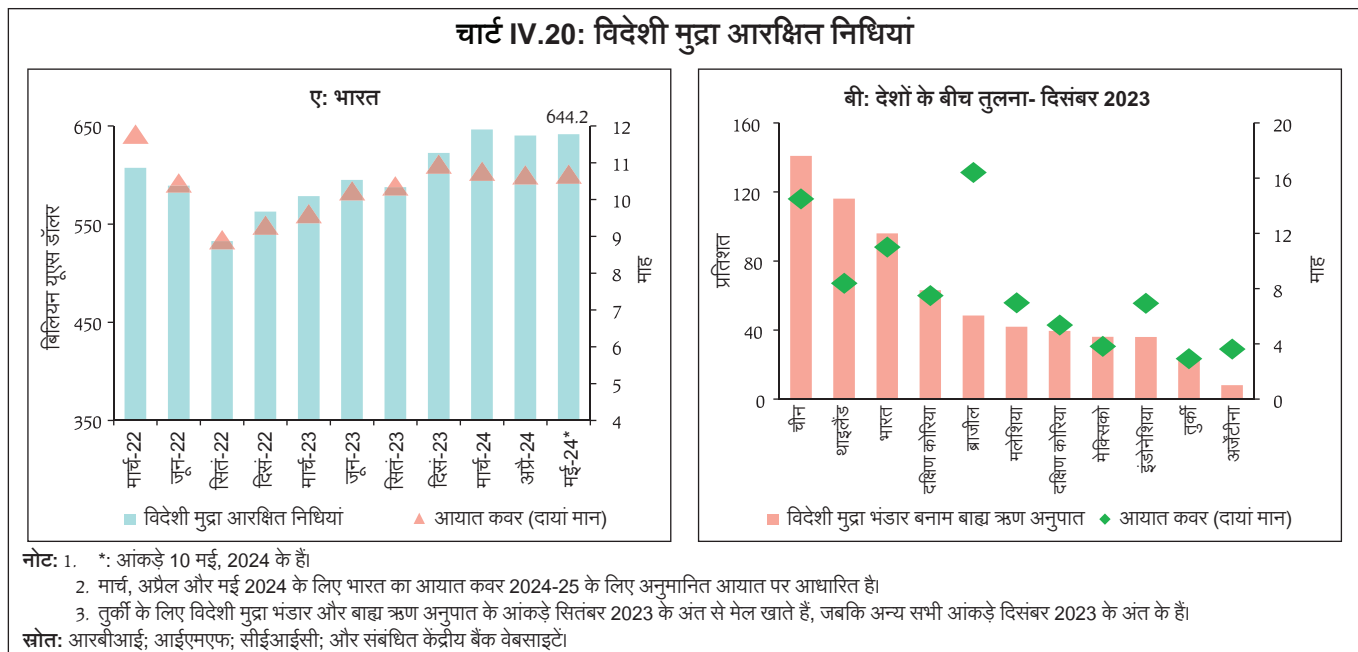


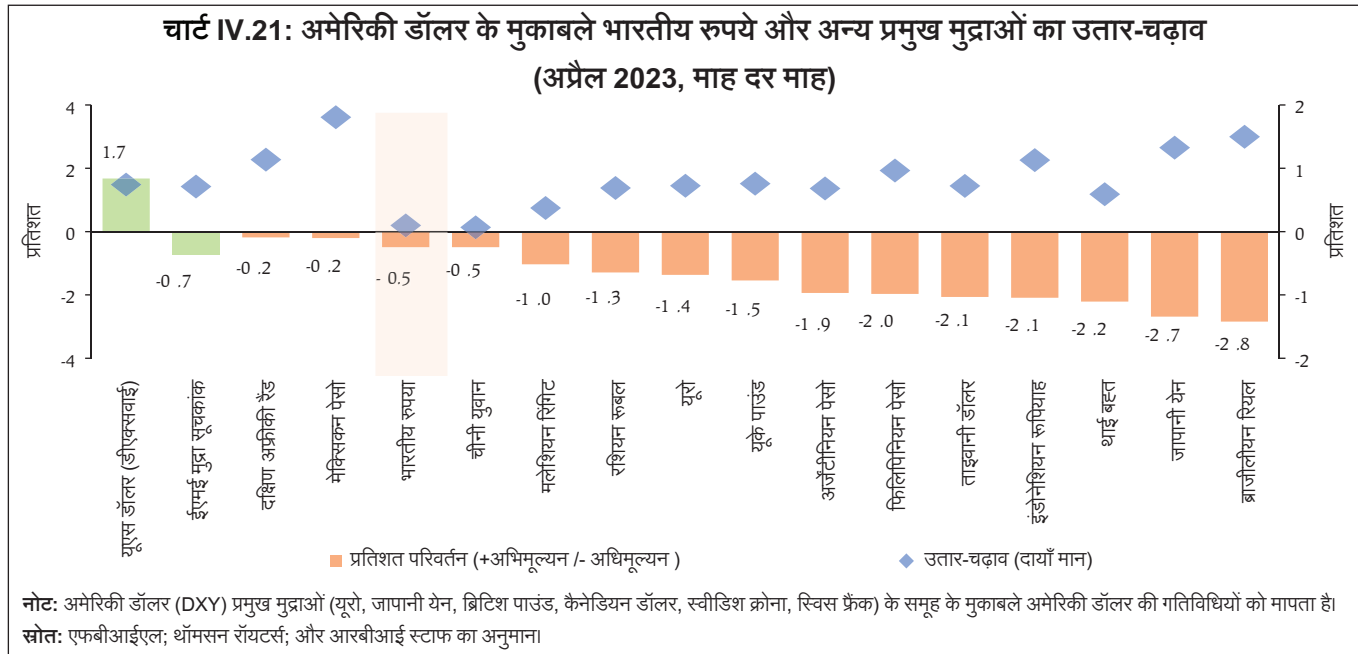


अन्य घटक - जोखिम प्रीमियम को प्रतिबिंबित करने वाला भारत औसत मार्जिन है - अप्रैल-मार्च 2024 के दौरान एक साल पहले के 172 बीपीएस से घटकर 159 बीपीएस और 2021-22 के दौरान औसतन 181 बीपीएस हो गया (चार्ट IV.19)।

कैलेंडर वर्ष 2024 के दौरान अब तक (10 मई, 2024 तक) भारत के विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में 21.7 बिलियन

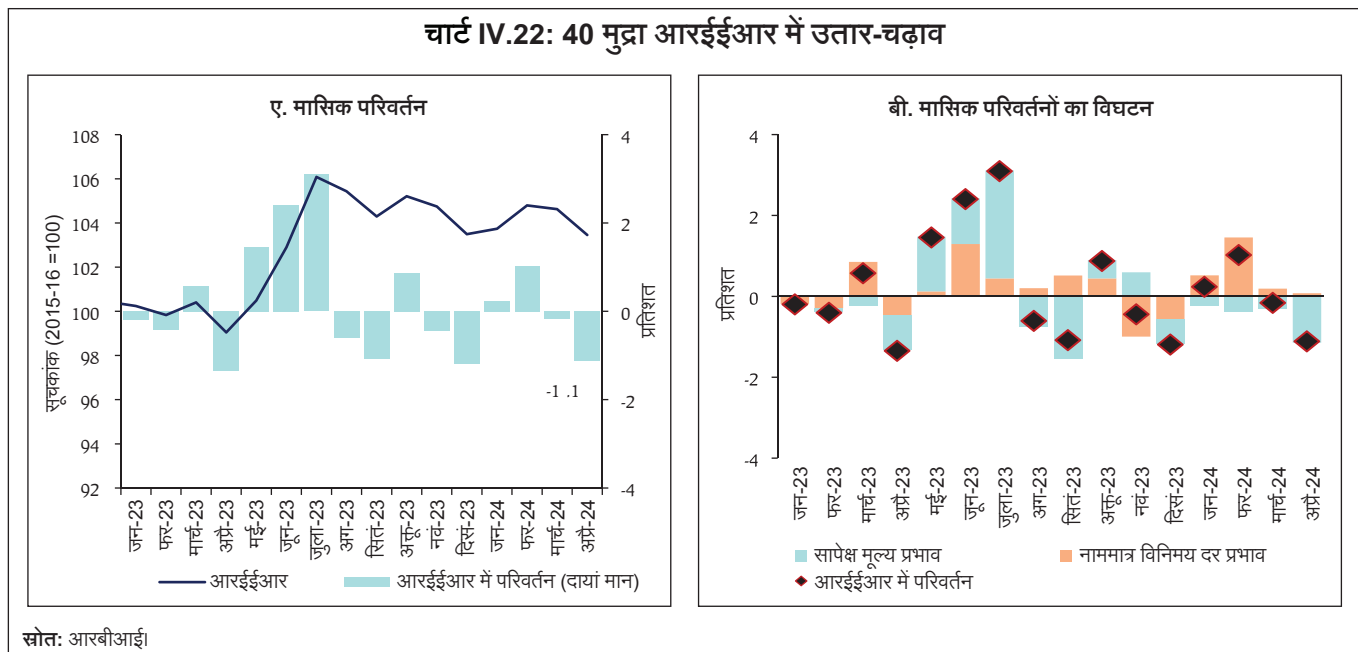
अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है, जो प्रमुख विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि रखने वाले देशों में सबसे अधिक विस्तार है। 644.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 2024-25 के लिए अनुमानित 10 महीने से अधिक के आयात के बराबर थी और दिसंबर 2023 के अंत में बकाया कुल विदेशी ऋण का 99 प्रतिशत से अधिक थी (चार्ट IV.20)।





अप्रैल 2024 में भारतीय रुपये (आईएनआर) में अमेरिकी डॉलर की तुलना में 0.5 प्रतिशत (मा-द-मा) की गिरावट आई, क्योंकि अधिकांश ईएमई ने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और घटती दर कटौती की प्रत्याशाओं के बीच सुदृढ़ अमेरिकी डॉलर का दबाव दर्ज किया। माह के दौरान प्रमुख मुद्राओं में आईएनआर सबसे कम अस्थिर रहा (चार्ट IV.21)।

40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, अप्रैल 2024 में आईएनआर में 1.1 प्रतिशत (म-द-म) की गिरावट आई, क्योंकि नकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर नाममात्र प्रभावी शर्तों में आईएनआर की अभिमूल्यन की तुलना में अधिक था (चार्ट IV.22)।



भुगतान प्रणाली

अप्रैल 2024 में डिजिटल लेनदेन का विस्तार (वर्ष-दर-वर्ष) जारी रहा, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से खुदरा खंड ने किया, जिसमें यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (एनएसीएच) और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) शामिल हैं [सारणी IV.4]। तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) लेनदेन में त्वरित वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) देखी गई, जबकि तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (एनईटीसी) की वृद्धि की गति अप्रैल 2024 में मात्रा और मूल्य दोनों स्तरों में कम हो गई। यूपीआई लेनदेन में वृद्धि मजबूत बनी हुई है, जो यूपीआई द्वारा समर्थित खाता प्रकारों की बढ़ती श्रृंखला के कारण देश भर में डिजिटल प्रणाली अपनाने में वृद्धि को दर्शाती है - जिसमें प्रीपेड भुगतान उपकरण (पीपीआई), वॉलेट, बचत खाते, ओवरड्राफ्ट खाते, रूपे क्रेडिट कार्ड खाते और बैंक क्रेडिट लाइनें शामिल हैं। यूपीआई को अपनाने और उसका अधिकाधिक उपयोग करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 8 मई, 2024 को विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक²⁴ की, जिसमें यूपीआई बुनियादी ढांचे के उन्नयन, यूपीआई पारितंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के साथ-साथ संभावित समाधान और संभावित उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान पारितंत्र में सम्मिलित करने के उपायों से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया।

बीबीपीएस ने अप्रैल 2024 के दौरान लेनदेन के उच्चतम मूल्य और मात्रा का दस्तावेजीकरण किया, जो आंशिक रूप से 1 अप्रैल, 2024 से परिचालनगत इकाइयों के रूप में प्रणाली में गैर-बैंक भुगतान एग्रीगेटर्स (पीए) की भागीदारी से प्रेरित था। इसके अलावा, एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सहयोग से यात्रियों की सुविधा के लिए अपने भारत बिलपे प्लेटफॉर्म पर एसबीआई नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड²⁵ (एनसीएमसी) की शुरुआत की।

एनपीसीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी - एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल)-ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने में समर्थन देने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया (बीओएन) के साथ एक समझौते²⁶ पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य नामीबिया के वित्तीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, भारत और घाना छह महीने से भी कम समय में घाना के इंटरबैंक भुगतान और निपटान प्रणाली (जीएचआईपीएसएस) पर यूपीआई को प्रारंभ करने के लिए तेजी से काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।²⁷ ग्राहक केंद्रितता के प्रति अपने संकल्प और क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) द्वारा लिए गए ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण के लिए

सारणी IV.4: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में विकास

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन मूल्य			
	मार्च-23	मार्च-24	अप्रै-23	*अप्रै-24	मार्च-23	मार्च-24	अप्रै-23	अप्रै-24
आरटीजीएस	7.8	12.3	3.2	16.9	11.5	12.4	7.0	21.5
एनईएफटी	26.8	45.2	29.1	45.9	7.4	15.2	10.5	13.4
यूपीआई	60.0	55.3	58.7	50.1	46.3	40.8	43.9	38.8
आईएमपीएस	1.0	16.8	5.1	11.0	18.2	16.2	17.2	13.7
एनएसीएच	29.8	22.8	-3.7	50.5	35.1	15.8	18.4	23.7
एनईटीसी	13.3	10.6	14.9	7.6	23.7	17.2	22.1	8.6
बीबीपीएस	56.5	25.4	33.5	45.1	61.6	82.8	51.2	107.5

नोट: आरटीजीएस: तत्काल निपटान, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, यूपीआई: यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा, एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण, बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

स्रोत: आरबीआई।

²⁴ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति। 8 मई 2024।

²⁵ एनपीसीआई परिपत्र। 18 अप्रैल 2024।

²⁶ एनपीसीआई परिपत्र। 2 मई 2024।

²⁷ पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति। 6 मई 2024।

नियामक ढांचे पर 'डिजिटल ऋण: एकाधिक ऋणदाताओं से ऋण उत्पादों के एकत्रीकरण में पारदर्शिता'²⁸ - विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां और प्रतिक्रिया आमंत्रित करना नामक एक मसौदा परिपत्र जारी किया। इसके अतिरिक्त, रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल ऋण में डिफॉल्ट हानि गारंटी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)²⁹ के रूप में दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया गया।

निष्कर्ष

इस परिवेश में, वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाल के घटनाक्रम ने मौद्रिक नीति अधिकारियों के लिए दुविधा को बढ़ा दिया है। मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक लाने में धीमी प्रगति को देखते हुए, उच्च ब्याज दरों को "अपना काम करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है"³⁰ मुद्रास्फीति की गति में कम सहजता को देखकर विश्वास की कमी है, क्योंकि पिछली आक्रामक सख्ती के बावजूद यह रुकी हुई है। इसके अलावा, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ते आप्रवासन, औद्योगिक नीति का सशक्त उपयोग, राजकोषीय ढिलाई और वैश्वीकरण के विखंडन से आपूर्ति शृंखला की पुनर्रचना के रूप में संरचनात्मक परिवर्तन मौद्रिक नीति के संचालन के लिए बिल्कुल नए आयाम हैं। तेजी से, दक्षता और लागत प्रभावशीलता से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और समुत्थानशीलता को प्राथमिकता दी जा रही है। आईएमएफ ने 2023 में दुनिया भर में कम से कम 2500 औद्योगिक नीति कार्रवाइयों की सूचना दी है, जिनमें से दो-तिहाई से अधिक व्यापार बिगाड़नेवाली थीं क्योंकि वे विदेशी वाणिज्यिक हितों के खिलाफ भेदभाव करती थीं।³¹ स्पष्ट रूप से, मौद्रिक नीति दुविधा संचार के कोलाहल के बजाय रणनीतिक संकेत देने की मांग करती है।

फिर भी, आर्थिक गतिविधि और उपभोक्ता भावना के धीमे होने से प्रतिबंधात्मक रुख को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, एक या दो महीने पहले की तुलना में कम नौकरियां जोड़ी जा रही हैं - मूल्य दबाव ने "जीवन के बुनियादी सिद्धांतों" को गंभीर रूप से प्रभावित किया है।³² इसलिए, मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी को कम करने के लिए दरों में बढ़ोतरी को असंभावित माना जाता है।

हालाँकि आशा है कि अर्थव्यवस्था सहज लैंडिंग की राह पर है, अब पहले की तुलना में अधिक सहज हो गई है, मौद्रिक नीति अधिकारी क्रैश लैंडिंग से बचने वाले गोल्डीलॉक्स परिदृश्य को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं। जल्दबाजी की मूर्खता के डर से, वे संभवतः वर्तमान पूर्वानुमानों की तुलना में अधिक समय तक धैर्यवान और उत्साहित रहना चाहेंगे। बाजार को आवास, बीमा और चिकित्सा लागत में अंततः धीमी गति से होने वाली तेजी से मुख्य अवस्फीति की प्रत्याशा से आशान्वित है। मुद्रास्फीति की घटनाओं से दर में कटौती का चक्र पटरी से नहीं उतरेगा, केवल उसमें विलंब होगा। नीतिगत विचलन एक बार फिर अटलांटिक के दोनों किनारों को अलग कर सकता है।

जैसे-जैसे मौद्रिक नीति में सहजता की शुरुआत हो रही है, उभरते बाजार के केंद्रीय बैंकों को कमजोर मुद्राओं, आयातित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव और उच्च मुद्रास्फीति के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। तदनुसार, जब मौद्रिक नीति की सख्ती को आर्थिक सुधार की गति को बाधित करने के रूप में देखा जा रहा है, तो आश्चर्यजनक दर में वृद्धि, समन्वित संचार और विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप का सहारा लिया जा रहा है। उच्च उधारी लागत घरेलू मांग पर अंकुश लगा रही है और उच्च स्तर के घरेलू ऋण वाले देशों में खतरा पैदा कर रही है। येन, युआन और वन में तेज गिरावट ने इस दृष्टिकोण को और भी जटिल बना दिया है, जिससे पिछले तीन महीनों में निर्यात की तेजी को सुरक्षित करने सहित मौखिक और विदेशी मुद्रा बिक्री रक्षा दोनों को बढ़ावा मिला है। तेजी से, बाजार की उम्मीदें इस दृष्टिकोण पर केंद्रित हो रही हैं कि ये केंद्रीय बैंक उच्च वास्तविक ब्याज दरों के बावजूद, यूएस फेड से आगे दरों में कटौती नहीं करेंगे। उनका कहना है कि वे 'फेड-निर्भर' नहीं होंगे, लेकिन वे फेड से कितनी दूर तक अलग हो सकते हैं, इस पर उन्हें व्यावहारिक सीमाओं का सामना करना पड़ेगा। नतीजतन, दर में ढील का चक्र आरंभिक अनुमान से कम हो सकता है। इस बीच, बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितता उभरते बाजार के केंद्रीय बैंकों को सोने की खरीदारी के लिए प्रेरित कर रही है, जो 2024 की पहली तिमाही में 290 टन जोड़ रही है जो कुल वैश्विक सोने की मांग का एक चौथाई हिस्सा है। भू-राजनीतिक विकास और धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच, ये केंद्रीय बैंक संकेत दे रहे हैं कि चुनौतीपूर्ण समय में बने रहने के लिए रणनीतिक विविधता की आवश्यकता है।

²⁸ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति 26 अप्रैल 2024।

²⁹ आरबीआई अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न 26 अप्रैल 2024।

³⁰ <https://www.ft.com/content/d1221cb9-9e5a-4512-9fef-4cc744a307fc>

³¹ <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2024/04/12/industrial-policy-is-back-but-the-bar-to-get-it-right-is-high>

³² फाइनेंशियल टाइम्स (2024, 2 मई)। जे पॉवेलस डाइलेमा: दी यूएस इकॉनमी इज टू स्ट्रॉंग टू कट रेट।